रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-73

REGISTERED NO. D. (D. N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 10, 1986/वैशाख 20, 1908

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 10, 1986/VAISAKHA 20, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1986

सूचना

का. आ. 1855.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री बुध राम सहारन, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे जयपुर (राजस्थान) व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(48)/85 न्या.]

आर एन पोद्दार, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 29th April, 1986

NOTICE

S.O. 1855.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Budh Ram Saharan Advocate for appointment as a Notary to practice in Jaipur (Rajasthan)

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(48)/85-Judl]

R. N. PODDAR, Competent Authority

कार्मिक, लोक शिकायत त[illegible] मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1986

का. आ. 1856.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संदेहजनक परिस्थितियों में श्री पीताम्बरन की मृत्यु के संबंध में केरल राज्य के कलामस्सेरी पुलिस थाना में रजिस्ट्रीकृत 1983 का अपराध सं. 72 तारीख 22-4-83 की बाबत भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 302 के अधीन दण्डनीय अपराधों और उन्हीं अपराधों और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के संबंध में या उनसे संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के अन्वेषण के लिए, केरल सरकार की सहमति से, दिल्ली विशेष

पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारों का विस्तार सम्पूर्ण केरल राज्य पर करती है।

[संख्या 228/5/86 ए. वी. डी (II)]

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(Dpartment of Personnel and Training)

ORDER

New Delhi, the 23rd April, 1986

S.O. 1856.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946, the Central Government, with the consent of the Government of Kerala, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Kerala for the investigation of the offence punishable under section 302, of Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), and attempt, abetment and conspiracy in relation to, or in connection with, the said offence and any offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts with regard to crime No. 72 of 1983 dated 22-4-1983 registered at Kalamassery Police Station in the State of Kerala in connection with the death of Shri Peethabaran under suspicious circumstances.

[No. 228/5/86-AVD.II]

का. आ. 1857—केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जी. एल. संघी, ज्येष्ठ अधिवक्ता और श्री अरूण नेहरा, अधिवक्ता को श्री बी. आर. बजाज और अन्य के विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन, चण्डीगढ़ आर. सी. संख्या 8,1986 से उत्पन्न श्री बी. आर बजाज, भा. प्र. से. वित्त सचिव, चण्डीगढ़ प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्र, चण्डीगढ़ द्वारा फाईल की गई दाण्डिक प्रकीर्ण अर्जी संख्या [2209, 1986 और दाण्डिक प्रकीर्ण (मुख्य) अर्जी संख्या 2208 एम, 1986] में पंजाब और हरियाणा राज्यों के उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में उपसंजात होने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[संख्या 225/16/86 ए. वी. डी. II]

S.O. 1857.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri G. L. Sanghi, Senior Advocate and Shri Arun Nehra, Advocate as Special Public Prosecutors to appear in the High Court of the State of Punjab and Haryana at Chandigarh of Criminal Misc. Petition No. 2209 of 1986 and Criminal Misc. (Main) Petition No. 2208-M of 1986 filed by Shri H. R. Bajaj, IAS Finance Secretary, Chandigarh Administration U.T. Chandigarh, arising out of Delhi Special Police Establishment, Chandigarh R. C. No. 8 of 1986 against Shri H. R. Bajaj, IAS and others.

[No. 225/16/86-AVD.II]

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 3986

का. आ. 1858—केन्द्रीय सरकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात राज्य के भड़ोंच जिला में संघवाड़ा पुलिस थाना में रजिस्ट्रीकृत प्र. ई. रि. अपराध संख्या 2/86 तारीख 13 जनवरी, 1986 की बाबत भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 114, 323, 376 के अधीन दण्डनीय अपराधों और उन्हीं अपराधों और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के संबंध में या उनसे संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षडयंत्रों के अन्वेषण के लिए गुजरात सरकार की सहमति से, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण गुजरात राज्य पर करती है।

[संख्या 228/4/85 ए. वी. डी. (II)]

New Delhi, the 24th April, 1986

S.O. 1858.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with section 6 of the Delhi Special Police Etablishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government, with the consent to the Government of Gujarat, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Gujarat for the investigation of offences punishable under sections 114, 323, 376 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offence committed in the course of the same transacion arising out of the same facts in regard to FIR Crime No. 2/86, dated the 13th January, 1986 registered at Saghbara Police Station, District Bharuch in the State of Gujarat.

[No. 228/4/86-AVD.II]

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1986

का. आ. 1859 केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 32 के अधीन दंडनीय अपराधों के अन्वेषण के लिए महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश सरकारों की सहमति से, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश राज्यों पर करती है।

[संख्या 228/30/85-ए. वी. डी. (II)]

New Delhi, the 25th April, 1986

ORDER

S.O. 1859.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946, (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Governments of Maharashtra Manipur, Orissa, Rajasthan, Tripura and Uttar Pradesh hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Maharashtra, Manipur, Orissa, Rajasthan, Tripura and Uttar Pradesh for the investigation of offences punishable under sections 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25 26 27, 28, 29, 30 and 32 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of1985).

[No. 228/30/85-AVD II]

आदेश

का. आ. 1860—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंडावरी, दौसा के निवासी श्री जुगल किशोर गुप्ता की हत्या के लिए संदिग्ध अपहरण से संबंधित एस. बी. क्रि. मिस. आवेदन सं. 527/85 में जयपुर उच्च न्यायालय में श्री राम किशोर गुप्ता द्वारा फाइल की गई अर्जी तारीख 16-9-85 की बाबत भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 364 के अधीन दण्डनीय अपराधों और उन्हीं अपराधों और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहारों के अनुक्रम में किए गए अन्य अपराध के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षडयंत्रों के अन्वेषण के लिए, राजस्थान सरकार की सहमति से

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य पर करती है।

[संख्या 228/34/85-ए. वी. डी. (II)]
एम. एस. प्रसाद, अवर सचिव

ORDER

S.O. 1860.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of Rajasthan hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Rajasthan for the investigation of offences punishable under section 364 of the Indian Panel Code, 1860 (45 of 1860) and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts in regard to petition dated 16-9-85 filed by Shri Ram Kishore Gupta in High Court at Jaipur in S. B. Cr. Misc. Application No. 527/85 relating to the suspected abduction for murder of Shri Jugal Kishore Gupta resident of Bhandaraga, Dausa.

[No. 228/34/85-AVD. II]
M. S. PRASAD, Under Secy.

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा विभाग)

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1986

[का. आ. 1861.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा शहरी विकास मंत्रालय के अधीन, भूमि तथा विकास कार्यालय में संपदा अधिकारी को, संपदा अधिकारी के रूप में उनके अपने कार्यभार के अतिरिक्त उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली तथा नई दिल्ली में सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्तियों के पट्टे अथवा वाहन विलेख जारी करने और पट्टा-विलेख के परिवर्तन, दिल्ली तथा नई दिल्ली में ऐसी सम्पत्तियों के साथ संलग्न प्रतिकर पूल के ही भाग अतिरिक्त भू-खण्डों तथा सुधारक क्षेत्र के आबंटन संबंधी प्रबंध अधिकारी के कार्यों के निष्पादन के प्रयोजन से प्रबंध अधिकारी नियुक्त करती है।

[सं.-4(42)/83-एस. एस. II(क)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Internal Security)

(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 17th April, 1986

S.O. 1861.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Estate Officer in the Land and Development Office under Ministry of Urban Development as Managing Officer for the purpose of performing, in addition to his own duties as Estate Officer, the functions of a Managing Officer by or under the aforesaid Act in respect of issue of lease or conveyance deeds of Government built properties in Delhi and New Delhi and conversion of lease-deeds, allotment of additional strips of Land and correctional areas adjoining such properties in Delhi and New Delhi forming a part of the compensation pool

[No. 4(42)/83-SS-II (A)]

का. आ. 1862.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा शहरी विकास मंत्रालय के अधीन, भूमि तथा विकास कार्यालय में उप भूमि तथा विकास अधिकारी को, उप भूमि तथा विकास अधिकारी के रूप में उनके अपने कार्यभार के अतिरिक्त उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली तथा नई दिल्ली में सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्तियों के पट्टे अथवा वाहन विलेख जारी करने और पट्टा-विलेख के परिवर्तन, दिल्ली तथा नई दिल्ली में ऐसी सम्पत्तियों के साथ संलग्न प्रतिकर पूल के ही भाग अतिरिक्त भू-खण्डों तथा सुधारक क्षेत्र के आबंटन संबंधी बंदोबस्त आयुक्त के कार्यों के निष्पादन के प्रयोजन से बंदोबस्त आयुक्त नियुक्त करती है।

[सं. 4(42)/83एस एस II (ख)]

S.O. 1862.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoint Deputy Land and Development Officer in the Land and Development Office under the Ministry of Urban Development, as Settlement Commissioner for the purpose of performing in addition to his own duties as Deputy Land and Development Officer, the functions assigned to him as a Settlement Commissioner by or under the aforesaid Act in respect of issue of lease or conveyance deeds of Government built properties in Delhi and New Delhi and conversion of lease-deeds, allotment of additional strips of land and correctional areas adjoining such properties in Delhi and New Delhi forming a part of the compensation pool.

[No. 4(42)/83-SS-II (B)]

का. आ. 1863.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा शहरी विकास मंत्रालय के अधीन, भूमि तथा विकास कार्यालय में उप भूमि तथा विकास अधिकारी को, उप भूमि तथा विकास अधिकारी के रूप में उनके अपने कार्यभार के अतिरिक्त उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली तथा नई दिल्ली में सरकार द्वारा निर्मित संपत्तियों के पट्टे अथवा वाहन विलेख जारी करने और पट्टा-विलेख के परिवर्तन, दिल्ली तथा नई दिल्ली में ऐसी संपत्तियों के साथ संलग्न प्रतिकर पूल के ही भाग अतिरिक्त भू-खण्डों तथा सुधारक क्षेत्र के आबंटन संबंधी उप मुख्य बंदोबस्त आयुक्त के कार्यों के निष्पादन के प्रयोजन से उप मुख्य बंदोबस्त आयुक्त नियुक्त करती है।

(सं.-4(42)/83-एस. एस.II(ग)

S.O. 1863.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoint Land and Development Officer in the Land and Development Office under the Ministry of Urban Development, as Deputy Chief Settlement Commissioner for the purpose of performing, in addition to his own duties as Land and Development Officer, the functions assigned to him as a Deputy Chief Settlement Commissioner by or under the aforesaid Act in respect of issue of lease or conveyance deeds of Government built properties in Delhi and New Delhi and conversion of lease-deeds, allotment of additional strips of Land and correctional areas adjoining such properties in Delhi and New Delhi forming a part of the compensation pool.

[No. 4(42)/83-SS-II (C)]

का. आ. 1864.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 28 तथा 33 के अंतर्गत दिल्ली तथा नई दिल्ली में सरकार द्वारा निर्मित संपत्तियों के पट्टे अथवा वाहन विलेख जारी करने और पट्टा-विलेख के परिवर्तन, दिल्ली तथा नई दिल्ली में ऐसी संपत्तियों के साथ संलग्न प्रतिकर पूल के ही भाग अतिरिक्त भू-खण्ड तथा सुधारक क्षेत्र के आबंटन संबंधी इसके द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का शहरी विकास मंत्रालय में निदेशक (भूमि) द्वारा

भी प्रयोग किया जाएगा बशर्ते कि वह ऐसी शक्तियों में से किसी का प्रयोग उन मामलों के संबंध में नहीं करेगा जिनमें उसने किसी अन्य हैसियत से आदेश दिया हो।

[सं.-4(42)/83-एस. एस. II(ई)]

S.O. 1864.—In exercise of powers conferred by sub-seciton (1) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby directs that powers exerciseable by it under sections 28 and 33 of the said Act, shall be exerciseable also by the Director (Lands) in the Ministry of Urban Development in respect of issue of lease or conveyance deeds of Government built properties in Delhi and New Delhi and conversion of lease-deeds, allotment of additional strips of land and correctional areas adjoining such properties in Delhi and New Delhi and forming a part of the compensation pool, subject to condition that he shall not exercise any of such powers in relation to any matter in which an order has been made by him in any other capacity.

[No. 4(42)/83-SS-II (E)]

का.आ. 1865.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा गृह मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा विभाग, पुनर्वास प्रभाग के अधीन (बंदोबस्त विंग) में सहायक बंदोबस्त अधिकारी श्री पी. एन. जेटले को उक्त अधिनियम के अधीन अथवा उसके द्वारा प्रबंध अधिकारी को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए उनके अपने कार्यभार के अतिरिक्त तत्काल प्रभाव से प्रबंध अधिकारी नियुक्त करती है।

[संख्या-1(4)/86-विशेष सैल/एस.एस.II(क)]

S.O. 1865.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (C&R) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoint Shri P. N. Jetley, Assistant Settlement Officer in the Settlement Wing under the Rehabilitation Division of M.H.A. as Managing Officer in addition to his own duties for the purpose of performing the functions assigned to a Managing Officer by or under the said Act, with immediate effect.

[No. 1(4)/Spl. Cell./86-SS-II (A)]

का. आ. 1866.—निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इसके द्वारा गृह मंत्रालय, पुनर्वास प्रभाग के बंदोबस्त विंग में सहायक बंदोबस्त आयुक्त श्री पी. एन. जेटले को उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा अंतर्गत सहायक अभिरक्षक को दिल्ली में निष्क्रांत संपत्तियों के संबंध में सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन से उनके अपने कार्यभार के अतिरिक्त तत्काल प्रभाव से सहायक अभिरक्षक नियुक्त करती है।

[सं.-1(4)/वि. सैल/86-एस. एस. II(ख)]
मोहम्मद असलम, अवर सचिव

S.O. 1866.—In erercise of powers conferred by sub-Section (1) of Section 6 of the Administration of Evacuee property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoint Shri P. N. Jetley, Assistant Settlement Officer in the Settlement Wing under the Rehabilitation Division of Ministry of Home Affairs as the Assistant Custodian in respect of Evacuee Properties in Delhi in addition to his own duties for the purpose of performing the functions assigned to a Assistant Custodian by or under the said Act, with immediate effect.

[No. 1(4)/Spl. Cell./86-SS-II (B)]
M. ASLAM, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक विभाग)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1986

बीमा

का. आ. 1867.—केन्द्रीय सरकार, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 27 ख की उपधारा (1) के खण्ड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 के खण्ड (2) के उपखण्ड (1) के अनुसार 1 नवम्बर, 1970 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारम्भ की गई पत्र पुनः मितीकाटा स्कीम में किए गए विनिधानों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "अनुमोदित विनिधान" घोषित करती है।

[फा. सं. 91(2)/बी. IV/78]
एस. आर. भाटिया, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 30th April, 1986

INSURANCE

S.O. 1867.—In exercise of powers conferred by clause (j) of sub-section (1) of Section 27B of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Central Government hereby declares investments in the Bills Rediscounting Scheme introduce by the Reserve Bank of India with effect from the 1st day of November, 1970 in terms of sub-clause (a) of clause (2) of section 17 of the Reserve Bank of India Act, 1934, as "approved investments" for the purposes of the said section.

[F. No. 91(2)/Ins. IV/78]
S. R. BHATIA, Under Secy.

बैंकिंग प्रभाग

नई दिल्ली 24 अप्रैल, 1986

का. आ. 1868.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर इसके द्वारा यह घोषित करती है कि बैंककारी विनियमन (सहकारी समिति) नियमवली, 1966 के नियम 10 के साथ पठित बैंककारी विनियमन (अधिनियम, 1949 जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 31 के उपबंध अनंतसयानाम को-आपरेटिव बैंक लि., त्रिवेन्द्रम को लागू नहीं होंगे जहां तक वे समाचार पत्र में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट सहित उनके दिनांक 30 जून, 1985 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र और लाभ हानि लेखा के प्रकाशन से संबंधित है।

[संख्या 8—2/86—ए.सी. (1)]

BANKING DIVISION

New Delhi, the 24th April, 1986

S.O. 1868.—In exercise of powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 31 of the Banking Regulation Act 1949 (As Applicable to Cooperative Societies) read with Rule 10 of the Banking Regulation (Cooperative Societies) Rules 1966 shall not apply to the Ananthasayanam Cooperative Bank Ltd., Trivandrum so far as they relate to the publication of its balance sheet and profit and loss account for the year ended 30 June 1985 together with the auditor's report in a newspaper.

[No. 8-2/86-AC(1)]

का. आ. 1869.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर इसके द्वारा यह घोषित करती है कि बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियों) नियमावली, 1966 के नियम 10 के साथ पठित

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 31 के उपबंध बडगारा सहकारी अर्बन बैंक लि., बडगारा को लागू नहीं होंगे जहां तक वे समाचार पत्र में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट सहित उनके दिनांक 30 जून 1985 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा के प्रकाशन से संबंधित हैं।

[संख्या 8-2/86-ए सी.]
के. पी. पाण्डियान, अवर सचिव

S.O. 1869.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 31 of the Banking Regulation Act, 1949 (As Applicable to Cooperative Societies) read with Rule 10 of the Banking Regulation (Cooperative Societies) Rules 1966 shall not apply to the Badagora Cooperative Urban Bank Ltd., Badagora so far as they relate to the publication of its balance sheet and profit and loss account for the year ended 30 June, 1985 together with the auditors report in a newspaper.

[No. 8-2|86-AC]
K. P. PANDIAN, Under Secy.

कार्यालय समाहर्ता: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क: मुख्यालय

अधिसूचना संख्या 13/85

इन्दौर, 18 अप्रैल, 1986

का. आ. 1870.—श्री एस. आर. कानूनगो, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह "ख" वार्धक्य आयु आने पर 30 नवम्बर 1985 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

[प. सं. II (3) 7 गोप 85/1998]

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

NOTIFICATION NO. 13/85

Indore, the 18th April, 1986

S.O. 1870.—Shri S. R. Kanungo, Superintendent of Central Excise Group 'B' having attained the age of superannuation retired from Government service on the afternoon of thirtieth November, 1985.

[C. No. II(3)7-Con/85/1998]

अधिसूचना संख्या 3/86

का. आ. 1871.—श्री एम. एस. चौरे, अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह "ख" निवर्तन की आयु प्राप्त होने पर शासकीय सेवा से दिनांक 28-2-86 को अपराह्न में सेवानिवृत्त हुए।

[प. सं. II (3) 2 गोप/86/2023]

NOTIFICATION NO. 3/86

S.O. 1871.—Shri M. S Chourey, Superintendent, Central Excise Grup 'B' having attained the age of superannuation retired from Government service on 28-2-1986 (AN).

[C. No. II(3)2-Con/86/2023]

अधिसूचना संख्या 1/86

का. आ. 1872.—श्री ए. एल. बहल, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह "ख," 28-2-1986 के अपराह्न से शासकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्त हुए।

[प. सं. II (3) 2 गोप/86/1973]
एस. व्ही. रामकृष्णन, समाहर्ता

NOTIFICATION NO. 4/86

SO. 1872.—Shri A. L. Behal, Superintendent, Central Excise, Group 'B' of Central Excise Collectorate, Indore has voluntarily retired from the Government service in the afternoon of 28th February, 1986.

[C. No. II(3)2-Con/86/1973]
S. V. RAMAKRISHNAN, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1986

का. आ. 1873.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में वाणिज्य मंत्रालय व वस्त्र मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:—

वाणिज्य मंत्रालय :

1. सहायक मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात का कार्यालय,
   वाणिज्य मंत्रालय, बिस्कोमान भवन,
   पटना 800001.
2. सम्पदा सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय, कैसर-ए-हिन्द बिल्डिंग,
   करीमभाय रोड,
   पोस्ट बाक्स नं. 689, बेलार्ड एस्टेट,
   बम्बई–400038.
3. संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात का कार्यालय,
   वाणिज्य मंत्रालय,
   117/एल-444 काकादेव,
   कानपुर–208025

वस्त्र मंत्रालय :

1. नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन लिमिटेड,
   (महाराष्ट्र नार्थ), बम्बई
2. नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन,
   (मध्य महाराष्ट्र), लि., बम्बई
3. नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (उ. प्र.), लिमिटेड (मुख्यालय)
4. स्वदेशी मिल, कानपुर,
   [एन. टी. सी., (यू. पी.) लि.],
5. न्यू विक्टोरिया मिल, कानपुर
   [एन. टी. सी. (यू. पी.) लि.],
6. लक्ष्मीरतन काटन मिल, कानपुर
   [एन. टी. सी (यू. पी.) लि.],
7. अथर्टन, मिल्स कानपुर,
   [एन. टी. सी. (यू. पी.) लि.],
8. बिजली काटन मिल्स, हाथरस
   [एन टी. सी (यू. पी.), लि.],
9. श्री विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ,
   [एन टी. सी. (यू. पी.) लि.],
10. लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर,
    [एन. टी. सी. (यू. पी.) लि.],
11. रिटेल सेल डिवीजन, [एन टी. सी.,
    (यू. पी.) लि.]
12. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र
    विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

ताज बिल्डिंग रावली,
आगरा-282001

13 दि. काटन कारपोरेशन, आफ इंडिया लिमिटेड,
ग्राउंड फलोर, शालीमार बिल्डिंग,
एम्बेसी मार्किट के पास,
नवरंग पुरा, अहमदाबाद-380009.

[फाइल स. ई. 11011(12)/76 हिन्दी]
वेद प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 17th April, 1986

S.O. 1873.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rule, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices under the Ministry of Commerce and Ministry of Textiles, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

Ministry of Commerce :

1. Office of the Assistant Chief Controller of Imports and Exports, Ministry of Commerce Biscoman Bhavan, Patna-800001.
2. Office of the Custodian of Enemy Property for India, Kaiseri-Hind Biulding Currimbhoy Road, Ballard Estate, Post Box No. 689, Bombay-400038.
3. Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Ministry of Commerce, 117|L-444, Kaka Dev, Kanpur-208025.

Ministry of Textiles :

1. National Textile Corporation Limited, (Maharashtra North), Bombay.
2. National Textile Corporation Limited, (South Maharashtra), Bombay.
3. National Textile Corporation (UP) Limited, (Head Quarter)
4. Muir Mills, Kanpur [N.T.C.(U.P.) Ltd.]
5. New Victoria Mills, Kanpur (N.T.C.(U.P.) Lttd.)
6. Laxmi Rattan Cotton Mills, Kanpur [N.T.C.(U.P.) Ltd.]
7. Atherton Mills, Kanpur [N.T.C.(U.P.) Ltd.]
8. Bijli Cotton Mills, Hathras [N.T.C.(U.P) Ltd.]
9. Shri Vikram Cotton Mills, Lucknow [N.T.C.(U.P.) Ltd.]
10. LordLord Krishna Textile Mills, Saharanpur [N.T.C.(U.P.) Ltd.]
11. Retail Sales Division, [N.T.C.(U.P.) Ltd.]
12. Marketing and Service Extension Centre, Office of the Development Commissioner Handicrafts, Taj Building Rawali, Agra-282001.
13. The Cotton Corporation of India Ltd., Air India Building, Ground Floor, Shalimar Building, Near Embassy Market, Navrangpura, Ahmedabad-380009.

[File No. E-11011(12)|76-Hindi]
VED PRAKASH, Director

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

दिल्ली, 28 फरवरी, 1986

का. आ. 1874 भण्डार / शैल, नियंत्रक इन्टीगरल कोच फैक्टरी, मद्रास को सप्लाई आर्डर सं० आई सी एफ/72/1/84/0/6049/3 दिनांक 28-9-1984 की संलग्न सूची के अनुसार अनुषंगियों सहित लेयर थिकनेस गौज के दो नग आयात करने के लिए 20,045/- रुपए मात्र के लिए आयात लाइसेंस सं. जी/बी/3203764 सी/एक्स एक्स/94, दिनांक 5/3/1985 दिया गया था।

2. उप नियंत्रक, भण्डार शैल इन्टीगरल कोच फैक्टरी, मद्रास ने उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय प्रति किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराये बिना और उपयोग में लाए बिना खो गई है और उप नियंत्रक, भण्डार/शैल, इन्टीगरल कोच फैक्टरी, मद्रास ने इस बात पर सहमति प्रगट की है तथा वायदा किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति मिल जाने पर इस कार्यालय को रिकार्ड के लिए वापस कर दी जाएगी।

3. अपने तर्क के समर्थन में उप नियंत्रक, भंडार/शैल इन्टीगरल कोच फैक्टरी, मद्रास ने 1985-88 के लिए हैंड बुक से पैरा 86 के अनुसार अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है तथा निर्देश देता है कि आवेदक को मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जाए। मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रद्द की जाती है।

4. लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[फाइल नं. 59—सी रेलवे/84-85/जी एल एस]
पाल बैक उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS

ORDER

New Delhi, the 28th February, 1986

S.O. 1874.—Controller of stores|Shell, Integral Coach Factory, Madras, was granted an Import Licence No. G|B|3203764|C/XX/94|H|84 dated 5-3-1985 for Rs. 20,045 only for the import of Two Nos. of Layer Thickness Gauge with Accessories as per list attached against Supply Order No. ICF|72|1|84|O/6049/3 dated 28-9-1984.

2. Dy. Controller of Stores|Shell, Integral Coach Factory Madras, has now requested for issue of duplicate Exchange Control Copy of the above licence on the ground that the original Exchange Control Copy has been lost without being registered with the Custom authority and utilised at all. Dy. Controller of Stores|Shell, Integral Coach Factory, Madras, agrees and undertakes to return the original Exchange Control Copy if traced later on to this office for record.

3. In support of their contention Dy. Controller of Stores/Shell, Integral Coach Factory, Madras, have filed an affidavit as required in terms of Para 86 of Hand Book for 1985-88. The undersigned is satisfied that the original exchange control

copy of the above said licence has been lost and directs that duplicate exchange control copy may be issued to the applicant. The original exchange control copy has been cancelled.

4. The duplicate Exchange Control Copy of the licence is being isued separately.

[F. No. 59-C/Rly/84-85/GLS]
PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
For Chief Controller of Imports & Exports

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1986

आदेश

का.आ. 1875:—श्री ए.एम. मूलचन्दानी, पो.बा. बाक्स 177, अजारे, बौची स्टेट, नाइजीरिया को एक न. टोयोटा करोला 1300 सी.सी. कार के आयात के लिए 61,000 रु. मूल्य का एक सीमा शुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3052483 दिनांक 1-10-1985 दिया गया था। आवेदक ने उक्त सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी किए जाने का इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट अस्थानस्थ/खो गया है। आगे यह भी कहा गया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट को किसी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था इस प्रकार सीमा शुल्क निकासी परमिट का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारक ने उचित न्यायिक प्राधिकारी के सम्मुख विधिवत शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं तदनुसार, संतुष्ट हूं कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3052483 दिनांक 1-10-1985 आवेदक द्वारा खो गई है। समय-समय पर यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक, 7-12-1955 की उपधारा 9 (सी सी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री ए.एम. मूलचन्दानी को जारी उक्त मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3052483 दिनांक 1-10-1985 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3. पार्टी को सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति को अलग से जारी किया जा रहा है।

[फा.सं. ए./एम-41/85-86/बी एल एस/207]
एन.एस. कृष्णामूर्ति, उप मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

New Delhi, the 24th April, 1986

ORDER

S.O. 1875.—Mr. A. M. Moolchandani, P.O. Box 177, Azare Bauchi State, Nigeria was granted as Customs Clearance Permit No. P|J|3052483 dt. 1-10-85 for Rs. 61,000 only for import of One No. Toyota Carolla 1300cc car. The applicant has applied for issue of Duplicate copy of the above mentioned Customs Clearance Permit on the ground that the original CCP has been misplaced|lost. It has further been stated that the original CCP was not registered with any Customs Authority and such the value of the CCP has not been utilised at all.

2. In support of his contention, the licence has filed an affidavit duly sworn before appropriate judicial authority. I am accordingly satisfied that the original CCP No. P|J|3052483 dt. 1-10-85 has been lost by the applicant. In exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended from time to time the said original CCP No. P|J|3052483 dt. 1-10-85 issued to Mr. A. M. Moolchandani is hereby cancelled.

3. A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is being issued to the party separately.

[F. No. A|M-41|85-86|BLS|207]
N. S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
For Chief Controller of Imports & Exports

संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात कार्यालय
(केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र)

नई दिल्ली, 1986

निरस्तन आदेश

का.आ. :—सर्वश्री बत्रा हैण्डलिंग एण्ड प्रोसेस इन्जीनियर्स लिमिटेड, 243, उद्योग विहार, डूंडाहेड़ा, गुड़गांवां 122016, नई दिल्ली को एक आयात लाइसेंस सं. पी/डी/2240624 दिनांक 11-4-85 का 10,29,000 रु. का लार्ज स्प्रोकेट्स हेड एण्ड ट्रैक्शन व्हील इत्यादि मदों के आयात हेतु जारी किया गया था।

आवेदक फर्म ने इस कथन के समर्थन में अब एक शपथ-पत्र, आयात-निर्यात की कार्यविधि पुस्तिका 1985–88 के पैरा 86 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उक्त लाइसेंस की कस्टम प्रयोजन कापी बम्बई कस्टम के पास पंजीकृत कराने एवं आंशिक रूप से उपयोग करने के पश्चात खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है।

फर्म द्वारा कस्टम प्रयोजन कापी की अनुलिपी लाइसेंस की बकाया राशि 6,61,352 रु० को पूरा करने के लिए अपेक्षित है।

अतः आयात–व्यापार नियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 7-12-55 (यथा संशोधित) की धारा 9 (डी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस सं. पी/डी/2240624 दि. 11-4-85 की मूल कस्टम प्रयोजन कापी को निरस्त करने का आदेश देता हूं।

आवेदक की प्रार्थना पर आयात-निर्यात की कार्य विधि-पुस्तिका 1985–88 के पैरा 86 के अनुसार उक्त लाइसेंस सं. पी/डी/2240624 दि. 11-4-85 की कस्टम प्रयोजन कापी की अनुलिपि (डुप्लीकेट कापी) जारी करने पर विचार किया जायेगा।

[फाइल सं. डी जी टी डी/सप्लीमेंट्री/235/ए एम 85/एयू–I/सी एल ए/86]

OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS
(CENTRAL LICENSING AREA)

New Delhi, 1986

CANCELLATION ORDER

S.O. 1876.—M/s. Batra Handling & Process Engineers Ltd. 243 Udyog Vihar, Dundahera, Gurgaon-122016 New Delhi was granted an import lic. No. P|D|2240624 dt. 11-4-85 for **Rs. 10,29,000 for import of the items Large sprockets head** & traction wheels etc.

The above mentioned party have filed an affidavit as required under para-86 of Hand book of import & export procedure 1985—88 wherein they have stated that the Customs purpose copy of the above, licence has been lost|misplaced after having been registered with customs Bombay and utilised partially.

A duplicate **customs purpose copy** is required by the firm to cover the balance value of the licence i.e. Rs. 6,61,352.

In exercise of the powers conferred on me under sub clause 9(d) in the Import Control Order, 1955 dated 7-12-55 as amended upto date, I cancel the customs purpose copy of the above licence.

The applicant (Licensee) is now being issued duplicate customs purpose copy of import licence No. P|D|2240624 dt. 11-4-85 for Rs. 6,61,352 in accordance with the provision of paragraph 86 of Hand Book of Import & Export Procedure, 85—88.

[F. No DGTD Suppl.|235|AM|AU-1|CLA|86]

निरसन आदेश

का.आ. 1877.—मर्वश्री स्टूबर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ए-10, सैक्टर-सात, नोएडा काम्प्लैक्स, जिला गाजियाबाद (यू.पी.) को एक आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2239664 दिनांक 9-2-84 को स्टार वाशर इत्यादि मद के आयात के लिए 1,70,230 रु. जारी किया गया था।

आवेदक फर्म ने इस कथन के समर्थन में अब एक शपथ-पत्र, आयात-निर्यात की कार्यविधि पुस्तिका 1985–88 के पैरा 86 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उक्त लाइसेंस की एक्सचेंज कंट्रोल कापी कहीं खो गई है फर्म द्वारा डुप्लीकेट एक्सचेंज कन्ट्रोल कापी लाइसेंस की बकाया राशि 1,47,230 को पूरा करने के लिए चाहिए।

अत: आयात-व्यापार नियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 7-12-55 (यथा संशोधित) की धारा में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस सं. पी/डी/2239664 दि. 9-2-84 की मूल एक्सचेंज कन्ट्रोल कापी को निरस्त करने का आदेश देता हूं।

आवेदक की प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात की कार्यविधि पुस्तिका 1985–88 के पैरा 86 के अनुसार उक्त लाइसेंस सं. पी/डी/2239664 दि. 9-2-84 की एक्सचेंज कन्ट्रोल कापी की अनुलिपि (डुप्लीकेट कापी) जारी करने पर विचार किया जायेगा।

[फाइल सं० डी जी टी डी-सप्लमेंट्री/252/ए एम-84/ए यू-आई/सी एल ए/86]

ह. —
जे०के० कालसी,
संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

CANCELLATION ORDER

S.O. 1877.—M/s. Stuber Engineering Pvt. Ltd., A-10 Sector-VII, Noida Complex, Distt. Ghaziabad (U.P.) was granted an import lic. No. P|D|2239664 dated 9-2-1984 for Rs. 1,70,230 for import of the item Star washer etc.

The above mentioned party have filed an affidavit as required under para-86 of Hand Book of import & export procedure, 1985—88 wherein they have stated that the Exchange Control copy of the above licence has been lost.

A duplicate Exchange Control copy is required by the firm to cover the balance value of the licence i.e. Rs. 1,47,230.

In exercise of the powers conferred on me under Sub-clause 9(d) in the Import Trade Control Order, 1955 dated 7-12-55 as amended upto date, I cancel the Exchange control copy of the above licence.

The applicant (Licencee) is now being issued duplicate Exchange control copy of import licence No. P|D|2239664 dated 9-2-1984 for Rs. 1,47,230 in accordance with the provision of paragraph 86 of Hand Book of Import & Export Procedures, 85—88.

[F. No. DGTD. Sup.|252|AM-84|AU-I|CLA|86]

Sd|-
J. K. KALSI, Jt. Chief Controller of Imports & Exports

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1986

का.आ. 1878:—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करने के बाद उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अनुसूची में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबंधित प्रविष्टियों में "मैम्बरशिप आफ द नेशनल एकाडमी आफ मेडिकल साइंसेस (क्लिनिकल फार्माकोलोजी एण्ड थिरेपुटिक्स), एम.एन.ए.एम.एस. (क्लिनिकल फार्माकोलोजी एण्ड थिरेपुटिक्स)", प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"मैम्बरशिप आफ द नेशनल एकाडमी
आफ मेडिकल साइंसेज (अस्पताल
प्रशासन सहित स्वास्थ्य प्रशासन)
एम.एन.ए.एम.एस.
(अस्पताल प्रशासन सहित स्वास्थ्य
प्रशासन)"

[सं. वी 11017/3/84-एम.ई. (पी.)]

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 13th March, 1986

S.O. 1878.—In execise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:—

In the said Schedule, in the entries relating to the National Board of Examinations, New Delhi, after the entry "Membership of the National Academy of Medical Sciences (Clinical Pharmacology and Therapeutics) M.N.A.M.S., (Clinical Pharmacology and Thera.)", the following entries shall be inserted, namely :—

"Membership of the National
Academy of Medical Sciences

(Health Administration including Hospital Administration) M.N.A.M.S. (Health Administration including Hospital Administration).

[No. V. 11017/2/84-ME(P)]

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1986

का.आ. 1879.— यत: भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपबन्ध के अनुसरण में सिलेट आफ यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान के डा. डी.एल. छंगानी का 17 अक्तूबर, 1985 से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के सदस्य के रूप में चयन किया है।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना का.आ. संख्या 138 (संख्या 5-13/59-एम-I) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्ष के अंतर्गत क्रम संख्या 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात् :—

"19 डा. डी.एल. छंगानी,
प्रधानाचार्य और अध्यक्ष, ई.एन.टी. विभाग
एस.एम. एस. मेडिकल कालेज,
जयपुर"

[संख्या वी. 11013/2/86-एम.ई. (पी)]
चन्द्र भान, अवर सचिव

New Delhi, the 25th April, 1986

S.O. 1879.—Whereas in pursuance of the provision of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1966 (102 of 1966) Dr. D.L. Chhangani has been selected by he Senate of University of Rajasthan to be a member of the Medical Council of India with effect from the 17th October, 1985.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of the section 3 of the said Act, the Central Government bereby makes the following further amendment in the notification of Government of India in the late Ministry of Health, No. S.O. 138 (No. 5-13/59-MI) dated the 9th January, 1960, namely:—

In the said notification under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3" for serial number 19 and the entry relating thereto the following serial number and entry shall be substituted namely:—

"19, Dr. D.L. Chhangani,
Professor & Health of Deptt. of ENT,
S.M.S. Medical College, Jaipur."

[No. V. 11013/2/86-ME (P)]
CHANDER BHAN, Under Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1986

आदेश

का. आ. 1880:— खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की 24 दिसम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या 13 (6)80-खान 6 के अनुक्रम में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 31 दिसम्बर, 1988 को ऐसी तारीख के रूप में निर्धारित करती है, जिस तक खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1972 प्रारम्भ से पूर्व स्वीकृत सभी खनन पट्टे, यदि वे अधिनियम के प्रारम्भ के समय विद्यमान थे उक्त अधिनियम तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुरूप कर लिये जायेंगे।

[फा.सं. 13(1)/86-खान 6]
बी. दास गुप्ता, निर्देशक

पाद टिप्पणी : पूर्ववर्ती का.आ. सं. 652 दिनांक 29-1-83 के अधीन जारी किया गया।

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 28th April, 1986

ORDER

S.O. 1880.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of the sub-section (1) of section 16 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957) and in continuation of the Notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines), No. 13(6)/80-M. VI dated the 24th December, 1982, the Central Government hereby specifies the 31st December, 1988 as the date within which all mining leases granted before the commencement of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Act, 1972, if in force at such commencement, shall be brought into conformity with the provisions of the said Act and the rules made thereunder.

[F. No. 13(1)/86-M. VI]
B. DASGUPTA, Director

Foot Note.—The previous Order was issued under S.O. No. 652 dated 29th January, 1983.

युवा कार्यक्रम और खेल विभाग

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1986

का.आ. 1881 समय-समय पर संशोधित के अनुसार 25 मार्च, 1982 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-II खण्ड 3, उपखण्ड 3 (ii) में प्रकाशित शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय की अधिसूचना, एस.ओ. संख्या 166 (ई) दिनांक 22 मार्च, 1982 के क्रम में, केन्द्रीय सरकार, धर्मार्थ प्रन्यासनिधि अधिनियम 1890 की धारा 4 (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, और खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि के प्रबन्ध और प्रशासन के प्रयोजनार्थ सामान्य समिति की सहमति से, एतद्द्वारा आदेश देती है कि 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) की राशि, भारत के धर्मार्थ प्रन्यासनिधि के कोषाध्यक्ष और न्यास के पद पर उनके उत्तराधिकारी को, उक्त राशि और उससे होने वाली आय को, डाकघर की समय जमा योजना में, 5 वर्ष के अवधि के लिए जमा करने हेतु, सौंपी जायेगी।

[सं. एफ 13-1/81(डी.1) (एस.पी.)]
ए. भट्टाचार्य, उप सचिव

DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

New Delhi, the 25th April, 1986

S.O. 1881.—In continuation of the Ministry of Education and Culture Notification S.O. No. 166(E) dated 22nd March, 1982 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II Section 3 Sub Section 3(ii) dated 25th March, 1982, as modified from time to time, the Central Government in exercise of the powers conferred under section 4(1) of the Charitable Endowments Act, 1890 and with the concurrence of the General Committee for the purpose of Management and Administration of the National Welfare Fund for Sportsmen do hereby order that an amount of Rs. 8 lakhs (Rupees

Eight-lakhs only) be vested in the Treasurer of Charitable Endowments for India to be held by him and his successors in office upon trust to hold the said monies and the income thereof for a period of five years for deposit in the Post Office Time Deposit Scheme.

[No. F. 13-1/81-D. I (SP)]
A. BHATTACHARYYA, Dy. Secy.

अंतरिक्ष विभाग

बंगलौर, 17 अप्रैल, 1986

का.आ. 1882—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम, 10 उपनियम (4) के अनुसरण में अंतरिक्ष विभाग के निम्न कार्यालयों को जिनके कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. शार केन्द्र, श्री हरिकोटा-524124 (आन्ध्र प्रदेश)

2. सिविल इंजीनियरी प्रभाग, अन्तरिक्ष विभाग, बंगलौर-560009

[सं. 16/5/(2)/86-I]
टी.एस. वेंकटरामन, उपसचिव

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore, the 17th April, 1986

S.O. 1882.—In pursuance of Sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use for the Official Purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following offices of the Department of Space, the Staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi:—

1. SHAR Centre, Sriharikota-524124 (Andra Pradesh)
2. Civil Engineering Division, Department of Space Bangalore-560009.

[No. 16/5(2)/86-I]
T.S. VENKATARAMAN, Dy. Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1986

का.आ. 1883—सिनेमाटोग्राफ (प्रमाणीकरण) नियमावली, 1983, के नियम 8 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित सिनेमाटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 5 की उपधारा (1) और नियम 7 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात निम्नलिखित व्यक्तियों को बम्बई के उक्त बोर्ड के सलाहकार पैनल के सदस्यों के रूप में दो वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक तत्काल नियुक्त करती है :—

1. श्रीमती मंजुला अशोक राव
2. डा. (श्रीमती) धनलक्ष्मी ए. डिसूजा
3. श्रीमती सरोज नीलकान्त आप्टे
4. श्रीमती टेरेसा विजु जेम्स
5. श्री के.डी. सिक्का
6. श्रीमती सनोबर शेखर
7. श्रीमती प्रतिभा शिरीष भट्ट
8. श्री किशोर वालिचा
9. श्रीमती शारदा पी. कारनिक
10. श्रीमती पदमजा एस. पाठक
11. डा. रमेश रंगनेकर
12. श्रीमती सुरैया करीम भाई
13. श्रीमती लक्ष्मी सुन्दरम
14. श्रीमती रुक्मणी कृष्णास्वामी
15. श्रीमती एस.ए. गोगटे
16. डा० विनायक आर. पोल
17. श्रीमती वीना वी. प्रभु
18. श्रीमती सुधा एस. वारडे
19. श्रीमती शीला रानी पटेल
20. डा. मिसेज उर्मिला पी. शाह
21. डा. एस.वी. डामले
22. श्रीमती कृष्णा अग्रवाल
23. श्री प्रबोध पारिख
24. डा. (श्रीमती) ऊषा सुरेश वाग

[फा.सं. 811/1/84-एफ. (सी)]

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Culture)

New Delhi, the 2nd April, 1986

S.O. 1883.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of hte Cinematograph Act, 1982 and sub-rule (3) of rule 7 read with sub-rule (1) and (2) of rule 8 of the Cinematograph (Certification) Rules 1983, the Central Government hereby appoints the following persons after consultation with the Board of Film Certification, as Members of the Advisory Panel of the said Board at Bombay with immediate effect for a period of two years or until further orders:—

1. Smt. Manjula Ashok Rao
2. Dr. (Mrs.) Dhanalakshmi A. Desouza
3. Smt. Saroj Neelkanth Apte
4. Mrs. Terese Viju James
5. Shri K. D. Sikka
6. Smt, Sanobar Shekar
7. Smt. Pratibha Shrish Bhatt
8. Shri Kishore Valicha
9. Smt. Sharda P. Karnik
10. Smt. Padmaja S. Pathak
11. Dr. Ramesh Rangnekar
12. Smt. Suraiya Currimbhoy
13. Smt. Lakshmi Sundaram
14. Smt. Rukmini Krishnaswamy
15. Smt. S.A. Gogate
16. Dr. Vnayak R. Pol
17. Smt. Veena V. Prabhu
18. Smt. Sudha S. Varde
19. Smt. Sushila Rani Patel
20. Dr. (Mrs) Urmila P. Shah
21. Dr S.V. Damle
22. Smt. Krishna Agarwal
23. Shri Prabodh Parikh
24. Dr. (Mrs) Usha Suresh Wagh

[File No. 811|1|85-F(C)]

का.आ. 1884—सिनेमाटोग्राफ (प्रमाणीकरण) नियमावली, 1983 नियम 8 के उप नियम (1) के साथ पठित सिनेमाटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा यह निर्देश देती है कि निम्नलिखित व्यक्ति 15 अप्रैल, 1986 से फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बम्बई सलाहकार पैनल के सदस्य नहीं रहेंगे :

1. श्री ए. एम. आई. अलवी
2. श्रीमती रंजन अमीन
3. श्रीमती प्रफुला वहलुकर
4. डा. मुकेश बत्रा
5. कुमारी भूमी विनायके
6. श्रीमती माया कमिथार
7. श्री आर.सी. बजाज

8. श्रीमती सुलोचना गुलाटी
9. श्रीमती ललिता जयराज
10. श्रीमती रमानी मुथाना
11. श्रीमती निर्मला माथन
12. श्री सनम गोरखपुरी
13. श्रीमती पदमा गोबोले
14. डा. के.बी. रथी
15. श्रीमती एस. जैड. गोगाटे
16. श्रीमती ललिता कामत
17. श्रीमती डोली सिंह
18. श्री सुरेन्द्र झा
19. श्रीमती सईदा खान
20. श्रीमती नजमा गोरियावाला
21. श्री मानिन्द्र सिंह

[फा.सं. 811/1/85-फ(सी)]
इकबाल कृष्ण, अवर सचिव

S.O. 1884.—In exercise of the powers conferred by section 5(1) of the Cinematograph Act, 1952 read with sub-rule (1) of rule 8 of the Cinematograph (Certification) Rules 1983, the Central Government hereby directs that the following persons shall cease to be members of the Bombay Advisory Panel of the Board of Film Certification with effect from 15th April, 1986.

1. Shri A.M.I. Dalvi
2. Smt. Ranjan Amin
3. Sm. Prafulla Dahanukar
4. Dr. Mukesh Batra
5. Kum. Commi Chinoy
6. Smt. Maya Manikar
7. Shri R.C. Dalal
8. Smt. Salloocana Gulati
9. Smt. Lalita Jairaj
10. Smt. Ramani Muthanna
11. Smt. Nirmala Mathan
12. Shri Sanam Gorakhpuri
13. Smt. Padma Gobole
14. Dr. K.B. Rathi
15. Smt. S.A. Gogate
16. Smt. Lalita Kamat
17. Smt. Dolly Singh
18. Shri Suresh Jha
19. Smt. Saeeda Khan
20. Smt. Najma Goriawala
21. Shri Maninder Singh

[File No. 811|1|85-F(C)]
IQBAL KRISHAN, Under Secy.

परिवहन मंत्रालय

(जल-भूतल परिवहन विभाग)

नई दिल्ली 23 अप्रैल, 1986

(नौवहन पक्ष)

का.आ. 1885.—वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 7 उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना क्रम सं. का.आ. 264, दिनांक 26 अप्रैल, 1985 के अधिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार श्री एन. चक्रवर्ती के स्थान पर श्री परवीन सिंह को, पद-भार संभालने की तारीख से नौवहन महानिदेशक नियुक्त करती है।

[सं. एस डब्ल्यू/1-एम डी एस (6)/85-एम ए)]
पी.वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

(Shipping Wing)

New Delhi, the 23rd April, 1986

(Merchant Shipping)

S.O. 1885.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and in supersession of Notification of the Government of India, Ministry of Shipping and Transport, No. S.O. 264, dated 26th April, 1985, the Central Government hereby appoints, from the date of taking over charge, Shri Parveen Singh as the Director General of Shipping vice Shri N. Chakraborty.

[No. SW|1-MDS(6)|85-MA]
P. V. RAO, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1986

का.आ. 1886.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खंड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 634अ, तारीख 28 फरवरी, 1957 को, जहां तक इसका संबंध विपणन और निरीक्षण निदेशालय से है, अधिक्रांत करते हुए, निम्नलिखित आदेश करते है, अर्थात्:—

संलग्न अनुसूची के भाग 1 और भाग 2 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट विपणन और निरीक्षण निदेशालय के साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" और समूह "घ" पदों की बाबत, स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी होगा और स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट शास्तियों की बाबत स्तम्भ (3) और (5) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी क्रमशः अनुशासन प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी होंगे।

अनुसूची

भाग 1-साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग"

पद का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति अधिरोपित करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी	शास्ति की प्रकृति	अपील प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सभी पद	संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार, शाखा मुख्यालय, नागपुर	संयुक्त विपणन सलाहकार, शाखा मुख्यालय, नागपुर	सभी	कृषि विपणन सलाहकार

भाग-2 साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ"

पद का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति अधिरोपित करने के लिए, अनुशासन प्राधिकारी	शास्ति की प्रकृति	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
सभी पद	संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार, शाखा मुख्यालय नागपुर	संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार शाखा मुख्यालय, नागपुर	सभी	कृषि विपणन सलाहकार

[सं. 17-70/82-एम-आई]
अनीता चौधरी, उपसचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
Department of Rural Development

New Delhi, the 28th April, 1986

S.O. 1886.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and clause (ii) of sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture No. S.R.O. 634-A, dated the 28th February, 1957, in so far as it relates to the Directorate of Marketing and Inspection, the President hereby makes the following notification, namely.—

In respect of the posts in the General Central Services, Group 'C' and Group 'D' of the Directorate of Marketing and Inspection specified in column (1) of Part I and Part II of the schedule, the authority specified in columns 2 shall be the appointing authority and the authorities specified in columns 3 and 5 shall be the disciplinary authority and appellate authority respectively in regard to the penalties specified in column 4.

SCHEDULE

Part I — General Central Service Group 'C'

Description of post	Appointing authority	Disciplinary authority to impose penalties	Nature of penalties	Appellate authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
All posts	Joint Agricultural Marketing Adviser, Branch Head Office, Nagpur.	Joint Agricultural Marketing Adviser, Branch Head Office, Nagpur.	All	Agricultural Marketing Adviser.

Part II — General Central Service Group 'D'

Description of post	Appointing authority	Disciplinary authority to impose penalties	Nature of penalties	Appellate authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
All posts	Joint Agricultural Marketing Adviser, Branch Head Office, Nagpur.	Joint Agricultural Marketing Adviser, Branch Head Office, Nagpur.	All	Agricultural Marketing Adviser.

[No. 17-70/82-M.L.]
ANITA CHAUDHARY, Dy. Sec

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1986

का.आ. 1887.—राष्ट्रपति केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 34 के साथ पठित नियम 9 के उपनियम (2) नियम 12 के उपनियम (2) के खंड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व संचार मंत्रालय (डाक और तार) की अधिसूचना संख्यांक का. नि.आ. 620 तारीख 28 फरवरी, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के भाग 2—साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" में रेल डाक कार्यालय शीर्ष के अधीन सभी अन्य पद प्रविष्टि के सामने स्तंभ 3, 4 और 5 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त में अन्तः स्थापित की जाएंगी अर्थात्:—

स्तंभ 3	स्तंभ 4	स्तंभ 5
सहायक अधीक्षक रेल डाक सेवा	(i)	ज्येष्ठ रेल डाक अधीक्षक

[सं. 12/3/85-विजी.-III]

बी.पी. शर्मा, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

New Delhi, the 24th April, 1986

S.O. 1887.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 9, clause (b) of Sub-Rule (2) of Rule 12 and Sub-rule 1 of rule 24, read with rule 34, of the C.C.S. (CCA) Rules, 1965, the President hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Communications (Posts & Telegraphs) No. SRO 520 dated the 28th February, 1957, namely:—

In the Schedule to the said notification in part II-General Central Service, Group C, under the heading "Railway Mail Offices, against the entry" All other posts" under column 3, 4 and 5, after the existing entries, the following entries shall be inserted at the end, namely:—

Col. 3	Col. 4	Col.5
Assistant Superintendent, Railway Mail Service.	(1)	Senior Superintendent Railway Mail Service

[No. 12|3|85-Vig. III]

(तार संचार विभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1986

का.आ. 1888:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने तलैवासल, रामानुजपुरम, पड्डनैकेनपालयम तथा वीरपोन्टी टेलीफोन केन्द्रों, तमिलनाडु में दिनांक 16-5-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-10/1986-पी एच बी]

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 23rd April, 1986

S.O. 1888.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March 1960, the Director General Department of Telecommunications, hereby specifies 16-5-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Talaivasal, Ramanujapuram, Peddenaiekenpalayam and Veerapondy Telephone Exchanges, Tamil Nadu Circle.

[No. 5—10|86-PHB]

नई दिल्ली 30 अप्रैल, 1986

का. आ. 1889.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा(क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने करियापट्टी तथा इलायिरामपन्नै टेलीफोन केन्द्र तमिलनाडु में दिनांक 10-5-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-33/86-पी एच बी]

New Delhi, the 30th April, 1986

S.O. 1889.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specifies 10th May, 1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Kariapatti and Elayirampannai Telephone Exchanges, Tamil Nadu Telecom Circle.

[No. 5-33/86-PHB]

नई दिल्ली, 1 मई, 1986

का. आ. 1890.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा(क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने मडातारा तथा कडक्कल टेलीफोन केन्द्र केरला में दिनांक 15-5-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-32/86-पी एच बी]

के.पी. शर्मा, सहायक महानिदेशक (पी.एच.बी.)

New Delhi, the 1st May, 1986

S.O. 1890.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specifies 15th May, 1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Madathara and Kadakkal Telephone Exchanges, Kerala Telecom. Circle.

[No. 5-32/86-PHB]

K. P. SHARMA, Assistant Director Genl. (PHB)

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली 14 अप्रैल, 1986

का. आ. 1891.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन 537 लाईसेंसों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, उनका अगस्त 1985 में नवीकरण किया गया है।

अनुसूची

क्रम संख्या	सी एम/एल संख्या	वैध तक
1	2	3
1.	0013413	1986-07-31
2.	0013615	1986-08-15
3.	0013716	1986-06-30
4.	0017320	1986-07-15
5.	0050015	1986-08-31
6.	0053829	1986-08-31
7.	0055530	1986-07-15

(1)	(2)	(3)
8.	0063731	1986-07-15
9.	0065634	1986-07-31
10.	0071033	1986-07-31
11.	0071134	1986-07-31
12.	0072429	1986-07-31
13.	0075839	1986-07-31
14.	0077641	1986-07-31
15.	0080933	1986-06-30
16.	0081026	1986-06-30
17.	0083131	1985-11-15
18.	0068232	1985-11-15
19.	0102008	1986-08-15
20.	0105216	1986-06-30
21.	0112213	1986-08-15
22.	0113619	1986-08-15
23.	0121618	1986-07-15
24.	0129836	1986-07-15
25.	0130720	1986-07-31
26.	0132522	1986-08-15
27.	0146937	1986-07-31
28.	0149034	1986-08-15
29.	0149135	1986-08-15
30.	0149236	1986-08-15
31.	0149943	1986-04-30
32.	0157841	1986-07-31
33.	0158540	1986-06-30
34.	0160830	1986-03-31
35.	0164939	1985-11-15
36.	0169848	1986-06-30
37.	0171128	1986-06-15
38.	0172938	1986-08-31
39.	0182133	1986-06-15
40.	0194241	1986-08-15
41.	0196346	1986-06-15
42.	0199958	1986-06-30
43.	0202315	1986-07-31
44.	0202719	1986-07-31
45.	0203822	1985-09-30
46.	0218633	1986-07-31
47.	0228737	1986-05-31
48.	0228838	1986-05-31
49.	0231524	1986-07-31
50.	0241224	1986-07-31
51.	0252835	1986-07-31
52.	0271940	1986-07-31
53.	0273136	1986-08-15
54.	0278853	1986-06-30
55.	0280234	1986-06-30
56.	0281842	1986-05-31
57.	0288957	1986-05-15
58.	0297554	1986-08-31
59.	0299053	1986-08-31
60.	0309232	1986-07-15
61.	0309333	1986-07-31
62.	0310116	1986-06-30
63.	0310823	1986-07-31
64.	0313627	1986-08-31
65.	0320321	1986-08-31
66.	0329541	1986-08-15
67.	0332934	1986-07-31
68.	0337439	1986-01-15
69.	0338340	1986-08-31
70.	0345640	1986-06-30
71.	0346945	1986-07-31
72.	0347240	1986-07-15
73.	0347442	1986-07-15
74.	0347543	1986-07-15
75.	0348040	1986-07-15
76.	0348141	1986-07-15
77.	0351534	1986-08-15
78.	0351736	1986-08-15
79.	0357849	1986-06-30
80.	0358346	1985-12-31
81.	0361537	1986-05-31
82.	0364139	1986-06-30
83.	0381442	1986-07-31
84.	0385248	1986-06-15
85.	0385349	1986-06-15
86.	0385450	1986-06-15
87.	0385955	1986-07-31
88.	0387252	1986-07-15
89.	0388052	1986-07-15
90.	0390241	1986-07-31
91.	0391243	1986-07-31
92.	0391344	1986-07-31
93.	0402323	1986-06-30
94.	0424434	1986-07-15
95.	0426943	1986-07-31
96.	0439649	1986-06-15
97.	0442840	1986-08-15
98.	0447446	1986-08-15
99.	0449046	1986-08-15
100.	0449147	1986-07-15
101.	0449248	1986-07-15
102.	0449349	1986-08-31
103.	0449551	1986-07-31
104.	0449753	1986-07-31
105.	0450132	1986-07-31
106.	0450233	1986-07-31
107.	0451942	1986-08-15
108.	0452136	1986-07-31
109.	0452843	1986-08-31
110.	0455243	1986-08-15
111.	0457651	1986-08-15
112.	0457752	1986-08-15
113.	0483248	1986-07-31
114.	0483450	1985-08-31
115.	0489361	1986-09-30
116.	0493453	1986-07-31
117.	0499364	1986-06-30
118.	0503329	1986-07-15
119.	0512734	1986-07-31
120	0515134	1986-08-15
121.	0523133	1986-06-30
122.	0523638	1986-06-30
123.	0531233	1966-06-30
124.	0531334	1986-08-30
125.	0532740	1986-07-31
126.	0532841	1986-07-31
127.	0532942	1986-07-31
128.	0535039	1986-07-15
129.	0535342	1986-07-15
130.	0536142	1986-07-15
131.	0537245	1986-07-31
132.	0538348	1986-07-31
133.	0539148	1986-07-31
134.	0529855	1986-07-31
135.	0540032	1986-09-30
136.	0540739	1986-10-15
137.	0541741	1986-08-15
138.	0542541	1996-07-31
139.	0542642	1986-08-15
140.	0543240	1986-08-15
141.	0543341	1986-08-15

(1)	(2)	(3)
142.	0546953	1986-09-15
143.	0561343	1986-07-31
144.	0561444	1986-07-31
145.	0572449	1986-06-30
146.	0579867	1986-07-31
147.	0586560	1986-06-30
148.	0587563	1986-07-31
149.	0592152	1986-07-31
150.	0597361	1986-08-31
151.	0608243	1986-07-31
152.	0610734	1986-08-31
153.	0612137	1986-07-15
154.	0613538	1986-06-30
155.	0614742	1985-05-31
156.	0617950	1986-06-30
157.	0622741	1986-07-15
158.	0623945	1986-07-31
159.	0624614	1986-07-15
160.	0629 50	1986-07-15
161.	0629856	1986-07-31
162.	0629957	1986-07-31
163.	0630437	1986-07-31
164.	0630538	1986-07-31
165.	0630942	1986-07-31
166.	0634037	1986-08-15
167.	0632138	1986-08-15
168.	0632239	1986-08-15
169.	0632643	1986-08-15
170.	0633342	1986-08-15
171.	0634849	1986-08-15
172.	0635851	1986-08-15
173.	0639253	1986-07-15
174.	0640440	1986-07-15
175.	0642646	1986-09-30
176.	0644044	1986-07-15
177.	0645046	1986-06-30
178.	0657356	1985-11-15
179.	0660042	1986-08-15
180.	0662046	1985-12-31
181.	0672150	1986-09-30
182.	0672251	1986-07-30
183.	0676461	1986-05-31
184.	0677463	1986-07-31
185.	0682557	1985-07-15
186.	0693461	1986-08-15
187.	0701333	1986-05-31
188.	0704844	1986-06-15
189.	0705846	1986-06-30
190.	0706343	1986-06-15
191.	0708347	1986-06-30
192.	0708751	1986-06-30
193.	0710031	1986-07-15
194.	0712742	1986-07-31
195.	0716548	1986-05-31
196.	0719554	1985-11-15
197.	0735552	1985-11-30
198.	0753756	1986-06-15
199.	0775665	1986-06-15
200.	0780759	1986-06-30
201.	0781559	1986-06-30
202.	0782460	1986-06-30
203.	0784060	1986-07-15
204.	0784363	1986-07-15
205.	0784464	1986-07-15
206.	0785466	1986-07-15
207.	0785567	1986-07-15
208.	0786266	1986-07-31
209.	0786367	1986-07-31
210.	0786670	1986-07-31
211.	0787571	1986-07-31
212.	0787672	1986-07-31
213.	0787975	1986-07-31
214.	0788775	1986-07-31
215.	0789373	1986-08-15
16.	0789676	1986-08-15
217.	0789877	1986-08-15
218.	0789678	19 6-08-15
219.	0790257	1986-08-15
220.	0790459	1986-08-15
221.	0790560	1986-08-15
222.	0791057	1986-08-15
223.	0791360	1986-08-15
224.	0791764	1986-08-15
225.	0793667	1986-08-31
226.	0794467	1986-08-31
227.	0795974	1986-08-31
228.	0819558	1986-05-31
229.	0834251	1986-06-30
230.	0842553	1986 07-15
231.	0851857	1986-07-31
232.	0863561	1986-07-31
233.	0865969	1986-04-30
234.	0867367	1986-07-31
235.	0670356	1986-06-15
236.	0871661	1986-06-15
237.	0874263	1986-06-30
238.	0875063	1986-06-30
239.	0875164	1986-06-30
240.	0876875	1986-06-30
241.	0877471	1986-07-15
242.	0877572	1986-07-15
243.	0879475	1986-07-15
244.	0879576	1986-07-15
245.	0880662	1986-07-31
246.	0881058	1986-07-31
247.	0881260	1986-07-31
248.	0681462	1986-07-31
249.	0881563	1986-07-31
250.	0881765	1986-07-31
251.	0882363	1986-07-31
252.	0883264	1986-07-31
253.	0883466	1986-08-15
254.	0883769	1986-07-31
255.	0884670	1986-08-15
256.	0884872	1986-08-15
257.	0884973	1986-08-15
258.	0885773	1986-08-15
259.	0886977	1986-08-15
260.	0887070	1986-07-31
261.	0887171	1986-08-15
262.	0888577	1986-08-15
263.	0889478	1986-08-31
264.	0889983	1986-08-31
265.	0890362	1986-08-31
266.	0891162	1986-07-31
267.	0891667	1986-08-31
268.	0893671	1986-08-31
269.	0899481	1985-09-30
270.	0899582	1985-09-30
271.	0957469	1986-03-31
272.	0966773	1986-05-15
273.	0967169	1986-05-15

(1)	(2)	(3)
274.	0967472	1986-07-31
275.	0967573	1986-07-31
276.	0969173	1986-05-31
277.	0971362	1986-05-31
278.	0971564	1986-07-31
279.	0972263	1986-06-15
280.	0975370	1986-06-15
281.	0977374	1986-06-30
282.	0977879	1986-06-30
283.	0978679	1986-07-15
284.	0978982	1986-07-15
285.	0979984	1986-07-15
286.	0980060	1986-07-15
287.	0982064	1986-07-31
288.	0982367	1986-07-31
289.	0982468	1986-07-15
290.	0982973	1986-07-31
291.	0983268	1986-07-31
292.	0983369	1986-07-31
293.	0983672	1986-07-31
294.	0983773	1986-07-31
295.	0983874	1986-07-31
296.	0983975	1986-07-31
297.	0984068	1986-07-31
298.	0984573	1986-08-15
299.	0984674	1986-08-15
300.	0985171	1986-08-15
301.	0985676	1986-08-15
302.	0985777	1986-08-15
303.	0985979	1986-01-15
304.	0986274	1986-08-15
305.	0987579	1985-08-15
306.	0987781	1986-08-15
307.	0989381	1986-08-31
308.	1032927	1986-07-15
309.	1035731	1986-06-30
310.	1041928	1986-03-15
311.	1043326	1986-03-15
312.	1052127	1986-09-15
313.	1057741	1986-03-31
314.	1057842	1986-03-31
315.	1070228	1986-08-15
316.	1077646	1986-05-31
317.	1076648	1986-07-31
318	1086748	1986-06-15
319.	1087649	1986-06-15
320.	1087750	1985-06-15
321.	1090941	1986-06-15
322.	1091034	1986-06-15
323.	1093543	1986-07-15
324.	1094747	1986-07-15
325.	1095042	1986-07-15
326.	1095143	1986-07-15
327.	1095244	1986-07-15
328.	1095951	1986-07-15
329.	1096448	1986-07-15
330.	1097046	1986-06-30
331.	1097551	1986-07-15
332.	1098250	1986-07-15
333.	1099353	1986-07-31
334.	1100514	1986-07-31
335.	1100615	1986-07-15
336.	110918	1986-07-31
337.	1101213	1986-07-31
338.	1101314	1986-07-31
339.	1102114	1986-07-31
340.	1102720	1986-07-31
341.	1103419	1986-08-15
342.	1103722	1986-08-15
343.	1103924	1986-08-15
344.	1105322	1986-07-31
345.	1105324	1086-07-31
346.	1105827	1986-07-31
347.	1106122	1986-08-15
348.	1106223	1986-08-15
349.	1106324	1986-08-15
350.	1106627	1986-08-15
351.	1106728	1986-08-15
352.	1107124	1986-07-31
353.	1107730	1986-08-15
354.	1108126	1986-08-31
355.	1108833	19 6-08-31
356.	1110517	1986-08-31
357.	1111014	1986-08-31
358.	1111418	1986-08-31
359	1111519	1986-08-31
360.	1113321	1986-08-31
361.	1115234	1986-09-15
362.	1126330	1985-10-31
363.	1136131	1985-12-15
364.	1136333	1985-12-15
365.	1152735	1986-07-15
366.	1160835	1986-02-15
367.	1161332	1986-02-15
368.	1169045	1986-03-15
369.	1188049	1986-05-31
370.	1168251	1986-05-31
371.	1188756	1986-05-31
372.	1190945	1986-05-31
373.	1192242	1986-03-15
374.	1193042	1986-06-15
375.	1193345	1986-06-15
376.	1195248	1986-06-15
377.	1195652	1986-06-15
378.	1196250	1986-07-31
379.	1196856	1986-06-15
380.	1198961	1986-06-15
381.	1199963	1986-06-30
382.	1200013	1986-06-30
383.	1200316	1986-06-30
384.	1201118	1986-06-30
385.	1201217	1986-06-30
386.	1202118	1986-06-30
387.	1202219	1986-06-30
388.	1202724	1986-07-15
389.	1202825	1986-07-15
390.	1204425	1986-06-30
391.	1204526	1986-06-30
392.	1204627	1986-06-30
393.	1204728	1986-06-30
394.	1204829	1986-06-30
395.	1205124	1986-06-30
396.	1205528	1986-06-30
397.	1205629	1986-06-30
398.	1205730	1986-06-30
399.	1205831	1986-06-30
400.	1205932	1986-06-30
401.	1206025	1986-06-30
402.	1206126	1986-06-30
403.	1207431	1986-06-15

(1)	(2)	(3)
404.	1207532	1986-07-15
405.	1207835	1986-06-30
406.	1207936	1986-06-30
407.	1208029	1986-07-15
408.	1208231	1986-06-30
409.	1209940	1986-06-30
410.	1210017	1986-06-30
411.	1210218	1986-07-15
412.	1210521	1986-07-15
413.	1210622	1986-07-15
414.	1210723	1986-07-31
415.	1210925	1986-07-31
416.	1211521	1986-07-31
417.	1211523	1986-06-30
418.	1212328	1986-07-31
419.	1212826	1986-07-31
420.	1212727	1986-07-31
421.	1212828	1986-07-15
422	1212929	1986-07-15
423.	1213022	1986-06-30
424.	1213123	1986-07-31
425.	1213325	1986-07-15
426.	1213830	1986-07-31
427.	1216129	1986-07-31
428.	1217335	1986-06-30
427.	1217636	1986-06-30
430.	1217737	1986-06-30
431.	1217959	1986-06-30
432.	1218032	1986-06-30
433.	1218133	1986-06-30
434.	1218537	1986-06-30
435.	1218638	1986-06-30
436.	1218737	1986-06-30
437.	1218840	1986-07-31
438.	1218941	1986-06-30
439.	1219135	1986-07-31
440.	1219236	1986-06-30
441.	1219438	1986-06-30
442.	1219741	1986-08-15
433.	1219842	1986-08-15
444.	1219843	1986-08-15
445.	1220625	1986-08-15
446.	1220928	1986-06-30
447.	1221122	1986-07-31
448.	1221223	1986-07-31
449.	1221324	1986-07-31
450.	1221425	1986-06-30
451.	1221728	1986-07-31
452.	1221829	1986-07-31
453.	1222023	1786-07-31
454	1222831	1986-08-15
455	1222932	1986-08-15
456.	1223028	1986-07-31
457	1223126	1986-07-31
458.	1223227	1986-08-15
459.	1223429	1986-07-31
460.	1223530	1986-07-31
461.	1223833	1986-07-31
462.	1223934	1986-07-31
463.	1224027	1986-07-31
464.	1224128	1986-07-31
465.	1224633	1986-07-31
466.	1224734	1986-07-31
467.	1225332	1986-08-15
468.	1225433	1986-08-15
469.	1225534	1986-08-15
470.	1225635	1986-08-15
471.	1228944	1986-08-15
472.	1229138	1986-08-31
473.	1229744	1986-08-31
474.	1230123	1986-07-31
475.	1246643	1986-01-15
476.	1247140	1985-11-15
477.	1250735	1985-11-30
478.	1267247	1986-01-31
479.	1279759	1986-02-28
480.	1287857	1986-03-15
481.	1269762	1986-03-15
482.	1305835	1986-04-30
483.	1310020	1986-05-15
484.	1311729	1986-05-31
486.	1315535	1986 06-15
486.	1316638	1986-06-15
487.	1317640	1986-06-15
488.	1317941	1986-06-30
489.	1318844	1986-06-30
490.	1318945	1986-06-30
491.	1319341	1986-06-30
492.	1319947	1986-06-30
493.	1320124	1986-06-30
494.	1320326	1986-06-30
495.	1320730	1986-06-30
496.	1321025	1986-06-30
497.	1321227	1986-06-30
498.	1321530	1986-06-30
499.	1322128	1986-07-15
500.	1322229	1986-07-15
501.	1323231	1986-07-15
502.	1323332	1986-07-15
503.	1323837	1986-07-15
504.	1323938	1986-07-15
503.	1324536	1986-07-15
506.	1325134	1986-07-15
507.	1325336	1986-07-15
508.	1325639	1986-07-31
509.	1325740	1986-07 31
510.	1325841	1986-07-31
511.	1326944	1986-07-31
512.	1327037	1986-07-31
513.	1327138	1986-07-31
514.	1327441	1986-07-31
515.	1327542	1986-08-15
516.	1327643	1986-07-31
517.	1328140	1986-07-31
518.	1328645	1986-07-31
519.	1329546	1986-08-15
520.	1329748	1986-07-31
521.	1329950	1986-07-31
522.	1330127	1986-07-31
523.	1330430	1986-08-15
524.	1330834	1986-08-15
525.	1331432	1986-08-15
526.	1331735	1986-08-15
527.	1331836	1986-08-15
528.	1332737	1086-07-31
529.	1333438	1986-08-15
530.	1333638	1985-08-15
531.	1335339	1986-08-15
532.	1336543	1986-08-31
533.	1336745	1986-08-31
534.	1336846	1986-08-31
535.	1337646	1986-08-31
536.	1338244	1986-08-31
537.	1341233	1986-08-31

[सं एम डी/13:12]

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 14th April, 1986

S.O.1891.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that 537 licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been renewed during the month of August, 1985.

SCHEDULE

Sl. No.	CM/L No.	Valid upto
1	2	3
1.	0013413	1986-07-31
2.	0013615	1986-08-15
3.	0013716	1986-06-30
4.	0017320	1986-07-15
5.	0050015	1986-08-31
6.	0053829	1986-08-31
7.	0055530	1986-07-15
8.	0063731	1986-07-15
9.	0065634	1986-07-31
10.	0071023	1986-07-31
11.	0071124	1986-07-31
12.	0072479	1986-07-31
13.	0075839	1986-07-31
14.	0077641	1986-07-31
15.	0080933	1986-06-30
16.	0081026	1986-06-30
17.	0083131	1985-11-15
18.	0083232	1985-11-15
19.	0102008	1986-08-15
20.	0105216	1986-06-30
21.	0112213	1986-08-15
22.	0113619	1986-08-15
23.	0121618	1986-07-15
24.	0129836	1986-07-15
25.	0130720	1986-07-31
26.	0132521	1986-08-15
27.	0146937	1986-07-31
28.	0149034	1986-08-15
29.	0149135	1986-08-15
30.	0149236	1986-08-15
31.	0149943	1986-04-30
32.	0157841	1986-07-31
33.	0158540	1986-06-30
34.	0160830	1986-03-31
35.	0161939	1985-11-15
36.	0169848	1986-06-30
37.	0171128	1986-06-15
38.	0172938	1986-08-31
39.	0182133	1986-06-15
40.	0194241	1986-08-15
41.	0176346	1986-06-15
42.	0199958	1986-06-30
43.	0200315	1986-07-31
44.	0202719	1986-07-31
45.	0203822	1985-09-30
46.	0218633	1986-07-31
47.	0228737	1986-05-31
48.	0228838	1986-05-31
49.	0231524	1986-07-31
50.	0241224	1986-07-31
51.	0252835	1986-07-31
52.	0271940	1986-07-31
53.	0273136	1986-08-15
54.	0278853	1986-06-30
55.	0280234	1986-06-30
56.	0281842	1986-05-31
57.	0288957	1986-05-15
58.	0297554	1986-08-31
59.	0299053	1986-08-31
60.	0309232	1986-07-15
61.	0309333	1986-07-31
62.	0310116	1986-06-30
63.	0310823	1986-07-31
64.	0313627	1986-08-31
65.	0320321	1986-08-31
66.	0329541	1986-08-15
67.	0332934	1986-07-31
68.	0337439	1986-01-15
69.	0338340	1986-08-31
70.	0345640	1986-06-30
71.	0346945	1986-07-31
72.	0347240	1986-07-15
73.	0347442	1986-07-15
74.	0347543	1986-07-15
75.	0348040	1986-07-15
76.	0348141	1986-07-15
77.	0351534	1986-08-15
78.	0351736	1986-08-15
79.	0357849	1986-06-30
80.	0358316	1985-12-31
81.	0361537	1986-05-31
82.	0364139	1986-06-30
83.	0381442	1986-07-31
84.	0385248	1986-06-15
85.	0385349	1986-06-15
86.	0385450	1986-06-15
87.	0385955	1986-07-31
88.	0387251	1986-07-15
89.	0388052	1986-07-15
90.	0390241	1986-07-31
91.	0391243	1986-07-31
92.	0391344	1986-07-31
93.	0402373	1986-07-30
94.	0424434	1986-07-15
95.	0426913	1986-07-31
96.	0439649	1986-06-15
97.	0442840	1986-08-15
98.	0447446	1986-08-15
99.	0449046	1986-08-15
100	0449147	1986-07-15
101.	0449248	1986-07-15
102.	0449349	1986-08-15
103.	0449551	1986-07-31
104.	0449753	1986-07-31
105.	0450132	1986-07-31
106	0450233	1986-07-31
107.	0451943	1986-08-15
108.	0452136	1986-07-31
109.	0452843	1986-08-31
110.	0455243	1986-08-15
111.	0457651	1986-08-15
112.	0457752	1986-08-15
113.	0483248	1986-08-15
114.	0483450	1985-07-31
115.	0389361	1985-09-30

1	2	3
116.	0493453	1986-07-31
117.	0499364	1986-06-30
118.	0503329	1986-07-15
119.	0512734	1986-07-31
120.	0515134	1986-08-15
121.	0523133	1986-06-30
122.	0523638	1986-06-30
123.	0531233	1986-06-30
124.	0531334	1986-06-30
125.	0531740	1986-07-31
126.	0531841	1986-07-31
127.	0532942	1986-07-31
128.	0535039	1986-07-15
129.	0535342	1986-07-15
130.	0536142	1986-07-15
131.	0537245	1986-07-31
132.	0538348	1986-07-31
133.	0539148	1986-07-31
134.	0529855	1986-07-31
135.	0540032	1986-09-30
136.	0540739	1986-10-15
137.	0541741	1986-08-15
138.	0542541	1986-07-31
139.	0542642	1986-08-15
140.	0543240	1986-08-15
141.	0543341	1986-08-15
142.	0546953	1986-09-15
143.	0561343	1986-07-31
144.	0561444	1986-07-31
145.	0572449	1986-06-30
146.	0579867	1986-07-31
147.	0585660	1986-06-30
148.	0587563	1986-07-31
149.	0592152	1986-07-31
150.	0597364	1986-08-31
151.	0608343	1986-07-31
152.	0610734	1986-07-31
153.	0612132	1986-07-15
154.	0613538	1986-06-30
155.	0614742	1986-05-31
156.	0617950	1986-06-30
157.	0622741	1986-07-15
158.	0623945	1986-07-31
159.	0624644	1986-07-15
160.	0626250	1986-07-15
161.	0629856	1986-07-31
162.	0629957	1986-07-31
163.	0630437	1986-07-31
164.	0630538	1986-07-31
165.	0630943	1986-07-31
166.	0632037	1986-08-15
167.	0632138	1986-08-15
168.	0632239	1986-08-15
169.	0633643	1986-08-15
170.	0633342	1986-08-15
171.	0634839	1986-08-15
172.	0635851	1986-08-15
173.	0639253	1986-07-15
174.	0640340	1986-07-15
175.	0642646	1985-09-30
176.	0644044	1986-07-15
177.	0645046	1986-06-30
178.	0657356	1985-11-15
179.	0660042	1986-08-15
180.	0660646	1985-12-31
181.	0672150	1986-09-30
182.	067225	1986-09-30
183.	0676461	1986-05-31
184.	0677453	1986-07-31
185.	0682557	1985-07-15
186.	0693461	1986-08-51
187.	0701333	1986-05-31
188.	0704844	1986-06-15
189.	0705846	1986-06-30
190.	0706343	1986-06-15
191.	0708347	1986-06-30
192.	0708751	1986-06-30
193.	0710031	1986-07-15
194.	0712742	1986-07-31
195.	0716548	1986-05-31
196.	0719554	1986-11-15
197.	0735552	1985-11-30
198.	0753756	1986-06-15
199.	0775665	1986-06-15
200.	0780759	1986-06-30
201.	0781559	1986-06-30
202.	0782460	1986-06-30
203.	0784060	1986-07-15
204.	0784363	1986-07-15
205.	0784464	1986-07-15
206.	0785466	1986-07-15
207.	0785567	1986-07-15
208.	0786266	1986-07-31
209.	0786367	1986-07-31
210.	0786670	1986-07-31
211.	0787571	1986-07-31
212.	0787672	1986-07-31
213.	0787975	1986-07-31
214.	0788775	1986-07-31
215.	0789373	1986-08-15
216.	0789676	1986-08-15
217.	0789777	1986-08-15
218.	0789878	1986-08-15
219.	0790257	1986-08-15
220.	0790459	1986-08-15
221.	0790560	1986-08-15
222.	0791057	1986-08-15
223.	0771360	1986-08-15
224.	0791764	1986-08-15
225.	0793667	1986-08-31
226.	0794467	1986-08-31
227.	0795974	1986-08-31
228.	0819558	1986-05-31
229.	0834251	1986-06-30
230.	0842553	1986-07-15
231.	0851857	1986-07-31
232.	0863561	1986-07-31
233.	0865969	1986-04-30
234.	0867367	1986-07-31
235.	0870356	1986-06-15
236.	0871661	1986-06-15
237.	0874263	1986-06-30
238.	0875063	1986-06-30
239.	0875164	1986-06-30
240.	0876873	1986-06-30
241.	0877471	1986-07-15
242.	0877572	1986-07-15
243.	0879475	1986-07-15
244.	0879576	1986-07-15
245.	0870662	1986-07-31
246.	0881058	1986-07-31
247.	0871260	1986-07-31

(1)	(2)	(3)
248.	0881462	1986-07-31
249.	0881563	1986-07-31
250.	0881765	1986-07-31
251.	0882363	1986-07-31
252.	0883264	1986-07-31
253.	0883466	1986-08-15
254.	0883769	1986-07-31
255.	0884670	1986-08-15
256.	0884872	1986-08-15
257.	0884973	1986-08-15
258.	0885773	1986-08-15
259.	0886977	1986-08-15
260.	0887070	1986-07-31
261.	0887171	1986-08-15
262.	0888577	1986-08-15
263.	0889478	1986-08-31
264.	0889983	1986-08-31
265.	0890362	1986-08-31
266.	0891162	1986-07-31
267.	0891667	1986-08-31
268.	0893671	1986-08-31
269.	0899481	1985-09-30
270.	0899582	1985-09-30
271.	0957469	1986-09-31
272.	0966773	1986-05-15
273.	0967169	1986-05-15
274.	0967472	1986-07-31
275.	0967573	1986-07-31
276.	0969173	1986-05-31
277.	0971362	1986-05-31
278.	0971564	1986-07-31
279.	0972263	1986-06-15
280.	0975370	1986-06-15
281.	0977374	1986-06-30
282.	0977879	1986-06-30
283	0978679	1986-07-15
284	0978982	1986-07-15
285.	0979984	1986-07-15
286.	0980060	1986-07-15
287.	0982064	1986-07-31
288.	0982367	1986-07-31
289.	0982468	1986-07-15
290.	0982973	1986-07-31
291.	0983268	1986-07-31
292.	0983369	1986-07-31
293.	0983672	1986-07-31
294.	0983773	1986-07-31
295	0983874	1986-07-31
296.	0983975	1986-07-31
297.	0984068	1986-07-31
298.	0984573	1986-08-15
299.	0984674	1986-08-15
300.	0985171	1986-08-15
301.	0985676	1986-08-15
302.	0985777	1986-08-15
303.	0985979	1986-08-15
304.	0986274	1986-08-15
305.	0987579	1985-08-15
306.	0987781	1986-08-15
307.	0989381	1986-08-31
308.	1032927	1986-07-15
309.	1035731	1986-06-30
310.	1041928	1986-03-15
311.	1043326	1986-03-15
312.	1053127	1986-90-15
313.	1057741	1986-03-31
314.	1057842	1986-03-31
315.	1070228	1986-08-15
316.	1077646	1986-05-31
317.	1078648	1986-07-31
318.	1086748	1986-06-15
319.	1087649	1986-06-15
320.	1087750	1985-06-15
321.	1090941	1986-06-15
322.	1091034	1986-06-15
323.	1093543	1986-07-15
324.	1094747	1986-07-15
325.	1095042	1986-07-15
326.	1095143	1986-07-15
327.	1095244	1986-07-15
328.	1095951	1986-07-15
329.	1096448	1986-07-15
330.	1097046	1986-06-30
331.	1097551	1986-07-15
332.	1098250	1986-07-15
333.	1099353	1986-07-31
334.	1100514	1986-07-31
335.	1100615	1986-07-15
336.	110918	1986-07-31
337.	1101213	1986-07-31
338.	1101314	1986-07-31
339.	1102114	1986-07-31
340.	1102720	1986-07-31
341.	1103419	1986-08-15
342.	1103722	1986-08-15
343.	1103924	1986-08-15
344.	1105322	1986-07-31
345.	1105524	1986-07-31
346.	1105827	1986-07-31
347.	1106122	1986-08-15
348.	1106223	1986-08-15
349.	1106324	1986-08-15
350.	1106627	1986-08-15
351.	1106728	1986-08-15
352.	1107124	1986-07-31
353.	1107730	1986-08-15
354.	1108126	1986-08-31
355.	1108833	1986-08-31
356.	1110517	1986-08-31
357.	1111014	1986-08-31
358.	1111418	1986-08-31
359.	1111519	1986-08-31
360.	1113321	1986-08-31
361.	1115224	1986-09-15
362.	1126330	1985-10-31
363.	1136131	1985-12-15
364.	1136323	1985-12-15
365.	1152735	1986-07-15
366.	1160835	1986-02-15
367.	1161332	1986-02-15
368.	1169045	1986-03-15
369.	1188049	1986-05-31
370.	1188251	1986-05-31
371.	1188756	1986-05-31
372.	1190945	1986-05-31
373.	1199242	1986-03-15
374.	1193042	1986-06-15
375.	1193345	1986-06-15
376.	1195248	1986-06-15
377.	1195652	1986-06-15
378.	1196250	1986-07-31
379.	1196856	1986-06-31

(1)	(2)	(3)
380.	1198961	1986-06-15
381.	1199963	1986-06-30
382.	1200013	1986 06 30
383.	1200316	1986-06 30
384.	120[illegible]16	1986-06 30
385.	120[illegible]217	1986-06-30
386.	1202[illegible]18	1986-06-30
387.	1202219	1986-06-30
388.	1202724	1986-07-15
389.	1202825	1986-07-15
390.	1204425	1986-06 30
391.	1204526	1986-06-30
392.	1204627	1986-06 30
393.	1204728	1986-06-30
394.	1204829	1986-06 30
395.	1205124	1986-06-30
396.	1205528	1986-06-30
397.	1205629	1986-06-30
398.	12057[illegible]0	1986-06-30
399.	1205831	1986-06-30
400.	1205932	1986 06 30
401.	1206025	1986-06-30
402.	120[illegible]126	1986-06-30
403.	120743[illegible]	1986-06-15
404.	1207532	1986-07-15
405.	12078[illegible]5	1986-06 30
406.	1207926	1986-06-30
407.	1208029	1986-07-15
408.	[illegible]	1986-06-30
409.	[illegible]	1986-06-30
410.	[illegible]	1986-06 30
411.	[illegible]	1986-07-15
412.	1210521	1986-07-15
413.	1210622	1986-07-15
414.	1210723	1986-07-31
415.	1210925	1986-07-31
416.	1211321	1986-07-31
417.	1211523	1986-06-30
418.	1212323	1986-07-31
419.	1212626	1986-07-31
420.	1212727	1986-07 31
421.	1212828	1986-07-15
422.	1212929	1986-07-15
423.	12[illegible]3022	1986-06-30
424.	[illegible]23	1986-07-31
425.	[illegible]25	1986-07-15
426.	[illegible]	1986-07-31
427.	[illegible]	1986 07-31
428.	[illegible]	1986-06-30
429	121[illegible]626	1986-06 30
430.	121773[illegible]	1986-06-30
431.	1217939	1986-06-30
432.	12180[illegible]	1986-06-30
433.	1218[illegible]	1986-06-30
434.	12185[illegible]7	1986-06-30
435.	12186[illegible]8	1986 06-30
436.	1218739	1986-06-30
437.	1218840	1986-07-31
438.	1218[illegible]	1986-06-30
439.	12[illegible]9[illegible]35	1986-07-31
440.	1219236	1986-06-30
441.	1219438	1986-06-30
442.	1219[illegible]	1986-08-15
443.	121984[illegible]	1986-08-15
444.	121994[illegible]	1986-08 [illegible]
445.	1220625	1986-06-15
446.	1220928	1986-06-30
447.	1221122	1986-07-31
448.	1221223	1986-07-31
449.	1221324	1986-07-31
450.	1221425	1986-06-30
451.	1221728	1986-07-31
452.	1221829	1986-07-31
453.	1222023	1986-07-31
454.	1222831	1986-08-15
455.	1222932	1986-08-15
456.	1223025	1986-07-31
457.	1223126	1986 07-31
458.	1223227	1986-08-15
459.	1223429	1986-07-31
460.	1223530	1986-07-31
461.	1222833	1986-07-31
462.	1223934	1986-07-31
463.	1224027	1986-07-31
464.	1224128	1986-07-31
465.	1224633	1986-07-31
466.	1224734	1986-07-31
467.	1225332	1986-08-15
468.	1225433	1986-08-15
469.	1225534	1986-08-15
470.	1225635	1986-08-15
471.	1228944	1986-08-15
472.	1229138	1986-08-21
473.	1229744	1986-08-31
474.	1230123	1986-07-31
475.	1246643	1986-01-15
476.	1247140	1985-11-15
477.	1250735	1985-11-30
478.	1267247	1986-01-31
479.	1279759	1986-02-28
480.	1287657	1986-03-15
481.	1289762	1986-03-15
482.	1305835	1986-04-30
483.	1310020	1986-05-15
484.	1311729	1986-05-31
485.	1315525	1986-06-15
486.	1316638	1986-06-15
487.	1317640	1986-06-15
488.	1317941	1986-06-30
489.	1318844	1986-06-30
490.	1318945	1986-06-30
491.	1391341	1986-06-30
492.	1319947	1986-06-30
493.	1320124	1986-06-30
494.	1320326	1986-06-30
495.	1320730	1986-06-30
496.	1321025	1986-06-30
497.	1321227	1986-06-30
498.	1321530	1976-06-30
499.	1322128	1986-07-15
500.	1322229	1986-07-15
501.	1323231	1986-07-15
502.	1323332	1986-07-15
503.	1323837	1986-07-15
504.	1323938	1986-07-15
505.	1324536	1986-07-15
506.	1325134	1986-07-15
507.	1325336	1986-07-15
508.	1325639	1986-07-31
509.	1325740	1986-07-31
510.	1325841	1986-07-31
511.	1326944	1986-07-31

1	2	3	3	2	3
512.	1327037	1986-07-31	526.	1331735	1986-08-15
513.	1327138	1986-07-31	527.	1331836	1986-08-15
514.	1327441	1986-07-31	528.	1332737	1986-07-31
515.	1327542	1986-08-15	529.	1333436	1986-08-15
516.	1327643	1986-07-31	530.	1333638	1986-08-15
517.	1328140	1986-07-31	531.	1335339	1986-08-15
518.	1328645	1986-07-31	532.	1336543	1986-08-31
519.	1329546	1986-08-15	533.	1336745	1986-08-31
520.	1329748	1986-07-31	534.	1336846	1986-08-31
521.	1329950	1986-07-31	535.	1337646	1986-08-31
522.	1330127	1986-07-31	536.	1333244	1986-08-31
523.	1330430	1986-08-15	537.	1341233	1986-08-31
524.	1330834	1986-08-15			
525.	1331432	1986-08-15			

[No. CMD/13 : 12]

का. आ. 1892—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियमावली, 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में जिन 103 लाइसेंसों के ब्यौरे दिये गये हैं, लाइसेंस-धारियों को मानक संबंधी मुहर लगाने का अधिकार देते हुए, फरवरी 1983 में स्वीकृत किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं. लाइसेंस संख्या	वैधता की अवधि से	तक	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया और तत्संबंधी पदनाम
1 2	3	4	5	6
1. सीएम/एल-1157442 1983-02-07	83-02-01	84-01-31	वनी कन्टेनर्स लिमि., प्लाट नं. 14, फेज 3, जीडीमेतला, रंगारेड्डी (जि.) आ. प्र.-500854	33.3 लिटर पानी की समाई वाले एलपीजी के लिए झले हुए निम्न कार्बन इस्पात के गैस सिलिण्डर – IS : 3196 - 1974
2. सीएम/एल-1157543 1983-02-07	83-02-16	84-02-15	बैंट ग्रो इंजीनियरिंग एंड जनरल मैन्युफैक्चरर्स, 7, बावली इंडस्ट्रियल इस्टेट, बावली, दिल्ली-110042 कार्यालय : 1/25, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110002	मोटर गाड़ियों के लिए केवल पीवीसी रोधित हल्का काम पश्चावरण रहित – IS : 2465 - 1969
3. सीएम/एल-1157644 1983-02-07	82-12-01	83-11-30	यूनिवर्सल केबल्स लिमि., डा. - बिरला विकास, सतना (म. प्र.)-485001	पीवीसी रोधित (भारी काम) खोल रहित एवं खोल सहित बिजली के केबल: (क) 3.3 किवो और 6.6 किवो तक कार्यकारी वोल्टता के लिए तांबे के चालकों वाले (ख) 3.3 किवो से 11 किवो तक कार्यकारी वोल्टता के लिए एलुमिनियम के चालकों वाले – IS : 1554 (भाग 2) – 1970
4. सीएम/एल-1157745 1983-02-07	83-02-16	84-02-15	सुपर एक्वासेम (इंडिया) प्रा. लि., 14ए, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली - 110015	डिस्टेम्पर, सूखा, अभीष्ट रंग का– IS : 427 - 1965
5. सीएम/एल-1157846 1983-02-07	83-02-16	84-02-15	एम. वी. एस. एफ. (पेन्ट डिवीजन) ए-5/3, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-110032	मिला-मिलाया ताजा पेन्ट ; फिनिशिंग, अंतरंग, सामान्य कार्यों के लिए, भारतीय मानक रंगों का— IS : 3537 – 1966
6. सीएम/एल-1157947 1983-02-07			कर्मी पेन्ट इंडस्ट्रीज, प्लाट नं. 28, रोड नं. 3 कल्तेदान इण्डस्ट्रियल स्टेट, हैदराबाद-500253	एनेमल, कृत्रिम बहिरंग, (क) अन्तर्लेपन और (ख) फिनिशिंग रंग श्रेणी सं. 27 IS : 3432-1974

1	2	3	4	5	6
7.	सी एम/एल-1158040 1983-02-07	83-02-16	84-02-15	चराग केमिकल इंडस्ट्रीज, के-14, इंडस्ट्रियल इस्टेट, अम्बत्तूर, मद्रास-600058 (त. ना.)	ताम्र सल्फेट—तकनीकी ग्रेड- IS : 261-1961
8	सी एम/एल-1158141 1983-02-07	"	"	सन्तानम मैच इंडस्ट्रीज, 1219/2, पांचवी स्ट्रीट, पांडियन नगर, तिरुत्तंगल शिव- काशी (वायर) (त. ना.) (कार्यालय : 12-ए वेयरमैन षण्मुख नाडार रोड, शिवकाशी-626123 (त. ना.)	दियासलाई की डिब्बियां, लकड़ी की तीलियां IS : 2653-1980
9.	सी एम/एल-1158242 1983-02-27	"	"	प्लास्टिक प्रेम मेटल इंडस्ट्रीज, मगनदास कम्पाउंड, रेलवे क्रासिंग के समीप, चन्डलोडिया, अहमदाबाद (गुजरात)	द्रवित पेट्रोलियम गैसों के साथ उपयोग के लिए घरेलू गैस के चूल्हे : (1) एक बर्नर, ढले लोहे की बाडी, बर्नर की रेटिंग : 1609 केसीएएल/घं (60 1/घं) (2) डबल बर्नर, ढले लोहे की बाडी, रेटिंग 1608/2144 केसीएएल/घ. (40/601/घं.) (3) डबल बर्नर, अढ़र धातु की बाडी, रेटिंग 1608/2144 केसीएएल/घं. (40/60/1/घं) IS : 4246-1978
10	सी एम/एल-1158343 1983-02-27	"	"	कौन पेस्टिसाइड्स प्रा. लि., सी-1/412, जी आई डी सी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, अंकलेश्वर- 393002 (गुजरात)"	मिथाइल पैराथियॉन पायसनीय सान्द्रण 50% IS : 2865-1978
11.	सी एम/एल-1158444 1983-02-07	"	"	सुपर एक्वासेम (इंडिया) प्रा. लि., 14-ए, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015	मिला-मिलाया तैयार पेन्ट, फिनिशिंग अंतरंग सामान्य कार्यों के लिए भारतीय मानक रंगों का — IS 3537-1966
13.	सी एम/एल-1158545 1983-02-07	83-02-06	84-02-15	बालाजी प्रेशर वेसल्स प्रा. लि., 26/ए, श्रीवेंकटेश्वर कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, आईडीए, जीडी मेटला, हैदराबाद-500854	33.3 लिटर पानी की समाई वाले एलपीजी के लिए झलित निम्न कार्बन इस्पात के गैस सिलिंडर- IS : 3196-1974
14.	सी एम/एल-1158646 1983-02-07	83-02-16	84-02-15	जैन ट्यूब कं. लि. मि., 21 किमी मेरठ रोड, गाजियाबाद उ. प्र. (कार्यालय : डी-20, कनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110001	मशीनी एवं सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए इस्पात की नलियां, ग्रेड : ईआरडब्ल्यू 17 IS : 3601-1966
15	सी एम/एल-1158747 1983-02-07			नेशनल स्टील रोलिंग मिल्स, द्वारकापुरी, मुजफ्फरनगर-251001	संरचना इस्पात (मानक किस्म)— IS : 226-1975
16.	सी एम/एल-1158848 1983-02-07			यूनाइटेड वायर रोप्स लिमि., मारुति कुमार रोड, पंच पखाडी, थाणे (महाराष्ट्र)	खानों में लपेटने और मनुष्यों द्वारा खींचने के लिए लड़दार इस्पात के तार के रस्से— IS : 1855-1977
17.	सी एम/एल-1158949 1983-02-07			गाइटन पेपर एंड ट्यूब्स कं. प्रा. लि., ए-164, जीआईडीसी इंडस्ट्रियल इस्टेट, अंकलेश्वर-392002 (गुजरात) (कार्यालय : बुकन इंपीरियल बिल्डिंग, 202/1, वीर नरीमन रोड, चर्चगेट रिक्लेमेशन, बम्बई - 400020)	एलुमिनियम के प्लग रहित नकुओं पर प्रयोग के लिए ऐंठन नलियां (कागज की)— IS : 3625-1971

1	2	3	4	5	6
17.	सीएम/एल - 1159042 1983-02-08	83-02-16	84-02-15	स्पेशल स्टील इंडस्ट्रीज प्रा. लि., एफ-8, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, तारापुर, जि. थाणे-401506 (महाराष्ट्र)	मेटल आर्क वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड कोर तार के लिए मृदु तार, साईज : 5.5 मिमी से 14 मिमी केवल — IS : 2879 - 1975
18.	सीएम/एल - 1159143 1983-02-08	"	"	"	संरचना इस्पात (मानक किस्म) के रूप में वेल्लन के लिए ढले बिलेट इंगट — IS : 6914 - 1978
19.	सीएम/एल - 1159244 983-02-08	"	"	"	संरचना इस्पात (साधारण किस्म) के रूप में वेल्लन के लिए ढले बिलेट इंगट — IS : 6915 - 1978
20.	सीएम/एल - 1159345 1983-02-08	"	"	"	संरचना इस्पात (मानक किस्म) — IS : 226 - 1975
21.	सीएम/एल - 1159446 1983-02-08	"	"	"	संरचना इस्पात (साधारण किस्म) — IS : 1977 - 1975
22.	सीएम/एल - 1159547 1983-02-09	83-02-16	83-02-15	प्रेसिडेंसी रबर मिल्स प्रा. लि., 11, न्यू टांगरा रोड, कलकत्ता - 700046 (प.बं.) (कार्यालय : पी - 36, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता — 700001 (प. बं.)	रबड़ के जल-चूषण और निस्सारण होज, भारी काम, साइज : 150 मिमी अन्तर्वर्ती व्यास — IS : 3549 - 1965
23.	सीएम/एल - 1159648 1983-02-08	"	"	जेम प्रा. लि., 9, सोनापुर रोड, कलकत्ता — 700088 (प. बं.)	मशीनी का तेल, मध्यम ग्रेड - बीजी 22 — IS : 495 (भाग 2) 1981
24.	सीएम/एल - 1159749 1983-02-08	"	"	"	मशीनी तेल, ग्रेड 4, बीजी 100 — IS : 493 (भाग 1) - 1981
25.	सीएम/एल - 1159850 1983-02-08	"	"	वेबीवयाल (सेल्स) प्रा. लि., 50/ए, जी आई डी सी इस्टेट, कलोल - 389330 (महाराष्ट्र)	मिथाइल पराथियोन पायसनीय सान्द्रण 50% — IS : 2865 - 1978
26.	सीएम/एल - 1159951 1983-02-09	"	"	नीरज ट्यूब्स प्रा. लि., 13वां किमी पत्थर, दिल्ली रोड, हिसार (हरियाणा)	मृदु इस्पात की नलियां, काली और जस्तीकृत पेचदार और जोड़दार, साइज : 500 मिमी तक — एलबी श्रेणी : हल्की मध्यम और भारी — IS : 1239 (भाग 1) — 1979
27.	सीएम/एल - 1160027 1982-02-08	83-02-16	84-02-15	जनता वायर वर्क्स (इंडिया), 24-बी, झिलमिल-ताहिरपुर इंडस्ट्रियल इस्टेट, जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032	1100 वोल्ट तक कार्यकारी वोल्टता के लिए पीवीसी रोधित खोलसहित और खोलरहित केबल, एलुमिनियम और तांबे के चालकों वाले, बहरिंग/निम्न तापमान में काम आने वाले ले केबलों को छोड़कर — IS : 694 - 1977
28.	सीएम/एल - 1160128 1983-01-29	"	"	सेन्ट्रल केबल्स प्रा. लि., ए-13, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, हिंगना रोड, नागपुर — 440001 (कार्यालय : 4टेम्पल रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001)	3.3 किवो कार्यकारी वोल्टता के लिये पीवीसी रोधित (भारी काम) बिजली के खोलदार केबल, तांबे के चालकों वाले — IS : 1554 (भाग 2) - 1970
29.	सीएम/एल - 1160229 1983-02-09	83-01-01	83-12-31	जयपुर डेयरी (आर. डी. सी. एफ. की एक यूनिट) गांधी नगर, रेलवे स्टेशन के निकट, जयपुर - 302017	सपरेटा दूध का पाउडर — IS : 1165 - 1975
30.	सीएम/एल - 1160330 1982-02-09	82-02-16	84-02-15	वोल्टरा लिमि., पाटन चेरू-502319, मेडक (जि.) (आ. प्र.) (कार्यालय : 115, पार्क लेन, सिकन्दराबाद - 500003)	मिथायल पराथियोन पायसनीय सान्द्रण 50% — IS : 2865 - 1978

1	2	3	4	5	6
31.	सीएम/एल-11604-31 1983-02-09	82-02-16	84-02-15	माडॅन मैच फैक्टरी, 209/2, विश्वनाथनग्राम, शिवकाशी (त. ना.) (कार्यालय: 136, नार्थ कार स्ट्रीट, इन्द्र बिल्डिंग, शिवकाशी-626123) (त ना.)	दियासलाई की डिबियां, लकड़ी की तीलियां – IS : 2653-1980
32.	सीएम/एल-11605-32 1983-02-09	"	"	प्रवर्तक जूट मिल्स लि., कमरहाटी, कलकत्ता-700058 (प. बं.) (कार्यालय: 5, सिनेगोग स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 (प. बं.)	सीमेंट भरने के लिए जूट के बोरे – IS : 2580-1982
33.	सीएम/एल-11606-33 1983-02-09	"	"	लाइमन मैच फैक्टरी, लिंगपुरम, शिवकाशी, (त. ना.) (कार्यालय: 136, नार्थ कार स्ट्रीट, इन्द्र बिल्डिंग, शिवकाशी-626123 (त. ना.)	दियासलाई की डिबियां, लकड़ी की तीलियां – IS : 2653-1980
34.	सीएम/एल-11607-34 1983-02-09	"	"	रामजी मैच फैक्टरी, सचियापुरम शिवकाशी (त. ना.) (कार्यालय: 136, नार्थ कार स्ट्रीट, इन्द्र बिल्डिंग, शिवकाशी-626123 (त. ना.)	" "
35.	सीएम/एल-11608-35 1983-02-09	83-02-16	84-02-15	कश्यप होम प्राडक्टस, किमी. नं. 127, महू-नीमच रोड, रतलाम-457001 (कार्यालय: धीसाजी मैंशन, एम. जी. रोड, रतलाम-454001 (म. प्र.)	द्रवित पेट्रोलियम गैसों के साथ उपयोग के लिए घरेलू गैस के चूल्हे, दो बर्नर वाले – IS: 4246-1978
36.	सीएम/एल-11609-36 1982-02-11	"	"	भगवती स्टील प्रा. लि., 58/4, गोशाला रोड, लिलुआ, हावड़ा (कार्यालय: 57, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-700016)	संरचना इस्पात (मानक किस्म) IS : 226-1975
37.	सीएम/एल-11610-29 1983-02-11	"	"	रामचन्द्र हीरालाल, 62, कालेज घाट रोड, शालीमार, हावड़ा (कार्यालय: 138, विप्लवी रास-बिहारी बसु रोड, कलकत्ता-700001)	
38.	सीएम/एल-11611-30 1983-02-11	"	"	दुर्गा इंडस्ट्रीज, ग्राम – महतान, जी. टी. रोड, जलन्धर	आरसीसी कंक्रीट पाइप, श्रेणी : एनपी 2 ;– साइज : 450 मिमी IS : 548-1971
39.	सीएम/एल-11612-31 1983-02-11	83-02-16	84-01-25	भगवती स्टील प्रा. लि., 58/4, गोशाला रोड, लिलुआ, हावड़ा कार्यालय: 67, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-700016)	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडे पिटे इस्पात की उच्चशक्ति विकृत सरिया- IS : 1786-1979
40.	सीएम/एल-11613-32 1983-02-11	"	"	हाई-स्पीड गैस एप्लायंसेज प्रा. लि., गेट नं. 907/2, समसवाडी-पूर्णनगर रोड, मालु-भिरूर, जि. पुणे (महाराष्ट्र) (कार्यालय: 4, डा. अम्बेदकर रोड, पुणे-411011 (महाराष्ट्र)	द्रवित पेट्रोलियम गैसों के साथ उपयोग के लिए गैस के चूल्हे, दो बर्नर वाले रेटिंग : 2412 और 1608 के सी ए एशल/घं. (87 और 60 1/घं.), सी आर सी ए चद्दर- IS : 4246-1978
41.	सीएम/एल-11614-33 1983-02-11	"	"	नार्थ लैंड रबर मिल्स, 20/5-6, मील का पत्थर, जी. टी. रोड, राई (सोनीपत) (हरियाणा)	सामान्य कार्यों के लिए वाहक और उत्थापक पट्टा, ग्रेड : एम-24 IS : 1891 (भाग-1)-1978.
42.	सीएम/एल-11615-34 1983-02-11	"	"	सिन्थीकेम लिमि., खापरी, रेलवे स्टेशन के निकट खापरी शहर, जि. नागपुर (महाराष्ट्र), (कार्यालय: नीलागार, रामदासपथ, नागपुर)	ऐंडोसल्फान पायसनीय सान्द्रण- IS : 4223-1980

1	2	3	4	5	6
43.	सी एम/एल-11616-35 1983-02-11	83-02-16	84-02-15	जलगांव रीरोलिंग इंडस्ट्रीज लि., 18-27, इंडस्ट्रियल इस्टेट, अजन्ता रोड, जलगांव-825001,	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडे पिटे इस्पात की उच्च शक्ति की विकृत सरिया- IS : 1786-1979
44.	सी एम/एल-11617-36 1983-02-11	83-03-01	84-02-29	शांता स्टील्स प्रा. लि., 84/1, पी. एन. मालवया रोड, रानीगंज, (कार्यालय : गोयन्का हाउस, पा. बी. नं. 19, रानीगंज-713347)	संरचना इस्पात (मानक किस्म) IS : 226-1975
45.	सी एम/एल-11618-37 1983-02-11	,,	,,	काश्मीर स्टील रोलिंग मिल, इंडस्ट्रियल काम्प्लैक्स, बारी ब्राह्मण जम्मू-तावी (जम्मू कश्मीर)	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडे पिटे इस्पात की उच्च शक्ति विकृत सरिया- IS : 1786-1979
46.	सी एम/एल-11618-38 1983-02-11	,,	,,	डिनैमिक कारपोरेशन, जी एस एफ टी के सामने, राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8, आई ओ सी पम्प के निकट, बड़ौदा (कार्यालय : इन्द्र निवास, दांडिया बाजार प्रताप रोड, बड़ौदा)	आग बुझाने के लिए शुष्क रासायनिक पाउडर- IS : 4308-1967
47.	सी एम/एल-11620-31 1983-02-11	83-03-01	84-02-29	रमा रोलिंग मिल्स, 156, मानिक टोला मेन रोड, कलकत्ता-700054.	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडे पिटे इस्पात की उच्च शक्ति की विकृत सरिया- IS : 1786-1979
48.	सी एम/एल-11621-32 9183-02-11	83-03-01	84-02-29	,, ,,	संरचना इस्पात (मानक किस्म)- IS : 226-1975
49.	सी एम/एल-11622-33 1983-02-11	,,	,,	जेनिथ स्टील इंडस्ट्रीज लि., खोपाली-410203 जि. रायगढ़ (महाराष्ट्र)	लाइन पाइप ग्रेड : वाई एस टी-18 और वाई एस टी 21- IS : 1978-1971
50.	सी एम/एल-11623-34 1983-02-11	,,	,,	मैकाटैथर एग्रो केमिकल्स एंड मिनरल्स प्रा. लि. प्लाट नं. 3-बी (एन पी) इंडस्ट्रियल इस्टेट अम्बत्तुर, मद्रास-600098.	फेन्थाट पायसनीय सान्द्रण 50 प्रतिशत IS : 8291-1976
51.	सी एम/एल-11624-35 1983-02-11	,,	,,	सुमनचन्द मुरारीलाल प्रा. लि., ए-7, इंडस्ट्रियल इस्टेट, परतापुर, मेरठ (उ. प्र.)	सीमेन्ट पेन्ट, अभीष्ट रंग का- IS : 5410-1969
52.	सी एम/एल-11625-36 1983-02-11	83-03-01	84-02-29	न्यू लाइट इंडस्ट्रीज, 59, अजय एन्क्लेव मार्किट, नई दिल्ली.	सरकवां किवाड़ों के लिए धातु की चटखनियां (आलड्राप), टाइप: 3 IS : 2681-1978
53.	सी एम/एल-11626-37 1983-02-11	,,	,,	नेशनल रोलिंग एंड स्टील रोप्स लि., ईस्ट घोषपाड़ा रोड, अथपुर, श्यामनगर, 24 परगना (प. बं.), (कार्यालय : निक्को हाउस, 1 और 2 हरे स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 (प. बं.)	तार एवं टेलीफोन के प्रयोजन के लिए जस्तीकृत इस्पात का तार- IS : 279-1981
54.	सी एम/एल-11627-38 1983-02-11	,,	,,		एलुमिनियम चालकों के लिए इस्पात कोर वाला तार, जस्तीकृत इस्पात प्रबलित- IS : 398 (भाग-2)-1976
55.	सी एम/एल-11628-39 1983-02-14	,,	,,	ला-गज्जर इंजीनियरिंग प्रा. लि., गुगोभी प्रा. लि., महाता, नरोडा रोड-अहमदाबाद-380025 (गुजरात)	द्रवित पेट्रोलियम गैसों के साथ उपयोग के लिए घरेलू गैस के चूल्हे पार्श्व छिद्रयुक्त, दो बर्नर वाले रेटिंग : 1068 के सी ए एल/घं. (प्रत्येक) IS : 4246-1978

1	2	3	4	5	6
56.	सी एम/एल-11629-40 1983-02-15	83-03-01	84-02-29	श्री कृष्ण कंपनी, 52 जे. एन. मुखर्जी रोड, हावड़ा-6, (प. बं.) (कार्यालय : 15, ब्रेबोर्न रोड, कलकत्ता-700001 (प. बं.)	उर्वरक भरने के लिए परतदार जूट के बोरे-407 जी/एम 2, 85×39 तिरपाल के कपड़े से बने— IS : 7406 (भाग-1)-1974
57.	सी एम/एल-11630-33 1983-02-15	,,	,,	,, ,,	उर्वरक भरने के लिए परतदार जूट के बोरे 380 जी/एम2, 68×39 तिरपाल के कपड़े से बने— IS : 7406 (भाग-2)-1980
58.	सी एम/एल-11631-34 1983-02-15	83-02-16	84-02-15	भारत इम्पैक्स प्रा. लि., ए-1/2202, थर्ड फेज, जी आई डी सी, वापी-396195 जि. वलसाड	पेय जल-पूर्ति के लिए अनम्यीकृत पी वी सी पाइप— IS: 4985-1981
59.	सी एम/एल-11632-35 1983-02-15	83-03-01	84-02-29	एक्रोलैक पेन्ट्स, 70, नजफगढ़ रोड, नयी दिल्ली-110015	सामान्य कार्यों के लिए मिला-मिलाया तैयार पेन्ट, ब्रुश द्वारा लगाया जाने वाले अग्नि और क्षार प्रतिरोधी [illegible] IS : 157-1950
60.	सी एम/एल-11633-36 1983-02-15	83-03-01	84-02-29	वूनिया होजियरीज, 15, कालेज रोड, तिरुपुर-638602 (त. ना.)	सादा बुनी सूती बनियानें, टाइप: आर एन. और आर एन एस, साइज : 75 से 90 सेमी. तक, गेज : 24— IS: 4964-1980
61.	सी एम/एल-11634-37 1983-02-15	83-03-01	84-02-29	एग्रो मैटल एंड ईक्विपमेंट कारपो., दिल्ली रोड, गोहाना रेलवे क्रासिंग, रोहतक (हरियाणा)	पैरा फुहारा— IS : 3652-1974
62.	सी एम/एल-11636-38 1983-02-15	,,	,,	नागपुर मोटर्स प्रा. लि., डी-76, एम. आई. डी. सी., नागपुर-440028	तीन-फेजी प्रेरण मोटर, श्रेणी "बी" रोधन, 2.2 किवा तक— IS : 325-1978
63.	सी एम/एल-11636-39 1983-02-15	,,	,,	जे. बी. फार्मेस्युटिकल्स, 10, गोपाल नगर मजीठा रोड, अमृतसर	कारमेल सादा— IS : 325-1978
64.	सी एम/एल-11637-40 1983-02-15	,,	,,	एकोमिक्स केमिकल्स ऐंड कोटिंग्स प्रा. लि., 327, ग्राम जोनपुर, महरौली, नई दिल्ली-110030.	सड़क पर निशान लगाने के लिए मिला-मिलाया तैयार पेन्ट ग्रेड 2— IS : 164-1981
65.	सी एम/एल—11639-41 1983-02-15	83-03-01	84-02-29	इंडो बैल इंस्युलेशन्स प्रा० लि०, 1, ट्रांसपोर्ट डिपो रोड, कलकत्ता-700038(प०बं०)	ताप रोधन के लिये बिना मुड़ी गैल और खनिज रूई, टाइप-2— IS : 3677—1973
66.	सी एम/एल—11629-42 1983-02-15	83-03-01	84-02-29	मूनलाइट पेन्ट्स इंडस्ट्रीज, 11, ईस्ट मोहन नगर, सुल्तान सिंह गेट के बाहर, अमृतसर (पंजाब)	ब्रुश द्वारा सड़क पर निशान बनाने के लिये मिला-मिलाया तैयार पेन्ट— IS : 164—1951
67.	सी एम/एल—11640-35 1983-02-15	,,	,,	सन्तोष ईक्विपमेंट कं०, 10, रैड हिल्स रोड, कोलातुर, मद्रास-600099(त०ना०)	द्रवित पैट्रोलियम गैसों के साथ उपयोग के लिये घरेलू गैस के चूल्हे, दो बर्नर वाले: रेटिंग 60/घं० (प्रत्येक)— IS : 4246—1978
68.	सी एम/एल—11641-36 1983-02-16	83-02-16	84-02-15	यूनिवर्सल केबल्स लि०, डा० बिरला विकास, सतना (म०प्र०)-485001	खनिकों के टोपी-दीप के लिये नम्य केबल— IS : 2593—1964
69.	सी एम/एल—11642-37 1983-02-15	83-03-01	84-02-29	इन्का केबल्स प्रा०लि०, 149, ताम्बरम, वेलाचेरी रोड, सेम्बक्कम, मद्रास-600073	1100 वोल्ट तक कार्यकारी वोल्टता के लिये पीवीसी रोधित (भार काम) बिजली के केबल, खोलरहित, एलुमिनियम चालकों वाले— IS : 1554(भाग 1)—1976

1	2	3	4	5	6
70.	सी एम/एल-11643 38 1983-02-15	83-03-01	84-02-29	वेलवर्थ इंस्युलेटिड केबल्स कं०, 22, इंडस्ट्रियल एरिया, यैयार्दी, मंगलौर-575008	1100 वोल्ट तक के कार्यकारी वोल्टता के लिये पीवीसी रोधित (भारी काम) बिजली के केबल, खालरहित एलुमिनियम चालकों वाले— IS : 1554(भाग 1)—1976
71.	सी एम/एल-11644 39 1983-02-16	83-02-16	84-02-15	हिन्द टिन इंडस्ट्रीज, पी-355, केयातला रोड, कलकत्ता-700029	18 लिटर के वर्गाकार टिन— IS : 916—1975
72.	सी एम/एल-11645 40 1983-02-18	83-03-01	84-02-29	मुथा इंडस्ट्रियल कारपो, 15, इंडस्ट्रियल इस्टेट, रायपुर (म०प्र०)	शिरोपरि प्रेषण कार्यों के लिये एलुमिनियम लड़दार चालक— IS : 398(भाग 1)—1976
73.	सी एम/एल-11646 41 1983-02-18	,,	,,	वैस्टर्न इलैक्ट्रानिक्स, ए-46, शास्त्री नगर, जोधपुर, (कार्यालय : 575, दसवीं-सी रोड, सरदार-पुरा, जोधपुर	खंड स 8.4.2.1 और खंड 9.3.2 के अनुसार धनाकार सांचे, साइज : 50 मिमी और 70.6 मिमी— IS : 4031—1968
74.	सी एम/एल-11647 42 1983-02-18	83-02-16	84-02-15	सुप्रीत इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, ए-21/24, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 नई दिल्ली-28	प्रणोदक प्रकार के ए सी संभासी पंखे एक-फेजी, श्रेणी ई रोधनवाले, साइज : 300 मिमी, 450 मिमी और 600 मिमी— IS : 2312—1967
75.	सी एम/एल-11648 43 1983-03-17	83-03-01	84-02-29	अवतार सिंह एंड कं०, देहरादून रोड, सहारन-पुर-247001	कंक्रीट के पाइप, श्रेणी : एन पी 2 और एन पी 3 साइज : 1200 मिमी तक केबल— IS : 458—1971
76.	सी एम/एल-11649 44 1983-02-15	83-03-01	84-02-29	जयाहिन्द टिन फैक्टरी, कलासपुर, जि० सहारनपुर (उ०प्र०)	18—लिटर के वर्गाकार टिन— IS : 916—1975
77.	सी एम/एल-11650 37 1983-02-20	,,	,,	जानसन पेढहार प्रा०लि०, इंडस्ट्रियल एरिया नं० 2, एबी, रोड, देवास (कार्यलय : 11/बी, रतलाम कोठी, इन्दौर-542001)	शौचालयों और मूत्रालयों के लिये फ्लश की टंकियां (बाल्वरहित, साइफन प्रकार की) काचीय चीनी मिट्टी की निम्न रतर पर लगने वाली, 10 और 12.50 लिटर पानी की क्षमता वाली— IS : 774—1971
78.	सी एम/एल-11651 38 1983-02-17	,,	,,	वैस्टर्न इलैक्ट्रोनिक्स, ए-46, शास्त्रीनगर, जोधपुर, (कार्यालय : 575, दसवीं—"सी" रोड, सरदार पुरा, जोधपुर)	धनाकार सांचे (15×15×15), खंड 2.9.1— IS : 516—1959
79.	सी एम/एल-11652 39 1983-02-17	83-03-01	84-02-29	फायरकूल प्रा०लि०, बी-16, सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट, होसुर-635126 (कार्यालय : 188, यमुचेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001)	आग बुझाने के लिये शुष्क पाउडर फोम संगतता को छोड़कर IS : 4308—1967
80.	सी एम/एल-11653 40 1983-02-17	,,	,,	आर० प्लाईवुड प्रोडक्ट्स, 7/1, गुरुदार दत्त गार्डन लेन, कलकत्ता 700067	चाय की पेटियों के लिये प्लाईवुड के तख्ते— IS : 10(भाग 2)—1976
81.	सी एम/एल-11654 41 1983-02-21	,,	,,	एक्रोमिक्स कैमिकल्स एंड कास्टिंग्स प्रा०लि०, 327, ग्राम जोनपुर, महरौली, नयी दिल्ली-30	सीमेंट के पेन्ट, क्लोरीन रंग के— IS : 5410—1969
82.	सी एम/एल-11655 42 1983-02-21	,,	,,	मेडीकेयर इक्विपमेंट कम्पनी, प्लाट नं० 333, जी०आई०डी०सी० इस्टेट माकरपुरा, बड़ौदा-390010 (गुजरात)	क्षैतिज वेलनाकार तीव्र गति भाप जीवाणुनाशक यन्त्र, बाक्स टाइप— IS : 4510—1978
83.	सी एम/एल-11656 43 1983-02-21	83-03-01	84-02-29	इंडस्ट्रियल फेल्ट कारपोरेशन, बीब/1/2, (फेज-6) आदितयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, डा० गमरिया जमशेदपुर-832108 (कार्यालय : रुस्तमजी मैन्शन, प्रथम तल, बिस्पुपुर (डा०) जमशेदपुर-832001)	ताप रोधन के लिये बिना मुड़ी, शैल एवं खनिज ऊन, टाइप 1— IS : 3677—1973

1	2	3	4	5	6
84.	सी एम/एल–11657 44 1983-02-21	83-03-01	84-02-29	गोल्डन पेन्ट्स एंड कैमिकल्स, चातीविंड गेट के बाहर, कोट मोहना सिंह, अमृतसर-143001 (पंजाब) (कार्यालय : 43, अकाली मार्केट, अमृतसर (पंजाब)	सीमेंट के पेन्ट, अभीष्ट रंगों के— IS : 5410—1969
85.	सी एम/एल–11658 45 1983-02-21	,,	,,	बजाज पेन्ट्स इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इस्टेट, काणीपुर-244713 जि० नैनीताल (उ०प्र०)	एनेमल, अन्तरंग, फिनिशिंग— IS : 133—1975
86.	सी एम/एल–11659 46 1983-02-21	,,	,,	कुशल मेटल एंड पेन्ट इंडस्ट्रीज, ए-78, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 2 नई दिल्ली-110020	सीमेंट के पेन्ट, अभीष्ट रंगों के— IS : 5410—1969
87.	सी एम/एल–11660 39 1983-02-21	83-03-01	84-02-29	आरिल कैमिकल्स, डब्ल्यू-27(ई), एम आई डी सी इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स, टी टी सी इंडस्ट्रियल एरिया, रबले-थाणे-बेलापुर रोड, थाणे-400701 (महाराष्ट्र)	1—फिनायल-3-मिथायल-5-पाइरेजोलोन— IS : 8553—1977
88.	सी एम/एल–11661 40 1983-02-21	83-03-01	84-02-29	मोना मोटिव इंजीनियर्स प्रा०लि०, 86/2, जी आई डी सी इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेज-1, वटवा, अहमदाबाद-382445 (गुजरात)	कृषि कार्यों के लिये साफ, ठंडे, ताजा पानी के वास्ते मोनोसेट पम्प, निम्नांकित साइजों के : साइज : 65×65 मिमी टाइप/माडल : ड्यूटी प्वाइंट : 22.5 एम पर, हैड डिस्चार्ज 10.5 एल पी एस और कुल दक्षता 54%, मोटर : 3.7 किवा श्रेणी ई रोधन— IS : 9079—1979
89.	सी एम/एल–11662 41 1983-02-21	,,	,,	भांगर एक्टरप्राइसेज, 211, जी आई डी सी इंडस्ट्रियल इस्टेट, अम्बरगांव, जि.-वलसर (गुजरात) (कार्यालय : 111, एटलान्टा, नरीमेन प्वाइंट, बंबई-400023)	कृषि कार्यों के लिये साफ, ठंडे ताजे पानी के वास्ते मोनोसेट पम्प, निम्नांकित साइजों के : साइज : 65×50 मिमी, टाइप : एच 32 इंच ड्यूटी प्वाइंट : 22.5 एम पर हैड डिस्चार्ज : 6.5:1/सि० और कुल दक्षता 49% मोटर अन्तर्गामी : 2.2 किवा, श्रेणी ई रोधन— IS : 9079—1979
90.	सी एम/एल–11663 42 1983-02-22	83-03-01	84-02-29	शिवालिक एग्रो कैमिकल्स, बी-59, इंडस्ट्रियल फोकल प्वाइंट, सासनगर, मोहाली, जि रोपड़	कार्बेरिल जलविसर्जनीय पाउडर 50% भूमि फुहार ग्रेड— IS : 7121—1973
91.	सी एम/एल–11664 43 1983-02-22	,,	,,	,, ,,	मलाथियान 25% जलविसर्जनीय पाउडर— IS : 2569—1978
92.	सी एम/एल–11665 44 1983-02-24	,,	,,	डिम्पैक्स रबर्स, 44.6 मिमी पत्थर जी टी रोड, ग्राम कोट, डा. दावरी-203207, जि. गाजियाबाद (कार्यालय : 107, सहयोग, 58 नेहरू प्लेस, नयी दिल्ली-110019)	सामान्य कामों के लिये वाहक और उत्थापक पट्टा ; ग्रेड : "एन-17 और एम-24"— IS : 1891 (भाग 1)—1978
93.	सी एम/एल–11666 45 1983-02-24	,,	,,	अग्रवाल मल्टी कास्टिंग, गोनियाना रोड, भटिंडा (पंजाब)	ढलवां लोहे के भित्ति नल, साइज : 100 मिमी— IS : 1729—1979
94.	सी एम/एल–11667 46 1983-02-24	83-03-01	84-02-29	हरचरन एंड ब्रादर्स, प्रीतनगर, इंडस्ट्रियल एरिया, जलन्धर सिटी	साइज अभिधान 2 तक की कुहनियां— IS : 1879 (भाग 2)—1975
95.	सी एम/एल–11668 47 1983-02-24	83-03-01	84-02-29	एवराइट सेल्स कारपो., 4, इंडस्ट्रियल एरिया, तिलकनगर, नयी दिल्ली-110016	भारी किवाड़ों के लिये लचकदार फर्श (द्रव नियन्त्रित)— IS : 6315—1971

1	2	3	4	5	6
96	सी एम/एल–11669 48 1983-02-24	83–03–01	84–02–29	क्वालिटी मेटल इंडस्ट्रीज, 614, शुक्रवारपेट, कोयम्बतूर-641001	चाय की प्लाईवुड की पेटियों के लिये धातु की फिटिंगें— IS : 10(भाग 4)—1976
97.	सी एम/एल–11670 41 1983-02-24	„	„	ग्रीन इंजीनियरिंग कारपोरेशन, एम-255, इंडस्ट्रियल एरिया, जलन्धर सिटी	साइज अभिधान 2 तक की कुहनियां— IS : 1879(भाग 2)—1975
98.	सी एम/एल–11671 42 1983-02-24	„	„	यूनाइटेड मेटल वर्क्स, 30 ए, इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कालोनी, बाई-पास, जलन्धर-144004	„ „
99.	सी एम/एल–11672 43 1983-02-25	83-03-01	84-02-29	कानोडिया कैमिकल एंड इंडस्ट्रीज लि., सुडलो जूट मिल्स डिवीजन, चेंगेल (दक्षिण-पूर्वी रेलवे), जि. हावड़ा (प०बं०) (कार्यालय : 16 ए, ब्रैबोर्न रोड, कलकत्ता-700001)	बी-ट्विल जूट के बोरे— IS : 2566—1965
100.	सी एम/एल–11637 44 1983-02-25	„	„	डाबर रीरोलिंग मिल, जवाहर लाल नगर मैंगो, जमशेदपुर-831012 (कार्यालय : कशाना-ए-शबीना, गोलमूरी मसजिद के पास, डा० गोलमूरी, जमशेदपुर)	कंक्रीट प्रबलन के लिये ठंडे पिटे इस्पात की उच्च शक्ति विकृत सरिया— IS : 1786—1979
101.	सी एम/एल–11674 45 1983-02-25	„	„	„ „	संरचना इस्पात (साधारण किस्म) — IS : 1977—1975
102.	सी एम/एल–11675 46 1983-02-25	„	„	„ „	संरचना इस्पात (मानक किस्म) — IS : 226—1975
103.	सी एम/एल–11676 47 1983-02-28	83-03-01	84-02-29	लेमको, 119, पंजानी इंडस्ट्रियल इस्टेट, खोपट, थाणे-406601 (कार्यालय : 127, मधानी इस्टेट, सेनापति बापट मार्ग, दादर, बंबई-400028(महाराष्ट्र)	द्रव घनत्वमापी— एल-50 और एम-50 शृंखला— IS : 3104(भाग 1)—1982

[सी एम डी/13 : 11]

बी एन सिंह, अपर महानिदेशक

S.O. No. 1892 :—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks Regulations, 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that one hundred and three licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been granted during the month of February 1983 authorizing the licensees to use the Standard Marks :

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No.	Period of Validity From	To	Name & address of the Licensee	Article/Process covered by the Licences and the Relevant IS : Designation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	CM/L-11574 42 1983-02-07	83-02-01	84-01-31	Verny Containers Ltd., Plot No. 14, Phase III, Jeedimetla, Rangareddy District, Andhra Pradesh-500854	Welded low carbon steel gas cylinders for LPG 33.3 Litres water capacity— IS : 3196—1974
2.	CM/L-11575 43 1983-02-07	83-02-16	84-02-15	Bat Bro Engg. & General Manufacturers, 7, Badli Indl. Estate, Badli, Delhi-110042 (Off : 1/25, Asaf Ali Road, New Delhi-110002).	Cables for motor vehicles, PVC insulated light duty without further covering IS : 2465—1969
3,	CM/L-11576 44 1983-02-07	82-12-01	83-11-30	Universal Cables Ltd., P.O. Birla Vikas Satna (M.P.)-485001.	PVC insulated (heavy duty) armoured & unarmoured electric cables : (a) with copper conductors for working voltages 3.3 & 6.6 kv ; (b) with aluminium conductors for working voltages from 3.3 kv up to and including 11 kv— IS : 1554 (Pt II)—1970.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	CM/L-11577 45 1983-02-07	83-02-16	84-02-15	Super Aquacem (India) Pvt. Ltd., 14-A, Najafgarh Road, New Delhi-110015	Distemper. dry, colour as required— IS : 427-1965.
5.	CM/L-11578 46 1983-02-07	83-02-16	84-02-15	M.B.S.F. (Paint Division) A-5/3, Jhilmil Indl. Area, Shahdara, Delhi-110032.	Ready mixed paint, finishing interior, for general purposes to Indian Standard colours— IS : 3537—1966
6.	CM/L-11579 47 1983-02-07	83-02-16	84-02-15	Karly Paint Industries, Plot No. 28, Road No. 3, Kaltodan Indl. Estate, Hyderabad-500252	Enamel, synthetic exterior, (a) undercasting; and (b) finishing, colour category No. 27— IS : 2932—1974
7.	CM/L-11580 40 1983-02-87	83-02-16	84-02-15	Charag Chemical Inds., K-14, Industrial Estate, Embattur, Madras 600058 (T.N.)	Copper sulphate, technical grade— IS : 261—1961
8.	CM/L-11581 41 1983-02-07	84-02-16	84-02-15	Santhosam Match Industries, 1219/2, 5th Street, Pandian Nagar, Thiruthangal Sivakasi (Via) (T.N.). (Off : 12-A, Chairman Shanmuga Nadar Road, Sivakasi-626123(T.N.).	Safety matches in boxes, wooden sticks IS : 2653—1980
9.	CM/L-11582 42 1985-02-07	83-02-16	84-02-15	Swastik Press Metal Industries, Mangaldas Compound, Nr. Rly. Crossing, Chandlodia, Ahmedabad (Gujarat).	Domestic gas stoves for use with liquified petroleum gases (i) single burner cast iron body burner rating 1608 Kcal/h (60 1/h) (ii) Double burner, cast iron body 1608/2144 kcal/h (40/60 1/h) (iii) Double burner, sheet metal body 1608/2144 kcal/h (40/60 1/h)— IS : 4246—1978
10.	CM/L-11583 43 1983-02-07	83-02-16	84-02-15	Keen Pesticides Pvt. Ltd., C-1/412, GIDC Indl. Estate, Ankleshwar-393002 (Gujarat).	Methyl Parathion EC 50% IS : 2865—1978
11.	CM/L-11584 44 1983-02-07	83-02-16	84-02-15	Super Aquacem (India) Pvt. Ltd., 14-A, Najafgarh Road, New Delhi 110015	Ready mixed paint, finishing, interior, for general purposes to Indian Standard colour— IS: 3537—1966
12.	CM/L-11585 45 1983-02-07	83-02-01	84-01-31	Balaji Prossure Vessels Pvt. Ltd., 26/1, Sri Venkateswara Co-operative Industrial Estate, IDA, Jeedimetla, Hyderabad-500854	Welded low carbon steel gas cylinder for LPG of 33.3 litres water capacity— IS : 3196—1974
13.	CM/L-11586 46 1983-02-07	83-02-16	84-02-15	Jain Tube Co. Ltd., 21 K.M., Meerut Road, Ghaziabad (U.P.) (Off : D-20, Cannaught Place, New Delhi-110001).	Steel tubes for mechanical & general engineering purposes : Grade : ERW 17 and 21 Sizes All— IS : 3601—1966
14.	CM/L-11587 47 1983-02-07	83-02-16	84-02-15	National Steel Rolling Mills, Dwarkapuri, Muzaffarnagar-251001	Structural steel (standard quality)— IS : 226—1975
15.	CM/L-11588 48 1983-02-07	83-02-16	84-02-15	United Wire Ropes Ltd., Maruti Kumar Road, Panchpakhadi, Thana (Maharashtra).	Standard steel wire ropes for winding & man riding haulages in mines— IS : 1855—1977
16.	CM/L-11589 49 1983-02-07	83-02-16	84-02-15	Titan Paper & Tubes Co. Pvt. Ltd., A-a/164,G.I.D.C. Industrial Estate, Ankleshwar-392002 (Gujarat) (Off : Vukan Insurance Bldg., 202/1, Veer Nariman Road, Churchgate Reclamation, Bombay-400020).	Warp tubes (paper) for use on aluminium plug type spindles— IS : 3625—1971

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	CM/L-11590 42 1983-02-08	83-02-16	84-02-15	Special Steel Inds. Pvt. Ltd., F-8, MIDC Indl. Area, Tarapur, Dist. Thana-405106 (Maharashtra).	Mild steel for metal arc welding electrode core wire. Size : 5.5 mm to 14 mm only— IS :2879—1975
18.	CM/L-11591 43 1983-02-08	83-02-16	84-02-15	—do—	Cast billet ingots for rolling into structural steel (standard quality)— IS : 6914—1978
19.	CM/L-11592 44 1983-02-08	83-02-16	84-02-15	—do—	Cast billet ingots for rolling into stuructural steel (ordinary quality)— IS : 6915—1978
20.	CM/L-11593 45 1983-02-08	83-02-16	84-02-15	—do—	Structural steel (standard quality)— IS :226—1975
21.	CM/L-11594 46 1983-02-08	83-02-16	84-02-15	—do—	Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1975
22.	CM/L-11595 47 1983-02-09	83-02-16	84-02-15	Presidency Rubber Mills (P) Ltd., 11, New Tangra Road, Calcutta-700046 (W.B.) (Off : P-36, India Exchange Place. Calcutta-700001 (W.B.)]	Water suction and discharge Hose of rubber, heavy duty, size : 150 mm internal dia— IS : 3549—1965
23.	CM/L-11596 48 1985-02-08	83-02-16	84-02-15	Jem Pvt. Ltd., 9, Sonapur Road, Calcutta-700088 (West Bengal).	Spindle oil, medium grade-VG 22— IS : 493 (Pt II)—1981.
24.	CM/L-11597 49 1983-02-08	83-02-16	84-02-16	—do—	Machinery oil, Grade IV, VG 100— IS : 493 (Pt I)—1981
25.	CM/L-11598 50 1983-02-08	83-02-16	84-02-15	Reidayal (Sales) Pvt. Ltd., 50/A, GIDC Estate, Kalol-389330 (Maharashtra).	Methyl paradhion EC 50%— IS :2865—1978.
26.	CM/L-11599 51 1983-02-09	83-02-16	84-02-15	Niraj Tubes (Pvt.) Ltd., 13th K.M. Stone, Delhi Road, Hisar (Haryana).	Mild steel tubes, black and galvanised, screwed and pocketed Size : upto and including 50 mm NB Class : LIGHT, MEDIUM AND HEAVY— IS : 1239(Pt I)—1979
27.	CM/L-11600 27 1983-02-08	83-02-16	84-02-15	Janta Wire Works (India), 24-B, Jhilmil Tahirpur Industrial Estate, G.T. Road, Shahdara, Delhi-110032	PVC insulated sheathed & unsheathed cables with aluminium and copper conductors for working voltages upto and including 1100 V, excluding cables for use under outdoor/low temperature condition— IS : 692—1977
28.	CM/L-11601 28 1983-01-29	83-02-16	84-02-15	Central Cables Pvt. Ltd., A-13, M. I. D. C. Indl. Area, Hingana Road, Nagpur-440001, (Off : 5, Temple Road, Civil Lines, Nagpur-440 001)	PVC insulated (heavy duty) electric cables armoured with copper conductors for 3.3 kv working voltages IS : 1554 (Part II)—1970
29.	CM/L-11602 29 1983-02-09	83-01-01	83-12-31	Jaipur Dairy, (A Unit of R.C.D.F.) Near Gandhi Nagar, Railway Station, Jaipur-302017.	Skim milk powder— IS : 1165—1975
30.	CM/L-11603 30 1983-02-09	83-02-16	84-02-15	Volhro Limited, Patancheru-502319 Medak Distt. (A.P.) (Off : 115, Park Lane, Secunderabad-500003).	Methyl parathion EC 50%— IS :2865—1978
31.	CM/L-11604 31 1983-02-09	83-02-16	84-02-15	Modern Match Factory, 209/2, Viswanathan Village, Sivakasi (TN) (Off : 136, North Car Street, Indra Building, Sivakasi-626123 (TN)]	Safety matches in boxes, wooden sticks IS :2653—1980
32.	CM/L-11605 32 1983-02-09	83-02-16	84-02-15	Prabartak Jute Mills Ltd., Kamarhati, Calcutta-700058 (W.B.) [Off : 5, Synagague Street, Calcutta-700001 (W.B.)]	Jute sacking bags for packing cement— IS :2580—1982

1	2	3	4	5	6
33.	CM/L-11606 33 1983-02-09	83-02-16	84-02-15	Lion Match Factory, Lingapuram Sivakasi (T.N.) [Off : 136 North Car Street, Indra Building, Sivakasi-626123 (TN)].	Safety matches in boxes, wooden sticks— IS :2653—1980
34.	CM/L-11607 34 1983-02-09	83-02-16	84-02-15	Ramji Match Factory, Sachipuram, Sivakasi (TN) [Off : 136, North Dar Street, Indira Building, Sivakasi-626123(TN)]	Safety matches in boxes, wooden sticks IS :2653—1980
35.	CM/L-11608 35 1983-02-09	83-02-16	84-02-15	Kashyap Homo Products, Km. No. 126, Mhow, Neemuch Road, Ratlam-457001. [Off : Visaji Mansion, M.G. Road, Ratlam-454001 (UP)].	Domestic gas stoves for use with liquefied petroleum gases with double burners rating— IS : 4246—1978
36.	CM/L-11609 36 1983-02-11	83-02-16	84-02-15	Bhagwati Steel Pvt. Ltd., 58/4, Goushala Road, Lilluah, Howrah [Off : 57, Park Street, Calcutta-700016].	Structural steel (standard quality) IS :226—1975
37.	CM/L-11610 29 1983-02-11	83-02-16	84-02-15	Ram hander Heeralall, 62, College Ghat Road, Shalimar, Howrah (Off : 138, Biplabi Rash Behari Basu Road, Calcutta-700001).	—do—
38.	CM/L-11611 30 1983,02-11	83-02-16	84-02-15	Doaba Industries, Village-Mehtan G.T. Road, Jullundur.	RCC Concrete pipes Class NP2 Size 450 mm— IS : 458—1971
39.	CM/L-11612 31 1983-02-11	83-02-16	84-02-15	Bhagwati Steel Pvt. Ltd., 58/4, Goushala Road, Lilluah, Howrah (Off : 67, Park Street, Calcutta-700016).	Cold worked steel high strength deformed bars for concrete reinforcement IS : 1786—1979
40.	CM/L-11613 32 1983-02-11	83-02-16	84-02-15	Hi-speed Gas Appliances Pvt. Ltd., Gate No. 907/2, Sanaswadi Pune nagar Road, Tal Shirur, Distt. Pune (Maharashtra) (Off : 4, Dr. Ambedkar Road, Pune-411011 (Maharashtra).	Domestic gas stove for use with liquefied petroleum gases with double burner, ratings 2412 & Kcal/h (87 & 60 1/h) CRCA sheet— IS : 4246—1978.
41.	CM/L-11614 33 1983-02-11	83-02-16	84-02-15	Northland Rubber Mills, 20/5-6, Mile stone, G.T. Road, Rai (Sonepat) (Haryana).	Rubber conveyor & elevator belting for general purposes, Grade M-24— IS : 1891 (Pt I)—1978.
42.	CM/L-11615 34 1983-02-11	83-02-16	84-02-15	Sindichem Ltd., Khapri, Near Railway Station, Town-Khapri, Distt. Nagpur (Maharashtra) (Off : Nilgiri, Ramdaspath, Nagpur).	Endesulfan SC IS : 4323—1980
43.	CM/L-11616 35 1983-02-11	83-02-16	84-02-15	Jalgaon Re-rolling Industries Ltd. 18-27, Indl. Estate, Ajintha Road, Jalgaon-425001	Cold worked steel high strength deformed bars for concrete reinforcement IS : 1786—1979
44.	CM/L-11617 36 1983-02-11	83-03-01	84-02-29	Shashi Steels (P) Ltd., 84/1, P.N. Malia Road, Raniganj (Off : Goenka House, P.B. No. 19, Raniganj-713347).	Structural steel (standard quality) IS :226—1975
45.	CM/L-11618 37 1983-02-11	83-03-01	84-02-29	Kashmir Steel Rolling Mill, Indl. Complex, Bari Brahmana, Jammu Tawi, (J & K State)	Cold worked steel High strength deformed bars for concrete reinforcement IS : 1786—1979
46.	CM/L-11619 38 1983-02-11	83-03-01	84-02-29	Dynamic Corporation, Opp. CSET, National Highway No. 8, Nr. I.O.C. Dump, Baroda. (Off : Indra Niwas, Dandia Bazar, Pratap Road, Baroda).	Dry chemical powder for fire fighting IS : 4308—1967

1	2	3	4	5	6
47.	CM/L-11620 31 1983-02-11	83-03-01	84-02-29	Rama Rolling Mills, 156, Muniktolla Main Road, Calcutta-700054.	Cold worked steel high strength deformed bars for concrete reinforcement— IS : 1786—1979
48.	CM/L-11621 32 1983-02-11	83-03-01	84-02-29	—do—	Structural steel (standard quality) IS : 226—1975
49.	CM/L-11622 33 1983-02-11	83-03-01	84-02-29	Zenith Steel Pipes Industries Ltd., Khopali-410203, Distt. Raigadh (Maharashtra).	Line pipes Grade : Yst18 and Yst21- IS : 1978—1971
50.	CM/L-11623 34 1983-02-11	83-03-01	84-02-29	Venkateswara Agro Chemicals & Minerals (P) Ltd., Plot No. 3-B (NP) Industrial Estate, Ambattur, Madras-600098.	Phenthoate EC 50%— IS : 291—1976
51.	CM/L-11624 35 1983-02-11	83-03-01	84-02-29	Sugan Chand Murari Lal (P) Ltd., A-7, Industrial Estate, Partapur, Meerut (U.P.).	Cement paint, colour asrequired— IS : 5410—1969.
52.	CM/L-11625 36 1983-02-11	83-03-01	84-02-29	Nu-Lite Industries, S-9, Ajay Enclave Market, New Delhi.	Metal sliding door bolts (Aldrops) Type-3—IS : 2681—1978.
53.	CM/L-11626 37 1983-02-11	83-03-01	84-02-29	National Rolling & Steel Ropes Ltd., East Ghoshpara Road, Athpur, Shyamnagar, 24 Parganas (WB) (Off : NICCO House, 1 & 2, Hare Street, Calcutta-700001 (WB).	Galvanized steel wire for telegraph & telephone purposes— IS : 279—1981
54.	CM/L-11627 38 1983-02-11	83-03-01	84-02-29	—do—	Steel core wire for aluminium conductors galvanized steel reinforced — IS : 398 (Pt II)—1976
55.	CM/L-11628 39 1983-02-14	83-03-01	84-02-29	La-Gajjar Engg. (P) Ltd., Ugami Pvt. Ltd., Premises, Naroda Road, Ahmedabad-380025 (Gujarat)	Domestic gas stoves for use with liquefied petroleum gases with double burners with side holes rating 1608 Kcal/h each— IS : 4246—1978
56.	CM/L-11629 40 1983-02-15	83-03-01	84-02-29	Shree Krishna Co., 52, J.N. Mukherjee Road, Howrah-6 (WB)— (Off : 15, Brabourne Road, Calcutta-700001 (WB)].	Laminated jute bags for packing fertilizers manuafactured from 407 g/m 85 × 39 tarpaulin fabric— IS : 7406 (Pt I)—1974.
57.	CM/L-11630 33 1983-02-15	83-03-01	84-02-29	—do—	Laminated jute bags for packing fertilizers manufactured from 380g/m 68 × 39 tarpaulin fabric— IS : 7406 (Pt II)—1980
58.	CM/L-11631 34 1983-02-15	83-02-16	84-02-15	Bharat Impex (P) Ltd., A-1/2202 3rd Phase C.I.D.C. Vapi-596195 (Distt. Bulsar).	Unplasticized PVC pipes for potable water supplies— IS : 4985—1981
59.	CM/L-11632 35 1983-02-15	83-03-01	84-02-29	Aquolac Paints, 70 Najafgarh Road, New Delhi-110015.	Ready mixed paint, brushing, acid and alkali resisting lead free, for general purposes— IS : 1571—1950.
60.	CM/L-11633 36 1983-02-15	83-03-01	84-02-29	Duniya Hosieries, 15 College Road, Tirupur-638602 (TN).	Plain Knitted cotton vests Type : RN & RNS, Size : 75 to 90 cm: Gauge 24— IS : 4964—1980.
61.	CM/L-11634 37 1983-02-13	83-03-01	84-02-29	Agroemental & Spray Equipent Corp, Delhi Road, Gohana Rly. Crossing, Rohtak (Haryana).	Foot sprayer— IS : 3652—1974
62.	CM/L-11635 38 1983-02-15	83-03-01	84-02-29	Nagpur Motors Pvt. Ltd., D-76 M.I.D.C., Nagpur-440028.	Three phase induction motors, Clas 'B' insulation, upto and including 2.2 kw— IS : 325—1978.

1	2	3	4	5	6
63.	CM/L-11636 39 1983-02-15	33-03-01	84-02-29	Jay Vee Pharmaceuticals, 10, Gopal Nagar, Majitha Road, Amritsar.	Cermal, plain— IS : 4467 (Pt)—1980.
64.	CM/L-11637 40 1983-02-15	83-03-01	84-02-29	Acromix Chemicals & Castings (P) Ltd. 327 Village Jonapur, Mehrauli, New Delhi-110030.	Ready mixed paint for road marking, grade 2— IS : 164—1981
65.	CM/L-11638 41 1983-02-15	83-03-01	84-02-29	Indo Bell Insulations (P) Ltd., 1 Transport Depot Road, Calcuitta-700038 (W.B.).	Unbonded rock and slagwool for thermal insulation, Type II— IS : 3677—1973
66.	CM/L-11639 42 1983-02-15	83-03-01	84-02-29	Moonlight Paints Inds., 11 East Mohan Nagar, Outside Sultanwind Gate, Amritsar (Punjab).	Ready mixed paint, brushing, for road marking— IS : 164—1951.
67.	CM/L-11640 35 1983-02-15	83-03-01	84-02-29	Santosh Equipment Co., 10 Red Hills Road, Kolathur, Madras-600099 (TN)	Domestic gas stoves for use with liquefied petroleum gases with double burners rating : 601/h each— IS : 4246—1978
68.	CM/L-11641 36 1983-02-16	83-02-16	84-02-15	Universal Cables Ltd., P.O. Birla Vikas, Satna (MP) 485001	Flexible cables for miner's cap lamps— IS : 2593—1964
69.	CM/L-1164 237 1983-02-15	83-03-01	84-02-29	Inca Cables Pvt. Ltd., 149, Tambaram Valachery Road, Sembakkam, Madras-600073	PVC insulated (heavy duty) electrical cables unarmoured with aluminium conductors for working voltages upto and including 1100 V— IS : 1554 (Pt I)—1976.
70.	CM/L-11643 38 1983-02-15	83-03-01	84-02-29	Welworth Insulated Cables Co., 22, Industrial Area, Yoyyadi, Mangalore-575008.	PVC insulated (heavy duty) electric cables, unarmoured with aluminium conductor for working voltages— upto and including 1100 volts— IS : 1554 (Ot I)—1976
71.	CM/L-11644 34 1983-02-16	83-02-16	84-02-15	Hind Tin Indutries, P-355. Keyatala Road, Calcutta-700029	18-Litre square tins— IS : 916 1975.
72.	CM/L-11645 40 1983-02-18	83-02-01	84-02-29	Mutha Indl. Corpn., 15 Industrial Estate, Raipur M.P.	Aluminium stranded conductors for overhead transmission purposes— IS : 398(Pt I)—1976
73.	CM/L-11646 41 1983-02-18	83-03-01	84-02-29	Western Electronics, A-46, Shastri Nagar, Jodhpur (Off : 575, 10th—'C' Road, Sardarpura, Jodhpur).	Cube moulds as per clause No. 8, 4.2.1 and clause 9.3.2 Sizes 50 mm and 70.6 mm IS : 4031—1968.
74.	CM/L-11647 42 1983-02-18	83-02-16	84-02-15	Suprect Electrical Industries, A-21/24, Naraina Industria Are Phase II, New Delhi-110028.	Propeller type AC ventilating fans single phase with Class E insulation sizes 300 mm, 450 mm and 600 mm— IS : 2312—1967.
75.	CM/L-11648 43 1983-02-17	83-03-01	84-02-29	Avtar Singh & Co., Dehradun Road, Saharanpur-247 001.	Concrete pipes Class NP2 and NP3— Sizes upto 1200 mm only IS : 458—1971.
76.	CM/L-11649 44 1983-02-18	83-03-01	84-02-29	Jai Hind Tin Factory, Kailashpur, Distt. Saharanpur (U.P.).	18-Litres square tins— IS : 916—1975.
77.	CM/L-11650 37 1983-02-20	83-01-01	84-02-29	Johnson Peddar Pvt. Ltd., Industrial Area No. 2, A.B. Road, Dewas (Off : 11/B, Ratlam Kothi, Indore-452001).	Flushing cisterns for water closets and urinals (Valveless siphonic type) vitreous china, low level 10 and 12.50 litres discharge capacity— IS : 774—1971.
78.	CM/L-11651 38 1983-02-17	83-03-01	84-02-29	Western Electronics, A-46, Shastri Nagar, Jodhpur (Off : 575, 10th—'C' Road, Sardarpura, Jodhpur).	Cube moulds (15 ×15×15 cm clause 2.9.1— IS : 516—1959.

1	2	3	4	5	6
79.	CM/L-11652 34 1983-02-17	83-03-01	84-02-29	Fyrcool &P. Ltd., B-16, SIDCO Industrial Estate, Hozur-635126 (Off : 188, Thambu Chetty Street, Madras-600001).	Dry powder for fire fighting excluding foam compatibility)— IS : 4308—1967.
80.	CM/L-11653 40 1983-02-17	83-03-01	84-02-29	R. Plywood Products, 7/1 Gurudas Dutta Garden Lane, Calcutta-700067.	Plywood tea-chest panels— IS : 10(Pt II)—1976
81.	CM/L-11654 41 1983-02-21	83-03-01	84-02-29	Acromix Chemicals & Coatings (P) Ltd., 327 Village Jonapur, Mehrauli, New Delhi-110030.	Cement paint, colour as required— IS : 5410—1969.
82.	CM/L-11655 42 1983-02-21	83-03-01	84-02-29	Medicare Equipment Co, Plot No. 333, C.I.D.C. Estate, Makarpura, Baroda-390010 (Gujarat)	Horizontal cylindrical high speed steam sterlizers, pressure type— IS : 2510—1978
83.	CM/L-11656 43 1983-02-21	83-03-01	83-02-29	Industrial Felt Corpn., 3/1-2 (Phase-VI), Adityapur Industrial Area, P.O. Gamaria, Jamshedpur-832108 (Off : 8, Rustomji Mansion, Ist floor, Bistupur, P.O. Jamshedpur-832001).	Unbonded rock and slagwool for thermal insulation, type I— IS : 3677—1973
84.	CM/L-11657 44 1983-02-21	83-03-01	84-02-29	Golden Paints & Chemicals, Outside Chatiwind Gate, Kot Mahna Singh, Amritsar-143001 (Punjab). (Off : 43, Akali Market, Amritsar).	Cement paint, colour as required— IS : 5410—1969
85.	CM/L-11658 45 1983-02-21	83-03-01	84-02-29	Bajaj Paints Industries, Industrial Estate, Kathipur—244713, Dist. Nainital (U.P.).	Enamel, Interior, finishing— IS : 133—1975
86.	CM/L-11659 46 1983-02-21	83-03-01	84-02-29	Kushal Metals & Paints Inds., A-76 Okhla Indl. Area, Phase-II, New Delhi-110020.	Cement paint, colour as required— IS : 5410—1969.
87.	CM/L-11660 39 1983-02-21	83-03-01	84-02-29	Aryl Chemicals, W-27, (E), MIDC Industrial Complex, TTC Industrial Area, Rabale Thane Belapur Road, Thane-400701 (Maharashtra)	1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone— IS : 8553—1977
88.	CM/L-11661 40 1983-02-21	83-03-01	84-02-29	Mona Motive Engineer Pvt. Ltd., 86/2, G.I.D.C. Industrial Estate, Phase-I, Vatva, Ahmedabad-382445 (Gujarat)	Monoset pumps for clear, cold, fresh water for agricultural purposes of the following size : 65 × 65 mm Type/Model :— Duty point : At 22.5 m head discharge 10.5 lps and overall efficiency 54% motor 3.7 kw Class E insulation— IS : 9079—1979
89.	CM/L-11662 41 1983-02-21	83-03-01	84-02-29	Bhangar Enterprises, 211, GIDC. Industrial Estate, Umbergaon, Dist. Bulsur, Gujarat (Off : 111, Atlanta, Nariman Point, Bombay-400023).	Monoset pumps for clear, cold, fresh water for agricultural purposes of the following sizes : Size - 65 x 50 mm Type : H32H. Duty Point : At 22.5 m head discharge 6.5.1/Sec and overall, efficiecy 49% Motor Input : 2.2 kw, Class E insulation— IS : 9079—1979.
90.	CM/L-11663 42 1983-02-22	83-03-01	84-02-29	Shivalik Agro Chemicals, B-59, Industrial Focal Point, SAS Nagar, Mohali Distt., Ropar.	Carbaryl WDP 50% Ground spray grade— IS : 7121—1973
91.	CM/L-11664 43 1983-02-22	83-03-01	84-02-29	—do—	Malathion 25% WDP— IS : 2569—1978.

1	2	3	4	5	6
92.	CM/L-11665 44 1983-02-24	83-03-01	84-02-29	Gimpex Rubbers, 44.6 K.M. Stone, G.T. Road, Village Kat, P.O. Dadri 203207, Distt. Ghaziabad. (Off : 107, Sahyog, 58 Nehru Place, New Delhi-110019).	Rubber conveyor and elevator belting for general purposes Grade : "N-17 & M--24" IS : 1891(Pt I)—1978
93.	CM/L-11666 45 1983-02-24	83-03-01	84-02-29	Aggarwal Multi Casting, Goniana Road, Bhatinda (PUNJAB).	Cast iron soil pipes Size 100 mm— IS : 1729—1979
94.	CM/L-11667 46 1983-02-24	83-03-01	84-02-29	Harcharan & Bros., Preet Nagar, Indl. Area, Jullundur City.	Elbows upto and including size designation 2— IS : 1879 (Pt II) 1975
95.	CM/L-11668 47 1983-02-24	83-03-01	84-02-29	Everite Sales Corpn., 4, Industrial Area, Tilak Nagar, New Delhi-110016	Floor spring (hydraulically regulated) for heavy doors— IS : 6315—1971
96.	CM/L-11669 48 1983-02-24	83-03-01	84-02-29	Quality Metal Industries, 614, Sukarawarpet, Coimbatore-641001	Plywood tea-chest metal fittings— IS : 10 (Pt IV)—1976
97.	CM/L-11670 41 1983-02-24	83-03-01	84-02-29	Green Engg. Corpn., S-255, Indl., Area, Jullundur City.	Elbows upto and including size designation 2— IS : 1879 (Pt II)—1975
98.	CM/L-11671 42 1983-02-24	83-03-01	84-02-29	United Metal Works, 30A, Industrial Development Colony, Bye Pass, Jullundur-144 004	—do—
99.	CM/L-11672 43 1983-02-25	83-03-16	84-03-15	Kanoria Chemicals & Industries Ltd. Ludlow Jute Mills Division, Chengail (S.E. Rly) Dist. Howrah (West Bengal) (Off : 16A, Brabourne Road, Calcutta-700001).	B-twill jute bags— IS : 2566—1965
100.	CM/L-11673 44 1983-02-25	83-03-16	84-03-15	Dawar Re-rolling Mill, Jawahar Nagar Mango, Jamshedpur-8311012. [Off : Kashana-e-Shabina, Near Golmuri Mosque, P.O. Golmuri, Jamshedpur].	Cold worked steel high strength deformed bars for concrete reinforcement— IS : 1786—1979.
101.	CM/L-11674 45 1983-02-25	83-03-16	84-03-15	Dawar Re-rolling Mill, Jawahar Nagar, Mango Jamshedpur-831012 (Off : Kashana-e-Shabina, Near Golmuri Mosque, P.O. Golmuri, Jamshedpur).	Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1975
102.	CM/L-11675 46 1983-02-25	83-03-16	84-03-15	—do—	Structural steel (standard quality)— IS : 226—1975
103.	CM/L-11676 47 1983-02-28	83-03-16	84-03-15	Leimco, 119 Punjani Industrial, Estates, Khopat, Thane-406601 [Off : 127, Madhani Estate, Senapati Bapat Marg, Dadar, Bombay-400028 (Maharashtra)]	Density hydrometers, L-50 and M-50 series— IS : 3104 (Pt I)—1982

[CMD : 13 : 11]

B. N. SINGH, Additional Director General

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1986

का. आ. 1893 :—मैसर्स श्री अरबुदा मिल्स लिमिटिड, राखिल रोड, अहमदाबाद-380021, (जी. जे./284) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि, आयुक्त, मद्रास को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपने दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम

का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/152/86-एस.एस-II]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 21st April, 1986

S.O. 1893.—Whereas Messrs Shri Arbuda Mills Limited, Rakial Road, Ahmedabad-380021 (GJ/284) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separte contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/152/86-SS-II]

का. आ. 1894—: मैसर्स एलेकोन इन्जीनियरिंग कम्पनी लि., पी. बो. नं.—6 बी. बी. नगर—388120, गुजरात (जी. जे /1834) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों, का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, या पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/153/86-एस.एस-II]

S.O. 1894.—Whereas Messrs Elecon Engineering Company Limited, P.B. No. 6, V. V. Nagar (Gujarat) (GJ/1834) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved, in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces-

sary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/153/86-SS-II]

का. आ. 1895—मैसर्स देवीदयाल (सेल्ज) प्रा. लि. पोस्ट बाक्स 6219, तुलसीराम गुप्ता मिल्ज एस्टेट रियें रोड़, बम्बई-400010 और इसकी हैदराबाद, गुलबर्गा, इन्दौर, विजयवाडा, हुबली, और नई दिल्ली स्थित शाखाएं (एम.एस./5153) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी एकमुश्त अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे

स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014(141)/86-एस. एस.-2]

S.O. 1895.—Whereas Messrs Devidayal (Sales) Private Limited, Post Box 6219, Tulsiram Gupta Mills, Estate, Reay Road, Bombay-400010 including its branches at Hyderabad, Gulbarga, Indore, Vijayawada, Hubli and New Delhi (MH/5153) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including, maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendments is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insu-Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/141/86-SS-II]

का. आ. 1896—मैसर्स सिपला लिमिटिड, 289 बैलासीस रोड, बम्बई—400008 (एम. एच. 1073) और इसकी इन्दौर, बंगलौर, चण्डीगढ़, अहमदाबाद, कोचीन, हैदराबाद, मद्रास, पटना, नई दिल्ली, कलकत्ता, पटलगंगा (महाराष्ट्र) बम्बई और लखनऊ स्थित शाखोओं सहित । (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 19 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976

(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं :

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी की विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014(150)/86-एस. एस.-2]

S.O. 1896.—Whereas Messrs Cipla Limited, 289, Bellasis Road, Bombay-400008 (MH/1073) including its branches at Indore, Bangalore, Chandigarh, Ahmedabad, Cochin, Hyedarbad, Madras, New Delhi Calcutta, Patalganga (Maharashtra, Bombay) and Lucknow (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving is approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(150)/86-SS-II]

का. आ. 1897—मैसर्स में एण्ड बैकर (इण्डिया) लि., मेंडबेंकर हाउस बानली बम्बई–400025, और बंगलौर बम्बई, कलकत्ता, गोहाटी, हैदराबाद इन्दौर, जयपुर, लखनऊ, मद्रास, नई देहली और पटना स्थित शाखाए (एम. एच./1057 और 3916) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) के कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 19 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2 क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं :

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसके स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014(151)/86-एस. एस.-2]

S.O. 1897.—Whereas Messrs May & Baker (India) Limited, May Baker House, Worli, Bombay-400025 including its branches at Bangalore, Bombay, Calcutta, Gauhati, Hyderabad, Indore, Jaipur, Lucknow, Madras, New Delhi and Patna (MH/1057 and 3916) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Bombay, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(151)/86-SS-II]

का. आ. 1898—मैसर्स फारमस्टि डेरीज, लिमिटिड 72, जनपथ नई, दिल्ली —110001. (डी. एल./3455) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापत कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2 क के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम या संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है :

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों की जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(149)/86-एस. एस. 2]

S.O. 1898.—Whereas Messrs Foremost Dairies Limited, 72, Janpath, New Delhi-110001 (DL/3455) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employes' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter refrered to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts,

submission of returns; payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sums assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(149)/86-SS-II]

का. आ. 1899—मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटिड, 6, न्यू फतेहपुरा, उदयपुर-313001 (आर. जे/1272) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1624 तारीख 5-3-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 19-3-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 18-3-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन की सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक

वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिति/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/25/83-पी. एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1899.—Whereas Messrs Hindustan Zinc Limited 6, Fatehpura, Udaipur-313001 (RJ/1272) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1624 dated the 5-3-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 19-3-1986 upto and inclusive of the 18-3-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case, within one month from the receipt of claim complete in all respects

[No. S-35014(25)/83-PF.II(SS.II)]

का. आ. 1900—मैसर्स आटोमैटिक इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटिड, सी-9 अम्बादूर इन्डस्ट्रियल एस्टेट, मद्रास-58 (टी. एन. /5647) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे

इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 324 तारीख 6-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 8-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 7-2-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन की सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/391/82-पी.एफ.-2/एस.एस-2]

S.O. 1900.—Whereas Messrs Autolec Industries Private Limited, C-9, Ambattur Industrial Estate, Madras-58 (TN| 5647) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 324 dated the 6-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the

said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for further period of three years with effect from 8-1-1986 upto and inclusive of the 7-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/391/82-PF.II(SS.II)]

का. आ. 1901 :—मैसर्स डेवलपमैन्ट कन्सैल्टैन्ट प्राईवेट लिमिटिड, 24—बी, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता—700016 (डब्ल्यू बी. /13709) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसकी पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 41 तारीख 9-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 1-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 31-12-88 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/416/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1901.—Whereas Messrs Development Consultants Private Limited, 24-B, Park Street, Calcutta-700016 (WB/13709) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 41 dated the 9-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 1-1-1986 upto and inclusive of 31-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/416/82-PF.II(SS-II)]

का.आ. 1902.—मैसर्स शिवालिक एग्रो प्लाए प्रोडक्टस लिमिटिड, प्लाट नं.—1, सैक्टर—III, इन्डस्ट्रियल एरिया, परवानू, (हि. प्र.) 173220 जिला सोलन (पी. एन./6854) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 798 तारीख 10-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 5-2-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 4-2-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति की 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन की सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति से एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/424/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1902.—Whereas Messrs Sivalik Agro Ploy Products Limited, Plot No. 1, Sector III, Industrial Area Parwanoo (H.P./173220 District Solan (PN/6854) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 798 dated the 10-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 5-2-1986 upto and inclusive of 4-2-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where, any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of establishment do not remain covered under the Gro rance Scheme of the Life Insurance Corporation of already adopted by the said establishment, or the b the employees under this Scheme are reduced in any the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to premium etc. within the due date, as fixed by the I rance Corporation of India, and the policy is allowed the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the emp payment of premium the responsibility for payment rance benefits to the nominees or the legal heirs of members who would have been covered under the sai but for grant of this exemption, shall be tha employer.

12. Upon the death of the members covered u Scheme the Life Insurance Corporation of India sh prompt payment of the sum assured to the nomin Legal heirs of the deceased member entitled for i any case within one month from the receipt of claim in all respects.

[No. S-35014/424/82-PF-

का.आ. 1903.—मैसर्स अपोलो ट्यूब लिमिटे नं.-5, सिपकोट इन्डस्ट्रियल कम्पलैक्स, रानीपैट-6 (टी०एन०/10118) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रक बन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इस पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उ के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का स बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 331 तारीख 6-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 8-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 7-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार,

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सदय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/395/82-पी. एफ.-2/एस. एस.-2]

S.O. 1903.—Whereas Messrs Apollo Tubes Limited, Plot No. 5, Sipcot Industrial Complex, Kanipet-632403 (TN/10118) (hereinafter referred to as the said establishment) have apled for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 331 dated the 6-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 8-1-1986 upto and inclusive of 7-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, a and when amended, alongwith a translation of the salien features thereof in the language or the majority of th employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of th Employees' Provident Fund or the Provident Fund of a establishment exempted under the said Act, is employed i his establishment, the employer shall immediately enrol hir as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor poration of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benfits availa ble to the employees under the Group Insurance Schem appropriately, if the benefits available to the employee under the said Scheme are enhanced so that the benefit available under the Group Insurance Scheme are mor favourable to the employees than the benefits admissibl under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu rance Scheme, if on the death of an employee the amoun

payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to employees under the scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/395/82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1904.—मैसर्स रपटाकोस ब्रैट एन्ड कम्पनी लिमिटेड 47 डाक्टर अनी बिसैन्ट रोड, वरली, बम्बई-25 (एम.एच/1067) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 920 तारीख 23-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 12-2-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 11-2-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभ उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी खर्चों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पलिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/459/82-पी. एफ.-2/एस. एस.-2]

S.O. 1904.—Whereas Messrs. Raptakas Brett and Company Limited, 47, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-25 (MH/1067) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 920 dated the 23-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 12-2-1986 upto and inclusive of 11-2-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employee under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/459/82-PF-II (SS-II)]

का.आ. 1905.—मैसर्स श्री दिगविजय सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, पो.आ. दिगविजय नगर, अहमदाबाद-382470 (जी. जे./3951) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 क उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 904 तारीख 21-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 12-2-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 11-12-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/452/82-पी. एफ.-2/एस. एस.-2]

S.O. 1905.—Whereas Messrs Shree Digvijay Cement Company Limited, PO Digvijay Nagar, Ahmedabad-382470 (GJ|3951) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 904 dated the 21-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 12-2-1986 upto and inclusive of 11-2-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/452/82-PF-II (SS-II)]

का.आ. 1906.—मैसर्स भारत कामर्स एन्ड लिमिटिड, सूर्य किरण पांचवीं मंजिल, 19 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 (डी.एल/2857) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1705 तारीख 12-3-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 26-3-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 25-3-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियों भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पटट् पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके

स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(50)/83-पी.एफ.-2 एस०एस०-2]

S.O. 1906.—Whereas Messrs Bharat Commerce and Industry Limited, Suryya Kiran, 5th floor, 19 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 (DL/2857) (hereinafter refrered to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1705 dated the 12-3-83 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 26-3-86 upto and inclusive of the 25-3-89.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioners, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employed been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/50/83-PF-II (SS-II)]

का.आ. 1907.—मैसर्स श्री रामालिंगा मिल्स प्राइवेट लिमिटिड, 212 रामासामीनगर, पो. बो. नं.-18, एपु-कोटई-626159(टी.एन/5252) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4088 तारीख 13-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 4-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 3-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसके बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले

फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/437/82-पी०एस० 2-एस०एस०-2]

S.O. 1907.—Whereas Messrs Shri Rama Linga Mills Private Limited, 212, Ramasamynagar, PB No. 18, Arupukaltai-626159 (TN/5252) (hereinafter refrred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952(19 of 1952) (hereinafter refrered to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4088 dated the 13-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 4-12-85 upto and inclusive of 3-12-88.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/437/82-PF. SS-II)]

का.आ. 1908.—मैसर्स होटल ओबराय टावर्स, नरीमन पोआइन्ट बम्बई-400021 (एम.एच./15448) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे

उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4280 तारीख 1-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 18-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजकों द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमो की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उस संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/389/82-पी.एफ-2/एस.एस-2]

S.O. 1908.—Whereas Messrs Hotel Oberoi, Towers Nariman Point, Bombay-400021 (MH/15448) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more

hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-12-1985 upto and inclusive of the 17-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/389/82-PF-II (SS-II)]

का.आ. 1909.—मैसर्स राठी गैसज लिमिटेड, 3-ए, बन्दना-11, टालसटाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 (डी.एल/-5224) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1333 तारीख 28-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 26-2-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 25-2-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक

बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत-सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/468/82-पी०एफ०-2-एस.एस-2]

S.O. 1909.—Whereas Messrs Rathi Gases Limited, 3A, Vandana, 11 Tolstoy Marg, New Delhi-110001 (DL/5224) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1333 dated the 28-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 26-2-1986 upto andinclusive of the 25-2-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the bentfis available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount apayable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, **the exemption shall be liable to be cancelled.**

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|468|82-PF-II (SS-II)]

का.आ. 1910.—मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टीबाओटिक लिमिटिड, पिम्परी पूना-411018 (एम.एच/1459) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4275 तारीख 26-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 18-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-एट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम की उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/339/82-पी.एफ.-2/एस. एस-21

S.O. 1910.— Whereas Messrs Hindustan Antibiotic Limited, Pimpri, Poona-411018 (MH/1459) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4275 dated the 26-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-12-1985 upto and inclusive of 17-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. E-35014/339/82-PF. II(SS.II)]

का. आ. 1911.—पैसर्स हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि. पो. आ. औंधार टाऊनशिप, नासिक डिविजन, नासिक (एम.एच./8266) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम

सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ,

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4274 तारीख 26-11-1982 के अनुक्रमण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 18-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत-सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम-निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय त्वरता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35011/333/82-पी.एफ-II एस.एस-II]

S.O. 1911.—Whereas Messrs Hindustan Aeronautic Limited, P.O. Ojhar Town Ship Nasik Division, Nasik (MH/8266) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4274 dated 26-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-12-1985 upto and inclusive of 17-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/333/82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1912.—मैसर्स फेनर इन्डिया लिमिटेड, कोचादाई, मदुराई (टी. एन/940), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, जिसे पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे अंशदायी की को उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3334 तारीख 25-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 18-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-9-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकम के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत-सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतगत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस.-35014/16/82-पी.एफ/2 एस. एस.-2]

S.O. 1912.—Whereas Messrs Fanner India Limited, Kochadai, Madurai (TN/940) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3334 dated the 27-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for further period of three years with effect from 18-9-1985 upto and inclusive of the 17-9-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/16/81-PF. II (SS-II)]

का. आ. 1913.—मैसर्स न्यू शोररोक मिल्स डिविजन आफ मफतलाल इन्डस्ट्रीज लिमिटिड, असवी रोड, अहमदाबाद (जी. जे./362), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3729 तारीख 11-10-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 30-10-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 29-10-1988 को समाप्त होता है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण भारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को

[illegible] का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/144/85-पी एफ-2 एस.एस-2]

S.O. 1913.—Whereas Messrs New Shorrock Mills (Division of Mafatlal Industries Limited), P.B. No. 2006, Asarwa Road, Ahmedabad (GJ/362) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 3729 dated the 11-10-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 30-10-1985 upto and inclusive of the 29-10-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time

2. The employer shall pay such inspection charges as the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, clause (a) of sub-secion (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features therefore, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/144/82 PF-II (SS-II)]

का. आ. 1914.—मैसर्स नीडल्स इन्डस्ट्रीस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटिड, कैटी, नीलगिरी (टी. एन./854), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को जो उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 21 तारीख 6-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 1-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 1-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (2क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(290)/82/पी.एफ.-2 (एस. एस.-2)]

S.O. 1914.—Whereas Messrs. Needle Industries (India) Private Limited Ketti, Nilgiri. (TN/854) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and, in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 21 dated 6-12-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 1-1-1986 upto and inclusive of the 31-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissoner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-secion (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insuracne Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to effects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable Opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/290/82-PF. II (SS-II)]

का. आ. 1915.—मैसर्स सिहिर टैक्सटाइल लिमिटिड, खोखरा मेहमेदाबाद, अहमदाबाद-380008 (जी. जे./262) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3548 तारीख 23-9-82 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 9-10-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 8-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसें स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित् करेगा।

[संख्या एस-35014/84/82—पी. एफ.-II]

S.O. 1915.—Whereas Messrs Mihir Textiles Limited, Khokhra, Mahemedabad. Ahmedabad-38008 (GJ/262) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3728 dated the 11-10-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 30-10-1985 upto and inclusive of the 29-10-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts,

submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect aversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered udner the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/79/82-PF. II (SS-II)]

का. आ. 1916.—मैसर्स महेश्वरी मिल्स लि., शाहीबाग रोड, अहमदाबाद-380004 (जी. जे./309), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3154 तारीख 21-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 4-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 3-9-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत-सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/146/82-पी.एफ. 2-एस.एस-2]

S.O. 1916.—Whereas Messrs. Maheshwari Mills Limited, Shahioag Road, Ahmedabad-380004 (GJ/309) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3154 dated the 21-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 4-9-1985 upto and inclusive of the 3-9-1988.

SCHEDULE

1. The employers in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provided such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal

heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/146/82-PF II (SS-II)]

का. आ. 1917.—मैसर्स मिनरल सेल्स प्राइवेट लिमिटेड को-आपरेटिव कालोनी, होसपेट-583203, जिला बेलरी, कर्नाटका (के. एन/3096), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3341 तारीख 27-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 18-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-9-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि, यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य का मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दाव की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/212/82-पी.एफ.-2 (एस.एस-2)]

S.O. 1917.—Whereas Messrs. Mineral Sales Private Limited, Co-operative Colony, Hospet-583203 Bellary District Karnatka (KN/3096) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976(hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3341 dated the 27-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 12-9-1985 upto and inclusive of the 17-9-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Whereas, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sums assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/212/82-PF. II (SS-II)]

का. आ. 1918.—मैसर्स ब्रिटिश मोटर कार कम्पनी (1934) लिमिटिड, प्रताप बिल्डिंग, ए न ब्लाक, कनाट प्लैस, नई दिल्ली-110001 (डी. एल./199), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 399 तारीख 9-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 15-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 14-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एकप्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापन पहले अपना दावा है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती-विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/281/82-पी.एफ.-2 (एम.एम.-2)]

S.O. 1918.—Whereas Messrs British Motor Car Company (1934) Limited, Pratap Building, N-Block, Connaught Place, New Delhi-110001 (DL/199) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976(hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 399 dated the 9-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for further period of three years with effect from 15-1-1986 upto and inclusive of the 14-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him

as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Whereas, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/281/82-PF. II(SS. II)]

का.आ. 1919 मैसर्स भोपाल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड–1 सुलतानिया रोड भोपाल–462001 (एम. पी/1059) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3610 तारीख 27-9-82 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 16-10-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 15-10-1988 भी सम्मिलित है उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय–समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय–समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा

में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती की प्रतिक के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दा करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय, जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/126/82 पी०एफ०-2-एस०एस०-2]

S.O. 1919.—Whereas Messrs. Bhopal Motors Private Limited, 1, Sultania Road, Bhopal-462001 (MP/1059) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3610 dated the 27-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 16-10-1985 upto and inclusive of the 15-10-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charge etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the account that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/126/82-PF. II (SS-II).

का.आ. 1920 मैसर्स अक्शाया टेक्सटाइलस लिमिटेड पो. आ. नं. 2008 गणपति पो. आ. कोइम्बाटूर-640006 [पहले श्री गोपाल कृष्ण मिल्स (प्रा.) लिमिटेड] (टी. एन./2395) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3237 तारीख 24-8-1982 के अनुसरण में और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 11-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 10-9-1988 भी सम्मिलित है उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें, ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु की पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम की, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/121/82-पी.एफ.-2/एस एस.-2]

S.O. 1920.—Whereas Messrs Akshaya Textiles Limited P. B. No. 2008, Ganapathy P.O., Coimbatore 641006 [formerly M/s. Sri Gopala Krishna Mills (P) Limited (T.N./2593)] (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3237 dated the 24-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 11-9-1985 upto and inclusive of the 10-9-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payament of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/121/82-PF. II (S-II)]

का.आ. 1921 मसर्स भीलवाड़ा स्पिनर्स लिमिटेड भीलवाड़ा (पहले राजस्थान स्पीनिंग एण्ड वविंग मिल्स लिमिटेड के नाम से था) राजस्थान (आर. जे./746) (जिसे, इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3336 तारीख 27-8-82 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 18-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-9-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा, यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितियों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(109)/82-पी. एफ.-2/एस. एस.-2]

S.O. 1921.—Whereas Messrs. Bhilwara Spinners Limited, Bhilwara (Formerly Rajasthan Spinning and Weaving Mills Limited) Rajasthan (RJ/746) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3336 dated the 27-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-9-1985 upto and inclusive of the 17-9-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/109/82-PF. II (SS II)]

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1986

का.आ. 1922:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिएं:—

1. मैसर्स प्लासडायनमिक्स, 5 लेक टैम्पल रोड, कलकत्ता-29
2. मैसर्स चक्रवर्ती चटर्जी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, 15, कालिज स्क्वेयर, कलकत्ता-73
3. मैसर्स स्टील प्लांट सर्विसिज, टोडी मेनसन पी, 15 इन्डिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-73, और इसकी (1) राउरकेला (2) धनबाद (बिहार) स्थित शाखाएं।
4. मैसर्स कलकत्ता मशीनरी एण्ड स्पेयर्स, 10 केनिंग स्ट्रीट कलकत्ता और इसका 2 गणेशचन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता-13 में स्थित आटो मोबाइल डिवीजन।
5. मैसर्स इलैक्ट्रोलिक इन्जीनियरिंग कम्पनी श्री अरविन्द रोड रामराजातला, हावड़ा-14।
6. मैसर्स चक्रवर्ती इण्डिया प्रा.लि., 17 गणेशचन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता-13
7. मैसर्स हिन्दुस्तान एमोलिएट्स 50/1, कालिज स्ट्रीट, कलकत्ता-73।
8. मैसर्स भगवती प्लाईवुड इन्डस्ट्रीज पखाबाड़ी रोड पी.ओ. सी टी गारा, सिलीगुड़ी (दार्जिलिंग) वेस्ट बंगाल।
9. मिर्जा दलित फर्टीर (मैसर्स आफ बागडोगरा एअर पोर्ट रैस्टोरैन्ट जिला दार्जिलिंग) वैस्ट बंगाल
10. मैसर्स आर्गेनिसियन्स सेन्टर "हिमालय हाउस" 38 चौरंगी रोड कलकत्ता-71 और इसका पी.ओ. गंगानगर जिला 24 परगना वैस्ट बंगाल स्थित यूनिट।
11. मैसर्स अग्रवाल स्टैंड बिज कम्पनी 100-ए, घोस घोष रोड, हावड़ा (वैस्ट बंगाल)
12. मैसर्स प्रोग्रेसिव मशीनरी प्रा.लि., 34, बिहारी लाल घोष रोड, कलकत्ता-57 और इसका 5ए गोबरा रोड, कलकत्ता-14 स्थित कार्यालय।
13. मैसर्स गारलिक इन्जीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 22, डा० बी. सी. राय रोड, पी.ओ. राजपुर, 24 परगना, वैस्ट बंगाल और इसका 16, खानपुर रोड, कलकत्ता-47 स्थित कार्यालय।
14. मैसर्स नैशनल सप्लायर्स कारपोरेशन, 11-ए मोलांगा लेन (फोर्थ फ्लोर) कलकत्ता-13
15. मैसर्स अपर्नेचर, 76, पी 29 सी. आई टी. रोड, कलकत्ता-14
16. मैसर्स प्रेसमैन एडवरटाईजिंग एण्ड मार्केटिंग प्रा. लि. 9 गार्स्टिन रोड, कलकत्ता-1 और इसकी ए. टी. रोड, शान्तिपुरम, गोहाटी आसाम स्थित शाखा।
17. मैसर्स रंगा जान डी एण्ड एसोसिएशन इन्डस्ट्रीज प्रा.लि., चटर्जी. इन्टरनेशनल सैंटर 20वीं मंजिल स्यूट नं. 1 33-ए, चौरंगी, रोड कलकत्ता-71
18. मैसर्स रिलायंस सर्विसिज एण्ड कन्सल्टेन्ट्स लि. 9, गार्स्टिन रोड, कलकत्ता-1
19. मैसर्स कोलापुर इंगलिश स्कूल, 59, ऊपर ईस्ट स्ट्रीट, कलकत्ता-2

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[संख्या 35017(7)/86-एस.एस.-2]

New Delhi, the 23rd April, 1986

S.O. 1922.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the respective establishments, namely :—

1. M/s. Pladynamics, 5, Lake Temple Road, Calcutta-29.
2. M/s. Chuckervertty Chatterjee & Co. Limited, 15, College Square, Calcutta-73.
3. M/s. Steel Plant Services, Todi Mansion P-15, Indian Exchange Place, Calcutta-73, including its branched at Rourkela and Dhanbad.
4. M/s. Calcutta Machinery and Spares 10, Canning Street, Calcutta, including its Automobile Division at 2 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.
5. M/s. Elecdrolik Engineering Company, Shree Aurobindo Road, Ramrajatala, Howrah-4.

6. M/s. Biworth India Private Limited, 17 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.

7. M|s. Hindustan Associates, 50|1, College Street, Calcutta-73.

8. M|s. Bhagwati Plywood Industries Pankhabari Road, P.O. Matigara. Siliguri, West Bengal.

9. M/s. Dipti Caterer (Lesee of Bagdogra Airport Restaurant), District Darjeeling, West Bengal.

10. M|s. Organon Research Centre, Himalya House 38 Chowringee Road, Calcutta-71 and its Unit at Ganganagar Dist. 24 Paraganas, West Bengal.

11. M|s. Agarwal Weigh Bridge Company-109A, Girish Ghosh Road Howrah.

12. M|s. Progressive Machinery Pvt. Ltd., 34, Biharilal Ghosh Road, Calcutta-57, including its office at 5-A Gobra Road, Calcutta-14.

13. M/s. Garrison Engineering Company Private Limited, 22 Dr. B. C. Roy Road, P.O. Rajpur, 24 Paraganas including its office at 16, Khanpur Road, Calcutta-47.

14. M|s. Marine Suppliers Corporation, 11-A, Molonga Line (1st Floor), Calcutta-12.

15. M|s. Adunique 76, P-29, CIT Road, Calcutta-14.

16. M|s. Pressman Advertising and Marketing Private Limited 9, Brabourne Road, Calcutta-1, including its branches at A.T. Road, Santispur Gauhati, Assam.

17. M/s. Rungajaun Tea and Plantation Industries Private Limited, Chatterjee International Centre 20th Floor, Suite No. 1, 33-A Chowringhee Road, Calcutta-71.

18. M|s. Reliance Services and Consultants Ltd., 9, Brabourne Road, Calcutta-1.

19. M|s. Cossipore English School, 59, Seven Tanks Estate Calcutta-2.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishment.

[S-35017|7|86-SS.II]

का.आ. 1923:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनों के सम्बद्ध नियोजकों और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापनों को लागू किये जाने चाहिएं।

1. मैसर्स सन तेज एजेन्सीज, 214 डाक लेन थर्ड फ्लोर कामन वैल्थ बिल्डिंग मेडोस स्ट्रीट, बम्बई-23

2. मैसर्स क्वालिटी पास्टरस, 262, कल्याण दास उद्योग भवन नियर सैचरी बाजार, वार्ली बम्बई-25

3. मैसर्स राजेश आर्ट प्रिन्टर्स, अपो. बी.डी.डी. चाल नं. 114 वार्ली बम्बई-13

4. मैसर्स रीट कैमिकल्ज, यूनिट नं. 13, गुरू गोविन्द सिंह इन्डस्ट्रीयल इस्टेट वैस्ट्रन एक्सप्रेस हाईवे गोरे गांव, बम्बई-63

5. मैसर्स एच के इन्डस्ट्रीज, 15 स्वास्तिक इन्डस्ट्रीयल इस्टेट 178 विद्या नगरी कालिना, बम्बई-98

6. मैसर्स न्योग्राफिक्स (इण्डिया) अलंकार बिल्डिंग पोस्ट बाक्स नं.-18 मार्गोव गोवा-1

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[संख्या एस-35018(6)/86-एस.एस-2]

S.O. 1923.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. Suntej Agencies, 2|4, Dak Lane, 3rd Floor, Commonwealth Building, Medows Street, Bombay-23.

2. M/s. Kwality Pasters, 262, Kalyandas Udyog Bhavan, Near Century Bazar, Warli, Bombay-25.

3. M|s. Rajesh Art Printers, Opposite B.O.D. Chawl No. 114, Waril, Bombay-13.

4. M/s. Ritu Chemicals, Unit No. 13, Guru Govind Singh Industrial Estate, Western Express, Highway, Goregaon (East., Bombay-63.

5. M|s. H. K. Industries, 15, Swastik Industrial Estate 178, Vidyahagari, Kalina, Bombay-98.

6. M|s. Neografiks (India), Alankar Building, Post Box No 18, Margao Goa-1.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[No. S-35018(6)/86-SS.II]

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1986

का.आ. 1924 मैसर्स सीट टायर्स आफ इण्डिया लि. 463 डाक्टर एनी बसन्त रोड बम्बई-400025 और इसकी ओटोमेटिव टायर फैक्ट्री भनडूप बम्बई 400078 (एम. एच/5581) और 82 मिड इण्डस्ट्रियल एस्टेट, सातपुर, नासिक-422007 (एम.एच./15654) में स्थित साईकल टायर यूनिट (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अन्तर्गत छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 402 तारीख 10-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 15-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 14-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसे विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसके मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/384/82-पीएफ-2/एस. एस-2]

New Delhi, the 24th April, 1986

S.O. 1924.—Whereas Messrs Ceat Tyres of India Limited, 463, Dr. Annie Besant Road, Bombay-400025 and its Automotive Tyre Factory, Bhandup, Bombay-400078(MH/5581) and cycle Tyre Unit at 82 Mide Industrial Estate, Satpur Nasik-422007 MH/15654) (hereinfater referred to as the said establishment) have aplied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 402 dated the 10-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 15-1-1986 upto and inclusive of the 14-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund

Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules ofthe Group Insuran e Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insuracne Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees orthe legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/384/82-PF. II (SS-II)]

का.आ. 1925 मसर्स गुजरात एलक्ट्रिसिटी बोर्ड विद्युत भवन रेस कोर्स वडोदरा (जी. जे./920) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उस स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2326 तारीख 6-5-1983 के अनुक्रम में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 21-7-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 20-7-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसा विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक

बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक जीवन बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत-सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/131/83-पी.एफ. 2-एस.एस.-2[

131 GI/86—11

S.O. 1925.—Whereas Messrs. Gujarat Electricity Board, Vidyut Bhavan, Race Cource, Vadodara-7 (GJ/920) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2326 dated the 6-5-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 21-7-1986 upto and inclusive of 20-7-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the maiority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insu-

rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/131/83-PF-II (SS-II)]

का.आ. 1926:—मैसर्स ट्रेड लिन्कस लिमिटेड 17 राजेन्द्रा प्लेस प्रभात किरण, तीसरी मंजिल, नई देहली—110008 (डी. एल./1075) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 931 तारीख 22-1-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 12-2-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 11-2-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दहेली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दहेली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता

से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/7/3/83-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1926.—Whereas Messrs. Trade Links Limited, 17 Rajindra Place, Prabhat Kiran, 3rd Floor, New Delhi-110008 (DL/1079) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee s Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 931 dated the 22-1-83 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 12-2 1986 upto and inclusive of the 11-2-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where, any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/7/83-PF-II (SS-II)]

का.आ. 1927.—मैसर्स श्री चामुण्डेश्वरी सूगर्स लिमिटेड, रजि. आफिस 37/1, मैसूर रोड, बंगलौर-560042 (के.एन./5710) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2325 तारीख 8-5-1983 के अनुसरण में हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 21-7-86 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 20-7-1989 भी सम्मिलित है । उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटका के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(130)/83-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1927.—Whereas Messrs. Shri Chamundeshwari Sugars Limited, Regd. Office 37/1, Ulsoor Road, Bangalore-560042 (KN/5710) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2325 dated the 6-5-83 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 21-7-1986 upto and inclusive of 20-7-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where, any amendment is likely to affects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/130/83-PF-II (SS-II)]

का.आ. 1928 —मैसर्स दी एसोसिएटिड सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेड पो.आ. शाहाबाद ए.सी.सी. 582229 जिला-गुलबर्गा (के.एन./154) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2323 तारीख 6-5-83 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 21-7-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 20-7-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/128/83-पी. एफ.-2/एस. एस.-2]

S.O. 1928.—Whereas Messrs, The Associated Cement Companies Limited, P.O. Shahabad, ACC-585229, Gulbarga Distt. (KN/154) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2323 dated the 6-5-83 and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for further period of three years with effect from 21-7-1986 upto and inclusive of the 20-7-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(128)/83-PF-II/SS-II]

का.आ. 1929.—मैसर्स एसोसिएटिड सिमेन्ट कम्पनीज लिमिटेड लखेरी सिमेन्ट वर्क्स पो.आ. लखेरी (राजस्थान) 323603 (आर.जे./1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2327 तारीख 6-5-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 21-7-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 20-7-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे

लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिति/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/127/83-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1929.—Whereas Messrs, Associated Cement Company Limited, Lakhari Cement Works, P.O. Lakhari (Rajasthan)-323603 (RJ/1) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976(hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2327 dated the 6-5-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 21-7-1986 upto and inclusive of the 20-7-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Whereas, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/127/83-PF-II (SS-II)]

का.आ. 1930 —मैसर्स श्री राम फाइबर्स लिमिटेड थीरु बिल्डिंग 160, ग्रीयम्स रोड, मद्रास-600006 (टी. एन./9227) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1926 तारीख 8-4-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 23-4-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 22-4-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसे विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना

हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/117/83-पी.एफ.-2 एस०एस०-2]

S.O. 1930.—Whereas Messrs. Shri Ram Fibres Limited, Thiru Building, 160 Greams Road, Madras 600006. (TN/9927) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1926 dated the 8-4-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 23-4-1986 upto and inclusive of 22-4-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where, any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/117/83-PF-II(SS II)]

का. आ. 1931 —मैसर्स दी कोइम्बाटूर सेन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोइम्बाटूर-18(टी.एन./4159) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952(1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3494 तारीख 18-9-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 2-10-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 1-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3 क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एम-35014/82/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1931.—Whereas Messrs. The Coimbatore Central Co-operative Bank Limited, Coimbatore-18 (TN/4159) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3494 dated the 18-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 2-10-1985 upto and inclusive of 31-10-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendement of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where an yamendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/82/82-PF. II (SS. II)]

का.आ. 1932 —मैसर्स जे.के. इन्डस्ट्रीज लिमिटेड जे.के. ग्राम पो.आ.कन्करोली, जिला-कन्करोली (आर.जे./2601) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2084, तारीख 18-4-83 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 7-5-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 6-5-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014(75)/82-पी. एफ.-2(एस. एस.-2)]

S.O. 1932.—Whereas Messrs. J. K. Industries Limited J. K. Gram, P.O. Kankroli, District—Kankroli, (RJ/2601) (hereinafter refetred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hecrinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2084 dated the 18-4-83 and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for further period of three years with effect from 7-5-1986 upto and inclusive of the 6-5-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of this majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/75/83-PF-II (SS-II)]

का.आ. 1933.—मैसर्स मुकुन्द आईवन एन्ड स्टील वर्क्स लिमिटेड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, कुरला, बम्बई-40 (एम.एच/43 और 44) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2014 तारीख 14-4-1983 के अनुसरण में और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 30-4-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 29-4-1989 भी सम्मिलित है उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्रा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा—17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्रा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश भारतीय जीवन बीमा निगम नियोजक द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014 (67)/83/पी एफ 2 एस. एस.-2]

S.O. 1933.—Whereas Messrs. Mukund Iron and Steel Works Limited, Lal Bahadur Shastri Marg, Kurla, Bombay-400070 (MH/43 & 44) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2014 dated 14-4-83 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for further period of three years with effect from 30-4-1986 upto and inclusive of the 29-4-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his aproval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased members entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(67)83-P.F. II-SS-II]

का.आ. 1934 —मैसर्स ग्वालियर रेयन सिल्क मैनूफक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी लिमिटेड गोसी लेन डिविजन वर्क्स, कुमापारिटनम (हरिहर) जिला धारवार (के.एन./7474) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का

संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम) 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2013 तारीख 14-4-1983 के अनुसरण में और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 30-4-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 29-4-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पटट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(66)/83-पी.एफ.-2/एस. एस-2]

S.O. 1934.—Whereas, Messrs The Gwalior Rayon Silk Manufacturing (Weaving) Company Limited, Grasi lane Division Works, Kumarapatinam—581123 (Harihar) Dharwar District, Dharwar (KN/7474) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any sepaarte contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2013 dated the 14-4-83 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for further period of three years with effect from 30-4-1986 upto and inclusive of the 29-4-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits aavilable to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(66)/83-PF. II SS-II]

का.आ. 1935.—मैसर्स भारत कामर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, राजपुरा, पंजाब (पी.एन./2199) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1707 तारीख 12-3-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 26-3-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 25-3-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया

जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक, कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशितो/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/48/83-पी.एफ.-2-एस०एस०-2]

S.O. 1935.—Whereas Messrs. Bharat Commerce and Industries Limited, Rajapura, Punjab (PN/2199) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of sectio n17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1707 dated the 12-3-83 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for further period of three years with effect from 26-3-1986 upto and inclusive of the 25-3-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits

available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Schemes are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/48/83-P.F. II(SS-II)]

का.आ. 1936.—मैसर्स देहली स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड 31, नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002 (डी.एल/1834) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचरी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 930, तारीख 22-1-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 12-2-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए, जिसमें 11-2-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, देहली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है के अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(8)/83-पीएफ II-एस एस-2]

S.O.1936.—Whereas Messrs. Delhi State Co-operative Bank Limited, 31, Netaji Subhash Marg, Daryaganj, New Delhi-110002, (DL|1834) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 930 dated the 22-1-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provision of the said Scheme for a further period of three years with effect from 12-2-1986 upto and inclusive of the 11-2-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any, reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|8|83-PF-II (SS-II)]

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1986

का. आ. 1937:—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पहली मई 1986 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

"जिला मयूरभंज के निम्नलिखित राजस्व ग्रामों में आने वाले क्षेत्र—

1. बारीपाडा के नगरपालिका क्षेत्र के बाहर तथा शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत छांचा।
2. बारीपाडा के नगरपालिका क्षेत्र के बाहर तथा शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत हेमचन्द्रपुर।
3. बारीपाडा के नगरपालिका क्षेत्र सहित बारीपाडा।
4. बारीपाडा के नगरपालिका क्षेत्र, बाहर तथा शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत बाजय राम चन्द्रपुर और
5. बेटनाटी तहसील के अन्तर्गत कठपाल।

[संख्या एस-38013/16/86-एस.एस.-I]

New Delhi, the 25th April, 1986

S.O. 1937.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st May, 1986 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Orissa namely :—

"The areas comprised of the Revenue villages of

(1) Chhancha out of Municipal area and within the Urban area of Baripada;

(2) Hemchandrapur out of Municipal area and within the Urban area of Baripada;

(3) Baripada including the Municipal area of Baripada;

(4) Bajay Ram Chandrapur ou of Municipal area and within the Urban area of Baripada; and

(5) Kathpal under Betnoti Tehsil in the District of Mayurbhanj."

[No. S-38013/16/86-SS-I]

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1986

का. आ. 1938:—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पहली मई, 1986 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

"नार्थ आरकोट जिले में वेल्लोर तालुक के

करुगमबाथुर राजस्व ग्राम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"।

[संख्या एस-38013/15/86-एस.एस.-I]

ए. के. भट्टराई, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

S.O. 1938.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st May, 1986 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except ub-section (1) of section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu namely :—

"The areas comprising Karugambathur Revenue Village of Vellore Taluk in North Arcot District."

[No. S-38013/15/86-SS-I]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

का. आ. 1939.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-4-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1939.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947, the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure in Central Bank of India Chandigarh and its employees which was received by the Central Government on the 11th April, 1986.

ANNEXURE

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL,

CHANDIGARH

Case No. I.D. 34/83 (Chandigarh) I.D. 73/83 (Delhi)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Bank of India.

AND

Their Workman : B. K. Bhambari

APPEARANCES :

For the Employers—Sh. Yogesh Jain.

For the Workmen—Sh. Mangat Sharma.

ACTIVITY : Banking STATE : Chandigarn.

AWARD

Dated the 8th of April, 1986

1. The Central Government Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947, as per their Order No. L-12012/(183)/80-D.II(A) dated 19 February, 1982 read with vide Order No. S.O.S. 11025(2)/dated the 8th of June, 1983 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the Central Bank of India in depriving Shri Bhambari, B.K., Asstt. Cashier-cum-Godown Keeper, Chandigarh from the posting/promotion as Head Cashier Category 'C' on opening of Extension Counter at Chandigarh on 19-10-79 is justified ? If not, to what relief the workman is entiled to ?"

2. According to the petitioner-workman he had joined services of the Respdt. Bank as an Asstt. Cashier-cum-godown Keeper w.e.f. 8-8-69, but on account of his higher eructional qualification was given notional seniority w.e.f. 8-8-67

Gradually he gained in seniority and by the time of preparation of the seniority list in the Selection Area of Chandigarh was fixed up at the top on 1-9-1979. It was avered that in accordance to the Promotion policy Settlement dated 20-12-1975, the petitioner was entitled for promotion to the rank of Head Cashier category 'C' and 'E' against the rst available vacancy; that such a vacancy did arise at the time of opening an Extension Counter in Sector-32, Chandigarh w.e.f. 19-10-1979, but for no ryhme or reason the management over looked his claim and deprived him of his right to promotion; On the other hand they offered him promotion at Vazra Canteen Extension Counter at Jullunder w.e.f. 28-11-1979. Feeling aggrieved the petitioner represented agaisnt the injustice but the management was found unresponsive despite the intervention of the A.L.C. (C) at the Conciliation stage, hence the reference.

3. Resisting the proceedings, the mangement denied the allegations of any bias or prejudice against the petitioner and avered that as a matter o fact he was interested in promtion on his own terms because he did not wane to go out of Chandigarh. Eleborating their version the mangement disclosed that in enticipation of certain departmental shiftings and transfers, on 10-9-1979 the petitioner sent representation to them that he was not interested in promotion and that was how that they had to make a timely arangement for posting some body at the Extension Counter Sector-32 Chandigarh since the same was likely to be operative w.e.f. 19-10-79. However when the petitioner came to know that a promotion post could be available at Chandigarh also, he made an application on 18-10-79; i.e. only a day before the opening of the Extension Countery expressing his desire to withdraw his earlier representation so that he could grab the Chandigarh posting as well as promotion.

4. The mangement further pleaded that even though under the Promotion Policy the petitioner should have been disqualified for promotion right at the time of his earlier reference dated 10-9-1979 yet they were graceful enough to offer him the promotion at Vazra Cantonment Extension Counter Jullunder n November, 1979 but he again declined the offer and vide his Letter dated 6-12-1979 expressed unwillngness to go out of Chandgarh. It was n vew thereof that per ther order dated 12-12-1979 they had to place 36 months' embarge on hss promoton n terms of Clause 1.51 of the Promoton Policy.

5. In support of hs case the pettoner examned hmself whereas the management produced their former Chief Manager (Personnel) Shri B. N. Kapoor. Of course both the parties filed a number of documents also whose authenticity was not disputed from either side.

6. On a careful scrutiny of the entire available date and hearing the parties I ans not inclined to sustain the petitioner"s cause since, by hs own act and conduct, he had forfeited his right to promotion at the relevant time. A bare persual of hs letters Ex. M1 dated 10-9-1979 and Ex. M11 dated 6-12-1979 would leave no manner of doubt that he was concerned with his promotion only to the extent of ensuring his continuous stay at Chandigarh where he was holding a Junior post for quite some time.

7. On behalf of the Petitioner it was straneously argued that Extenson Counter Sector 32 Chandigarh was opened w.e.f. 19-10-1979 and prior to that he had already called upon the Management to ignore his previous letter dated 10-9-79: moreover by then he had not received information from the management regarding the acceptance of his "surrender", In the same sequence it was argued that subsequent offer of promotion posting at Jullunder made to him by the management per thetir Letter Ex. M3 and M4 dated 28-11-1979 was declined by him because they had over looked his claim for retrospective promotn frm 19-10-79 when one of his junior was fixed up at the Extension Counter Sector 32 Chandigarh.

8. Despite seeming attraction, the submission failed to carry conviction with me because I am convinced that he was trying to have best of both the worlds. There is no gain saying that as and when Extension Counters are opened for various because of the routine system of working after all some premises has to be hired, furniture has to be arranged and the exercise for the selection of the staff has also to be gone through. Obviously the petiioner must have got the scent when the Extension Counter was proposed for Chandigarh where he could claim promotion posting by virtue of his seniority and that was the pracise reason that he withdrew his previous letter dated 10-9-1979 only a day before the opening of the Extension Counter.

9. Otherwise also on his behalf there is absolutely no explanation as to under what circumstance or for what particular reason he had given up his right to promotion by sending the relevant surrender note. The management's reluctance in passing a formal order of his debarment rather shows their sense of mananimity that they did not want to be harsh with him, but all the same they could not possibly play to his tune at the cost of his junior colleagues.

10. Despite all this as and when the next oportunity arose in a few weeks time they again offered him a promotion posting which he declined on raising abolutely irrelevant and frivilous objection that he should have been posted at Extension Counter Sector 32 Chandigarh and given promotion from the particular date when the said Counter started operating. The crowing glory is that in the concluding part of his letter Ex. M11 dated 6-12-1979 he came out in true colours by asserting that he was interested for promotion only at Chandigarh and not otherwise.
esa"

11. Hence for the reasons recorded above on sustaining the mangement"s view point I return my award against the petiioner-workman.

Chandigarh.

Dated : 8-4-1986.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer.

[No. L-12012/183/80-D.II(A)]

का. आ. 1940.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, कनारा बैंक, बंगलौर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16 अप्रैल, 1986 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 1940.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government nereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure in the industrial dispute oetween the employers in relation to the Canara Bank, Bangalore and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th April, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN KARNATAKA BANGALORE

Dated this the 7th day of April 1986

PRESENT :

Sri R. Radhakrishna, B.A., B.L., Presiding Officer.
Central Reference No. 3 of 1986

I Party

Shri G. Thyagaraj, No. 5, 8th Street, G.P.R. Road, Bangalore-560051.

II Party

The Chairman-cum-Managing Director, Canara Bank, No. 112, J. C. Road, Bangalore-560002.

APPEARANCES :

For the I Party—Sri O. Sreedharan, Advocate, Bangalore

For the II Party—Sri S. S. Ramdas, Advocate, Bangalore.

REFERENCE

(Government Order No. L-12012/156/84-D.II (A) dated 7-3-85)

AWARD

The Central Government being of the opinion that an Industrial Dispute exists between the above parties has referred this dispute for adjudication in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section 1 of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Canara Bank in relation to their Kodemballi Branch in terminating the services of Shri G. Thyagaraj, w.e.f. 25-10-77 is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. The I Party workman who has been represented by an Advocate has filed his claim statement contending thereon that he was appointed as a temporary peon on 1-12-1972 and posted to P and D zone, Head Office. He has been transferred to Eastern zone on 11-12-1972. Thereafter he has been appointed as a probationary peon on 7-2-1973. He has been further informed on 9-2-1973 that he will be treated from 7-2-1973 as the date of his joining to the bank for all purposes.

3. He has further contended that by a proceedings dated 17-5-1973 he has been again transferred from Eastern zone to Central zone. He was confirmed as peon in a proceeding dated 20-7-1973 with effect from 7-8-1973. From there he has been transferred to Kodamballi Branch and he began working there.

4. He has further contended that since he was not feeling well on 24-10-1977 he has applied for two days leave for 25th and 26th and left for home at Bangalore for treatment. Due to sudden and unexpected death of his father his illness became acute and he has developed some sort of mental depression and he lost mental awareness and did not understand what was happening to him. He was under treatment for rheunatism till 28-2-1978 and he was declared fit for duty with effect from 1-3-78.

5. He along with medical certificate went to Kodamballi branch for reporting to duty, but the Manager told him that he should have reported to duty on or before 27-2-1978 as per the orders of the II Party and therefore, he could not take him to duty without orders from the head office. Due to this the I Party had to return home. He has further contended that before he ascertained that he could submit a representation regarding reasons for not reporting to duty on or before 27-2-1978 the II Party issued the termination order No. BSS/10980/B-13, dated 18-3-1973 stating that the I Party was deemed to have voluntarily abandoned the services of the bank from 26-10-77 after office hours. He has further contended that thereafter he submitted a representation to the board of directors on 13-4-78, but there was no response He has again submitted a representation dated 3-8-1981 to the Chairman and Managing Director explaining the circumstances under which he has overstayed. After all his attempts failed to move the II Party he has approached the Assistant Labour Commissioner with a petition dated 9-4-84 under Section 3-A of the Act.

6. He has further submitted that there was nothing in the surrounding circumstances indicating or suggesting an intention on his part to abandon service, which would have been permitted an inference that he has voluntarily abandoned services and hence the action of the II Party is arbitrary illegal and is liable to be sent aside. He has not been given a reasonable opportunity to show cause why he did not report to duty on or before 27-2-78 and hence the termination without complying with the minimum principles of natural justice is unjustified and further his termination amounted to retrenchment and the same is liable to be set aside and there shall be an order for reinstatement with all back wages and other benefits flowing therefrom.

7. The II Party have filed their counter statement and thereby contended that the reference is illegal, bad and without jurisdiction as the I Party who was working as a peon applied for casual leave for two days and did not report for duty as required nor he submitted any leave application. He has remained absent unauthorisedly from 27-10-77 without any intimation. The I Party was thereafter called upon by the II Party by its letter No. BSS/46/333-B.13 dated 28-12-77 to report for duty on or before 4-1-78 informing him that if he fails to do so his services could be deemed to have been voluntarily abandoned and the I Party has refused to receive this letter.

8. The II Party thereafter wrote another letter dated 18-2-78 requiring the I Party to report for duty on or before 27-2-78 and give reasons for unauthorised absence. It was also informed that in case he fails to report for duty and give reasons for the absence, it would be deemed that he had no intention of continuing in the services and that he would be considered as having voluntarily left the services of this II Party. A copy of this letter was also displayed on the notice board of the II Party at its Kodamballi Branch. The I Party received this letter, but failed to report for duty nor did he offer any explanation. Thereafter the II Party published a notice in Daccan Herold newspaper dated 22-2-78 calling upon the I Party to report for duty and explain the unauthorised absence. It was also made clear that if fails to report within the stipulated time it would be deemed that he had voluntarily abandoned the services of the II Party. Inspite of this, the I Party failed to report for duty nor offer any explanation hence the II Party at its proceedings 18-3-78 considered the whole case and recorded that the I Party had voluntarily abandoned the services and they had no other choice but to take such an action. There was absolutely no correspondence from I Party about his absence and having regard to the long lapse of the II Party was well within its rights to presume that the I Party has voluntarily abandoned his services and there are absolutely no grounds to interfere with the action of the II Party.

9. It is further contended that the II Party have not terminated the services of the I Party but it is a case of voluntary abandonment of service. It is evident from the above facts that the Government has not applied its mind in referring the matter as one of termination and therefore the reference is liable to be rejected. The reference is also bad as more than nearly eight years elapsed since the I Party ceased to be an employee of the II Party. This long delay has seriously prejudiced the case of the II Party and for this reason also, the reference is bad.

10. The management after traversing the various allegations made in the claim statement have further contended that the past record of the I Party has shown that he was in the habit of remaining absence for long period and infact during his service the I Party had remained absent for 402 days on loss of payment they prayed for rejecting the reference.

11. The I Party along with his claim statement has also filed an application for Interim Relief. When the objections for the main petition and for this interim relief application was filed by the II Party the case was posted to bear on the interim application. However, the II Party made it clear that they will rendered all possible co-operation to dispose the main dispute at the earliest. Due to this submission the case was adjourned to record the evidence of the II Party on the merit of the case. Due to this no additional issues have been framed, due to the contentions raised by the II Party that it is a case of abandonment of service by the I Party and due to this the II Party had no other option except to terminate the services of the I Party after observing all legal formalities.

12. Now the issues that arises for determination are :

1. Whether the II Party are justified in terminating the services of the I Party workman with effect from 26-10-77 ?

2. Whether the order of termination is disproportionate to the act committed by the I Party workman ?

3. What award ?

Issue No. 1.—To prove this issue the II Party have examined the Manager of their bank and closed their evidence. This witness has deposed that during 1977 the I Party who was working at Kodamballi Branch in Kolar District has applied for two days casual leave on 25-10-77 and 26-10-77 and he was required to report for duty on 27-10-77. The I Party has not reported for duty and continuously absent without

any leave application hence the Circle Office sent a letter to the I Party dated 28-12-77 as per Ext. M-1. The postal cover containing that letter has returned with an endorsement "Refused" as per Ext. M-2 and M-2 (a). It was directed in Ext. M-2 that he should report for the duty on or before 4-1-78. He has further deposed that thereafter they have written another letter dated 18-2-78 as per Ext. M-3 calling upon the I Party to report for the duty on or before 27-2-78. This letter was sent under R.P.A.D. and a copy was also displayed in the notice board at Kodamballi Branch. They have not received the acknowledgement or the cover nor the I Party reported for duty. They have also given a notice in Deccan Herald newspaper on 22-2-78 asking the I Party to report for duty as per Ext. M-4 and M-4 (a). Due to some mistake they have issued a corrigendum as per Ext. M-5(a) and Ext. M-6 and M-7 are the bills having paid for the printing charges.

13. He has further deposed that on 18-3-78 the General Manager of the Bank has considered the case of the I Party and recorded that the I Party had voluntarily abandoned the service of the bank as per Ext. M-8. This letter was sent to the I Party by R.P.A.D. and though he acknowledged as per Ext. M-8(a), he has never approached the bank nor reported for duty upto the date of proceedings i.e. 18-3 78.

14. He has further deposed that from 1973 to 1977 the I Party has taken 400 days, under loss of pay and also utilised 20 days under permissible leave category. In this regard, 3 warning notices were issued to the I Party and Ext. M-3 is the leave card of the I Party. He has further deposed that the I Party has not informed nor sent any communication to remain absent after 26-10-77. There is a provision in Bi-partite settlement that if a workman absents himself continuously for 90 days without any sanction or permission is deemed to have voluntarily abandoned the services. In view of the past records of the I Party the bank is not willing to take him back.

15. It is elicited in his cross-examination that except the communications mentioned above the bank has not made any personal efforts to contact the I Party. He had no information of having the I Party approaching the Branch Manager but the bank has received a letter addressed on 13-4-78 as per Ext. W-1. It is further elicited that the I Party has given representations on 3-7-81 as per Ext. W-2 and on 5-3-81 as per Ext. W-3. He has denied having any knowledge of I Party approaching the Branch Manager on 1-3-78 along with his fitness certificate. They have also not issued one month's notice under retrenchment compensation as his case is abandonment of service.

16. To rebutt this evidence the I Party inspite of several opportunities given by this Tribunal has not chosen to examine himself in support of the claim statement made by him. In view of this, this Tribunal has closed the evidence of the I Party on 26-2-86 and posted the case to 15-3-86. The I Party or his counsel have not appeared even on that day then again the case was posted to 22-3-86 and the counsel for the II Party has addressed the arguments on the merits of the case.

17. The learned counsel for the II Party Sri S. S. Ramdas after summarising both oral and documentary evidence placed by them, has submitted since the wear abouts of the I Party workman was not known from 27-10-77, the bank has left with no option then issued notices calling upon the workman to report for duty in accordance with the rules and natural justice. The counsel further submitted that admittedly the first notice was refused by the workman has endorsed by the postal authorities, then the management have once again issued a notice on 18-3-78 and also published this fact in the local newspaper as per Ext. M-4 and M-5. Since the I Party workman has not reported for duty the II Party have compelled to pass on order as per Ext. M-8 on 18-3-78 and this fact was communicated to the I Party which he has acknowledged as per Ext. M-8(a). Hence all legal formalities has been applied by the II Party before terminating the services of the I Party workman for voluntary abendonment of service. The learned counsel brought to the notice of this Tribunal, the memorandum of settlement entered between the Indian Banks Association and their workmen and he drew the reference of the Tribunal to serial No. 16 of the Memorandum of Settlement at page No. 62.

18. The item No. 16 of the settlement reads as follows : Voluntary Cessation of Employment by the Employees.

> In Supersession of Clause 2 of the Settlement dated 8th September 1983 the following shall apply ;
>
> Where an employee has not submitted any application for leave and absents himself from work for a period of 90 or more consecutive days without or beyond any leave to his credit or absents himself for 90 or more consecutive days beyond the period of leave originally sanctioned or subsequently extended or where there is satisfactory evidence that he has taken up employment in India or the management is satisfied that he has no present intention of joining duties the management may at any time thereafter give a notice to the employee's last known address calling upon the employee to report for duty within 30 days of the notice, stating, inter alia, the grounds for the management coming to the conclusion that the employee has no intention of joining duties and furnishing necessary evidence, where available, unless the employee reports for duty within 30 days or unless he gives an explanation for his absence satisfying the management that he has not taken up another employment or avocation and that he has no intention of not joining duties the employee will deemed to have voluntarily retired from the Bank's service on the expiry of the said notice.

19. On a perusal of the cross-examination made by the counsel for the I Party and the documents relied by him Ext. W-1 is a representation sent by the I Party workman dated 13-4-78 long after the receipt of the termination order Ext. M-8. Though the I Party has contended that he has been prevented to attend the duties due to his continuous illness and also due to the death of his father he has not placed any material to substantiate the same. The past records of the I Party as per Ext. M-9 discloses that he was irregular for the duties from the beginning of his employment. The II Party have afforded several opportunities for the I Party workman to report for his duty in accordance with law but the I Party has failed to report for duty nor he has sent any communication about his illness to the II Party. Hence I am compelled to hold this issue in the affirmative.

Issue No. 2.—The learned counsel for the II Party has submitted that there is unreasonable delay in making reference of this dispute as the I Party has abandoned his service during 1978 and this reference has been made during 1985 after a lapse of 7 years. He has further submitted that since the workman has stated in his claim statement that he has lost his mental awareness and also due to the fact that he was very irregular in his career the bank is not willing to provide an employment to such a person in the interest of the activities of the bank.

20. Now coming to the facts of this case though the I Party workman is himself responsible for making the II Party to take such a coercive steps. He has reiterated the fact of his physical and mental disability to report for the duty before the order of termination. It is also to be seen that the I Party gave a representation on 13-4-78 and when he has not received any communications by the II Party, he again sent the representation on 5-3-81 and 3-7-81. It is admitted that the II Party have not replied to these representations and they have lent deafears. It was opened for the bank to consider his representation dated 13-4-78 treating his absence as leave without wages and consequently they would have conducted a domestic enquiry and give some minor punishment to the I Party workman. Since this Tribunal feels that the order of dismissal is disproportionate to the act committed by the I Party workman, acting under Section 11-A of the Industrial Disputes Act, the award of some compensation to the I Party workman will meet the ends of justice.

AWARD

The reference is partly allowed and in lieu of reinstatement of the I Party workman a sum of Rs. 15,000 is awarded as a compensation payable by the II Party within 15 days from the date of publication of this award. The parties shall bear their own costs.

(Dictated to the Stenographer, transcribed and typed by her and corrected by me.)

R. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

[No. L-12012/155/84-D.II (A)]

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1986

का.आ. 1941—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार, स्टेट बैंक आफ पटियाला के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करता है, जो केंद्रीय सरकार को 11-4-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, 28th April, 1986

S.O. 1941.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of Patiala and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th April, 1986.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I. D. 48 of 1984 (CHD); I. D. 5 of 1981 (DELHI)

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of Patiala, Punjab.

AND

Their workman ; Rattan Chand Aggarwal

APPEARANCES :

For the Employers—Shri I. D. Gupta.

For the Workman—Shri Tara Chand Gupta.

ACTIVITY : Banking STATE : Punjab

AWARD

Dated the 7th of April, 1986

The Central Government, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under sectinon 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, per their Order L-12012 (37)/79-D.II (A) dated 13th January, 1981 read with S.O. No. S-11025(9)/84-D.IV (B) dated the 26th of October, 1984 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of State Bank of Patiala in discharging Shri Rattan Chand Aggarwal, Ex. Head Cashier of Bhawanigarh Branch of the Bank from the services of the Bank with effect from 22nd July, 1977 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. To trace a short history of the matter, in June 1975 the petitioner was working as Head Cashier at Bhiwani Garh Branch of the Respondent Bank which was subjected to a surprise audit by Shri H. S. Tulsi on 16th June, 1975; that it was a public holiday on the preceding day i.e. 15th June 1975 and as such the verification of the Cash balance had to be done as it existed on the closing of 14th June 1975. On physical verification by the Auditor a shortage of Rs. 6,500 in different bundles of Rs. 100 denomination was detected. To precise, the cash in hand according to the record should have been Rs. 1,85, 281.80 p. whereas it was actually found to be Rs. 1.78, 781.08 p. On verbal inquiry the petitioner explained the shortage on account of an urgent but late withdrawl which was affirmed by the Branch Manager Shri B. S. Khosla. But all the same there was no document available to justify the withdrawl. However the petitioner immediately arranged the amount and informed the Auditor that as a matter of fact shortly before the closing time on 14-6-1975 on old Account Holder had requested for the withdrawl which was allowed by him to maintain the Branch's good will because of the high credibility of the concerned Account holder and that the said Account Holder had then sent in the money for deposit when the Audit Inspection was still under progress.

3. In view of the fishy nature of events the Auditor obtained a written confession from the petitioner and submitted it to the Head Quarters alongwith his own report. In due course, the petitioner was placed under suspension and charge sheeted for the alleged mis-appropriation. Since the petitioner's reply to the charge sheet was not found satisfactory, therefore, he was put on a regular departmental inquiry in which he was held guilty. On the basis of the findings of the Inquiry Officer the Disciplinary Authority called for the petitioner's explaination and also issued him a show cause notice for dispensing with his services. On petitioner's failure to submit a satisfactory reply the Disciplinary Authority passed an order of dismissal on 21-7-1977 feeling aggrieved against which he moved a service appeal to the General Manager (Operation), who on reducing the punishment converted the "Dismissal" into a simple "Discharge".

4. But the petitioner was not contended with the propriety and legality of the management's action and so he raised an issue on the plea that he was quite innocent and victim of circumstances.

5. However the matter could not be settled amicably between the parties despite the intervention of the A.L.C. (C) at the Conciliation stage and hence the reference.

6. For the obvious reasons, the petitioner impugned the validity of the inquiry proceedings on all conceivable grounds, even though the management asserted that the same were conducted in a free and fair manner in which the petitioner had fully participated, and availed of due opportunity to demolish the "Charges" as also to project his own defence.

7. In support of his case the petitioner examined himself whereas the management produced the Inquiry Officer Shri J. N. Verma and another officer Shri Harnam Singh Sohal. Of course both the parties also filed a number of documents whose authenticity was not disputed from either side.

8. During the course of hearing before me a suggestion was floated to the management for giving a second thought to their action in view of the compassions involved; after all the petitioner was one of their tried soldier who had spent the better part of his life in their service without any blemish. The relevant incident dated 16-6-1975 could be one momentary aberration in an otherwise untainted career; and that too was rectified right on the spot without any lose of time. In short, even though the petitioner might not be completely absolved or guilt, yet his lapse did not cause any monetary loss to the Bank.

9. It was therefore, suggested that he be re-instated without any backwages and that the intervening period could be frozen as "dies-non". In all fairness, the management was not found averse to the proposition of an amicable settlement, but it expressed a serious reservation on the point of petitioner's re-employment which, to my mind, was not devoid of force. It was argued that Banking industry is primarily a service-oriented activity which discharges a sort of public trust with letter's money; and that every now and then the employees have to handle huge amounts of cash, more so when one is posted on a sensitive seat like the petitioner's; therefore, in the very nature of things the management could not gamble on the re-instatement of a person who had lost his credit and betrayed questionable propensities.

10. The petitioner then offered to withdraw his claim provided the management was willing to give employment to either of his two some one of whom was under matric and other under-graduate; but in such event he wanted to be compensated with some cash amount because of the enormous expenses incurred by him on this protracted litigation. The management responded with a sense of magnanimity but requested the Tribunal to spare it of any financial implications.

11. In my considered opinion in the totality of the circumstances the petitioner's offer deserves to be approved as reasonable, fair and just to both the sides. It may be worthwhile to mention here that even according to the findings of the Inquiry Officer, the deficiency of Rs. 6,500 had been made up on the spot even though its withdrawl on the preceding working day was irregular and violative of the Banking norms. The Branch Manager who had also supported the petitioner's cause was not even subjected to any departmental inquiry inspite of the fact that he could be equally responsible for the alleged deficiency in the case because the withdrawl was allowed by the petitioner with his tacit consent. And to crown it all the petitioner's confessional statement to the Auditor was held to be a procured and extorted one. It is an entirely different thing that ultimately the petitioner was condemned because of his own admission before the Inquiry

Officer on the point of irregular withdraw and deposit. But it was perhaps, in view there of that his dismissal was changed to "discharge" on service appeal.

12. I, therefore, strike a balance and an sustaining the Inquiry Officer's findings to the extent of petitioner's gulity, set aside the order of punishment and substitute the same with my following Award :

(a) One of the petitioner's son who is an under matric shall be given appropriate employment in the Bank's regular cadre with immediate effect subject, of course, to his passing the medical fitness test ;

(b) An ex-gratia amount of Rs. 10,000 (Ten thousand) shall be forthwith paid to the petitioner.

(c) The petitioner's disengagement shall be deemed to be one without any stigma and as such he would be accorded all the terminal benefits like Gratuity, and refund of Provident Fund etc. as available on the date of his aforesaid "discharge".

[No. L-12012/37/79-D.II(A) (Pt.)]

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

का.आ. 1942—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार, यूनियन बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केंद्रीय सरकार को 11-4-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1942.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th April, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM LABOUR COURT KANPUR

Reference No. L-12012/235/83-D.II (A) dated 6-2-1984

Industrial Dispute No. 15 of 1984

In the matter of dispute between :

S/Shri A. K. Srivastava and Pratap Shukla C/o The Deputy General Secretary, Union Bank's Employees Union U.P. 26/11-A Patkapur, Kanpur.

AND

The Assistant General Manager, Union Bank of India Hotel Awadh Clerks, Hazaratganj, Lucknow.

APPEARANCES :

Shri S. N. Mehra—for the management.

Shri V. N. Sekhari—for the workman.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-12012/235/83-D.II (A), dated 8th February, 1984, has referred the following dispute for adjudication :

Whether the action of the management of Union Bank of India, Zonal Office, Lucknow in relation to their Sarvodaya Nagar, Branch Kanpur in superseding S/Shri A. K. Srivastava and Pratap Shukla clerks cum cashier by their junior clerks cum cashier, namely Shri R. K. Awasthi and B. L. Agarwal for promotion to the post of Head Cashier category C is justified ? If not, to what relief is S/Shri A. K. Srivastava and Pratap Shukla entitled ?

2. The case set out on behalf of the workman is that in October, 81, there was vacancies for the post of head cashier at the each branches of the management bank in U.P. including Kaushalpuri and Sisamau branch at Kanpur. To fill the above posts the management invited consent and choice for the said post from senior employees consequently the two workman in question namely S/Shri A. K. Srivastava and Pratap Shukla enquired and in response both of them gave consent and choice for the post of head cashier for Sisamau and Kaushalpuri branches respectively and the same was forwarded to the management's head office. The management without informing the two workman regarding fate of their consent and choice posted S/Shri R. K. Awasthi and B. L. Agarwal on the two above said branches on permanent basis. Thus the management's action ignoring the consent of the workmen is unfair and unlawful hence they too be posted at Kanpur as head cashier with retrospective effect.

3. The management has averred that in a meeting of the management and union held in September, 1978 it was agreed that a circular will be issued calling applications from the eligible employees for the post of head cashier from various branches and appointments will be made on the basis of such requests received. If for a particular branch there are more than one applicant then the senior most applicant will be appointed. It was further agreed that those eligible employees who do not apply in response to the circular will not be barred. Accordingly in 1979 a circular was issued and many of the vacancies were filled in. To fill up the remaining vacancies as also the vacancies at the proposed branches further circulars were issued in July and August 1980. In the meantime, before we could issue the final orders, the General Secretary of UPBEU objected to filling up the vacancies of head cashiers by issuance of a circular as against the provisions in the promotion agreement for filling up of vacancies by offering the same to the senior most eligible employees. In view of above for filling up the remaining 34 vacancies of the head cashier offer was made in October 1981 to the senior most eligible clerk/cashiers seeking their willingness, and in response thereof the workman concerned Shri A. K. Srivastava and Pratap Shukla were asked to give their willingness in the General Secretary Union Bank Employees Union by his letter dated 17-11-81 informed the management that they have no objection if the management decide to fill up the vacancies by issuance of a circular. The management issued a circular in May 82 calling for applications from clerks/cashiers who are willing to work as head cashier category C. Since the above mentioned workmen concerned S/Shri Pratap Shukla and A .K. Srivastava did not apply in response to the circular issued in May 82 as such their cases could not be considered for filling up the posts. Management stresses that one of the workman i.e. Shri Pratap Shukla was the Dy. General Secretary of Union Bank Employees Union and it was on that account that none responed to circular issued in May 82 and that they can not be considered for appointment as head cashier at Kaushalpuri and Sisamau Branch.

4. The Union in its rejoinder averred that the department of personnel Central Office Bombay vide circular letter dated 16-10-81 and 17-10-81 addressed to 102 senior most clerk cum cashiers, including the workmen concerned invited their consent offering a post of head cashier category C at Kanpur in Sisamau and Kaushalpuri branch and the offer was accepted by both the workmen which was sent to the Central Office through the management bank. The petitioner union admits that they informed the management that they had no objection if the management decided to fill up vacancies by issuance of circular and it was no where stipulated that the cases of senior most persons including to the workmen were to be adversely effected in the selection of head cashier for which they had already exercised their option much before the letter of the General Secretary, as referred by the management bank and that the management bank did not inform the workmen concerned about the fate of their acceptance for the post of head cashier cum clerk for Sasamau and Kaushalpuri Branches on the basis of their seniority till they knew about the posting of the junior hand at these branches which was immediately protested by the workmen concerned and it was only on 11 and 12 November when junior hands were posted. The workmen requested the management to scrutinise the position of these postings and offer them the post of head cashier cum clerk in the aforesaid branches On knowing about the issuance of circular No. DP : CZI : 6422/82 dated 24-5-82 from the Central Office the sponsoring union enquired from the local units of the branch if any such circular had

been received and circulated amongst the members of the staff to which the reply of the local management was that no such circular mentions to have been received. Thereaffer, the matter was taken up with the Central Office at Bombay on which the Central Office replied that both the workmen did not apply in response the circular dated 24-5-82 hence they could not be considered. As the said circular of the management dated 24-5-82 was never received in the two branches the deprivement of the two workmen was their genuine and legitimate and just right of being posted as head cashier is illegal and improper and they should be posted as such.

5. The management has filed circular dated 29-1-79 Ext. M-1 whereby applications were invited for the post of head cashiers category C from 88 branches of the management bank including branch at Kalyanpur and Swarup Nagar at Kanpur. The management has also filed letter dated 17-2-81 Ext. M-1 of the General Secretary Shri S. D. Mishra of the Union Bank Employees Union U. P. intimating the management that the union had no objection if the management decides to fill up the post of head cashiers in branches in U. P. States as was being done earlier. The management issued a circular thereafter on 24 May 82 Ext. M-4 whereby applications included invited for the post of head cashier category C included branches Sisamau and Kaushalpuri at Kanpur with a proforma form obtaining in the application in response to that circular, mentioning orders of preference and also mentioning that the applicant is prepared to carry out his transfer permanently to any of the branches in the circular.

6. On the other hand the workmen has filed the offer of appointment Ext. W-1 to Shri Ashok Kumar Srivastava workman offering him promotion as head cashier category C on which the workman himself gave his willingness to work as head cashier to any of the aforesaid branches. A similar offer was made to other workman Shri Pratap Shukla Ext. W-2 which he signed and sent in token of having work as such. The workmen have filed other letter through proper channel Ext. W-3 that despite their offer of willingness to work as head cashier junior Shri B. L. Agarwal and R. K. Awasthi have been posted as head cashier at Sisamau and Kaushalpuri branch without giving any reply regarding their earlier offer. A similar objection was made by Shri Pratap Shukla, and the same is exhibit W-4. On a querry made by Shri S. D. Mishra, General Secretary of the Union Zonal Manager informed him that the Central Office Bombay had informed that as no application of Shri Pratap Shukla was received in response to circular dated 24-5-82, there was no question of considering his name. On that the Kanpur unit of the bank employees union enquired from the branch manager Sarvodaya Nagar if staff circular Central Zone I dated 24-5-82 was received in the branch to which the branch manager informed vide Ext. W-7 that circular dated 24-5-82 does not seems to have been received as the same is not available with their records. The workman Pratap Shukla, Deputy General Secretary of the union requested the Central Office Bombay that the junior members have been appointed ignoring the claim of senior. The management replied per letter Ext. W-9 that postings were made on the basis of seniority and eligibility and that it was made clear in the circular that unless employee applied for the post it was to be deemed that they are not interested and that Pratap Shukla and Ashok Kumar both have not sent the application aforesaid in response to the aforesaid circular. The workman Pratap Shukla vide Ext. W-1 wrote to the head office for their appointment as for no fault of their was ignored as circular dated 24-5-82 was never received in the branch and as such he could not circular it amongst the staff members. The management expressed its inability to post and of the two workmen as the postings of head cashier at Kaushalpuri and Sisamau branch had been done as according to seniority on the basis of the applications received.

7. In support of its contention the management gave affidavit evidence of Shri S. L. Verma, that after discussion with the union it was agreed to issue circular for calling applications for eligible candidates for the post of head cashier consequently a circular was issued in 1979 and large number of vacancies were filled, for remaining vacancies at the proposed branches circular were issued in July/August, 81 true copy of which is Annexure A 1 and 2. Before orders could be issued the general secretary of union bank employee union objected to filling up the vacancies by issuing circulars hence individual offer were made to Shri Pratap Shukla and Shri A. K. Srivastava also meanwhile employees union again intimated per letter Ext. M-3 dated 17-11-81 that they had no objection if the management decides to fill up vacancies by issuance of circular in May 1982 in which workmen Pratap Shukla and A. K. Srivastava did not apply hence they can not be considered.

8. In cross examination the management witness again testified if the workmen B. L. Agarwal and R. K. Awasthi as special assistants were junior to the workmen or not. He has further stated that Ext. M-4 circulated in May 82 must have been received in the office/branch in the ordinary course of communication. In the end he has stated that upto 17-10-81, the management used to get personal offers to the workmen and after that they intrusted offers by circulars. He has admitted that he did not issue notice of 9-A of the I. D. Act or 19.2 of the bipartite settlement. He admits that no individual letter was sent informing the workmen that their records were cancelled for their promotion circular have been issued inviting application for the post.

9. On behalf of the two workmen Shri Pratap Shukla has given his affidavit evidence and appeared in the witness box. In cross examination he has deposed that he has no knowledge if there was any meeting between union and the management bank. He has admitted that in November 1981 general secretary of his union gave no objection certificate to the filling of vacancies of head cashiers by issuance of circular instead of making indlvidual offer and regarding circlar of may 1982, he came to know about it later and he and his colleagues A. K. Srivastava can not apply as that circular was not received in their Sarvodaya Nagar Branch. Kanpur. He has denied specifically that being Dy. General Secretary he has been in the know about that circular in 1982 as that circular was not sent to the union and he came to know only when the posting had been made.

10. It has been argued by the management that Shri R. K. Awasthi and Shri B. L. Agarwal promoted to head cashier category C who have been not made a party to the case as their interest is likely to be affected in case award is given in favour of the workmen. If Shri R. K. Awasthi and B. L. Agarwal were interested they could have applied suo moto or the management applied under section 18(3(B) that they be summoned and heard.

11. The management has drawn my attettention to a ruling Shyam Lal and other Vs. Veersingh and others 1973 Lab IC page 957 Delhi High Court wherein it was held that :

> An award setting aside promotion order without giving notice to the employee being promoted is invalid in as much as it offends the principles of natural justice.

12. I fully agree with the preposition laid down that no one should be condemned unheard, thus there is no question of giving an award disentitling them from promotion or transfering back to any other station which is a propogative of the management only. The only point to be seen is whether the workmen had knowledge of the circular dated 24 May 82 or they deliberately did not apply in the proforma required and as detailed in the said circular. It has come in evidence that no such circular was received at Sarvodaya Nagar Branch for circulation among the senior workmen whom application in the proforma enclosed was invited.

13. As regards workmen Shri Pratap Shukla one of the workmen being Deputy General Secretary of bank employees union must have known about the circular the reply is to be found in his cross examination where he has categorically stated that he had information of the no objection certificate but no of any circular of May 82 as neither the same was received in his branch nor in his union's office. The management has failed to substantiate by filing any acknowledgement that the same was received in the Sarvodaya Nagar, branch and had relied upon general presumption that it must have received in due course. In view of specific denial that it has not reached to the management branch there was no question by the two workmen for giving offer in the proposed proforma application. Further there was no reason for them not to have given such a consent when on an earlier occassion they had given their consent as is evident from Ext. W-1 and W-2 on record. Giving their willingness to be made head cashier category C at any of the branches mentioned therein.

14. In these circumstances it is not the workmen but the management to be blammed for not ensuring that the application reaches to their respective branches. They could have atleast found why no application was sent from Sarvodaya Nagar, Branch when on an earlier occassion senior most employees had applied. The management can not be allowed to take advantage of its own wrong.

15. Under the circumstances of the case and reasons discussed above I hold that the action of the management of Union Bank of India Zonal Office Lucknow in relation to their Sarvodaya Nagar Branch in superceding Shri A. K. Srivastava and Pratap Shukla by not giving them promotion to the post of head cashier category C is not justified.

The result is that the management shall promote the two workmen to the post of head cashier category C from the date of their counter parts Shri R. K. Awasthi and Shri B. L. Agarwal were promoted and give them full benefits of pay of head cashier category C. The management would be at liberty to take work of the promoted post at any of their branches in Lucknow Zone.

16. I, therefore, give my award accordingly.

17. Let six copies of this award be sent to the Government for its publication.

Dated : 4-4-1986.

[No. L-12012/235/83-D.III (A)]

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

का.आ. 1943—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केंद्रीय सरकार को 11-4-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1943.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th April, 1986.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDGARH

Case No. I. D. 29/83 (Chandigarh) I. D. 134/83 (Delhi)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Bank of India.

AND

Their Workman : R. C. Taneja

APPEARANCES :

For the Employers—Shri Yogesh Jain.

For the Workman—Shri Mangat Sharma.

ACTIVITY : Banking STATE : Haryana

AWARD

Dated, the 8th of April, 1986

1. The Central Government, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, as per their Order No. L-12012/104/81-D.II (A) dated 30th January, 1982 read with vide Order No. S.O. 1-11025(2)/83 dated the 8th June, 1983 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Central Bank of India in depriving Shri R. C. Taneja, Assistant Cashier-cum-Godown Keeper, Karnal from posting/promotion as Head Cashier in either of the three extension counters opened after 1-9-79 in Ambala, is justified ? If not, to what relief the workman is entitled to ?"

2. On having joined service as an Asstt. Cashier-cum-Godown Keeper at Karnal Branch of the Respdt. Bank on 15-1-1968 the petitioner had attained considerable seniority amongst his colleagues in the Ambala Selection Area so as to qualify for the next promotion of Head Cashier category 'C' in accordance with the Promotion Policy Settlement. But then he ran into some department difficulties and, as a matter of punishment was required to forgo his promotion for 3 years w.e.f. 9-7-1976.

3. According to the petitioner even though the period of his disqualification ended on 9-7-79 yet he was over looked in favour of his juniors Sarvshri B. N. Sharma and A. K. Bhatia when extension counters were opened at Heigh Lines Ambala Cantt. and S. D. High School Panipat in late August, 1979. He therefore raised an issue and called upon the management to grant him the requisite promotion alongwith its attendant service benefits like the enhanced salary/emoluments. However the management was found unresponsive despite the intervention of the A.L.C. (C) at the conciliation stage and hence the reference.

4. Without raising much of dust on the averments of fact, the management resisted the proceedings on the plea that under the applicable Promotion Policy they had to prepare Seniority list of the eligible candidates on the 1st of March and 1st of September every year and that during the intervening period promotion could be granted (serial-wise) only to those persons who figured in such lists; Elaborating their case they contended that because of his subsisting disqualification on 1-3-1979 the petitioner did not figure in the relevant list till it was revised on 1-9-79 when his name was duly entered therein and on the next available vacancy he was promoted w.e.f. 25-8-1980. Thus according to the management the dispute did not survive any more to warrant any reference by the Appropriate Government in January 1982.

5. In support of his case the petitioner examined himself whereas the management produced their former Chief Manager (Personnel) Shri B. N. Kapoor. Of course both the parties filed a number of documents also whose authenticity was not controverted from either side.

6. On a careful scrutiny of the entire available data and hearing the parties I am inclined to sustain the petitioner's cause because on admitted facts his period of disqualification had expired on 9-7-79 whereas the promotion opportunity arose in the first week of September, 1979 when 3 new Extension counters were opened in the Selection area a one of his junior was granted retrospective promotion w.e.f. 22-8-79.

7. On behalf of the management it was argued that in the terms of Promotion Policy they had to prepare Seniority lists of the eligible candidates every year on the first of March and first of September; that in the case in hand the petitioner's claim could not possibly be included in the list preparation of the next list in September, they had to prepared on first of March, 1979 and that by the time of finalize the posting at the new Extension-counters in advance.

8. I am not amused with the management's view point because neither in Chapter 1 nor in Chapter 10 or 18 of the Promotion Policy there is anything which could empower the management to extend the period of disqualification from the particular date when it was to expire in the normal course. In the absence thereof, I am of the considered opinion that the management was obliged to include the petitioner's name in the list prepared on first of March 1979; of course, with a rider that he would be entitled for promotion only if the chance accrued after 9-7-1979 i.e. on the expiry of the period of debarment and not otherwise. And since the process was not followed by them, therefore, I quash their action and direct them to accord all the monetary benefits of the relevant higher post of Head Cashier to the petitioner from 22-8-79 to 25-8-80.

9. Before parting with the case I would like to record that the learned representative of the management had also raised a technical objection against the validity of the reference with the submission that since the petitioner had already been promoted to the officer cadre w.e.f. January, 1983, therefore he could not claim any relief in these proceedings arising out of the Reference dated 30-1-1982. The submission requires summary rejection because the claim pertains to the period between August 1979 to August 1980 when the petitioner's status of a "workman" as defined in Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, was fairly conceded.

9. Award returned accordingly.

Chandigarh,
Dated : 8-4-1986.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer
[No. L-12012/104/81-D.II (A)]

का.आ. 1944—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1957(1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अधिकरण अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-4-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1944.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th April, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT KANPUR

Reference No. L-12012/256/82-D.II (A) dated 26-6-83
Industrial Dispute No. 213 of 1983

In the matter of dispute between :

Shri Mahendra Singh C/o Shri V. K. Gupta 2/363 Namneir Agra.

AND

The Regional Manager, State Bank of India, Hotel Lauries Agra.

APPEARANCES :

Shri V. K. Gupta—for the workman.

Shri P. K. Gupta—for the Management.

AWARD

1. The Central Government, Miinistry of Labour, vide its Notification No. L-12012/256/82-D.II (A) dated 26-6-83, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

> Whether the action of the management of State Bank of India in relation to its Nunhai Branch under control of Regional Manager, Region Agra in not absorbing Shri Mahendra Singh Sub-staff in the Bank's services and terminating his services on 10-6-1984 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?

2. The case of the applicant is that he was appointed in the management banks Naunhai branch at Agra in November 1973 and for 178 days worked there excluding weekly off and artificial breaks till June 74 when on 10th June 74 his services were abruptly terminated without any notice without any reason or written order. That the bank management appointed guards in the establishment in such a way that no one could complete 240 days of work. That the management appointed other persons later who were absorbed in the service of the bank management permanently. That on representation made by the workman he was again appointed at Naunhai branch in the month of February 1982 for 42 days and in the end he was told not to come in the bank in future. That after his termination new hands were appointed and thus the provisions of section 25-G and H of the I. D. Act were violated. The workman has requested that his termination be declared illegal and he be awarded reinstatement with full back wages.

3. In written statement the management has contested the case of the workman admitting that workman was appointed as banks only at Naunhai branch on various dates in the month of November, 1973 as badli guard till June 1974. According to the details given the workman worked for 184½ days. It is however, denied that he was appointed against any permanent vacancies, that the workman was appointed in leave vacancies or in absence of a regular employee and the management was within its right to remove him when there was no such vacancy. It is further averred that it was not necessary for the management to give any reason or notice at the time of the termination of the services of the workman and that appointments were made according to exigency of work. The management has further admitted that the workman was appointed against purely temporary vacancy in the bank for 42 days in February 82 to June 82 and as per details given he was appointed on 23rd February 82 for 3 days and again in June for 4 days besides four days in March and 20 days in April and 10 day in May 82 in all 41 days and taking the total of work done in 1974 and 74 his total number of working days comes to 225½ days. The management has further averred that infrasement of section 25-G 'H' does not arise as removal of workman does not come within the definition of retrenchment and further he was not entitled to any benefit of reemployment.

4. Parties in the instant case have filed joint inspection report and it appears that after the termination of workman another guard Shri Vikaram Singh was appointed and no appointment or termination letter was available in the bank record nor any seniority list of such badli guards were maintained. It is however admitted that bonus paid to the workman for 73-74.

5. The workman has given his affidavit evidence. In cross examination he has deposed that at the time when he was appointed there were four guards out of whom two were permanent and three were temporary including himself and those who were temporary were working from before and every guard were required to perform 8 hours. He has further stated that there use to be double duty of guard one guard was out side but other remained inside bank and other used to be single guard duty from 5 a.m. to 2 p.m. and other from 2 p.m. to 5 p.m. and thus these used to be dobule guard duty.

6. In the arguments the management admitted that at the relevant time there were four guards working at the branch and the workman was the fifth guard from which it is clear that he was to be engaged when there was a necessity to relive any of the guards. It is common ground that each guard was required to perform 8 hours duty. So according to the management one guard was surplus, but the workman has deposed that from 2 p.m. to 5 a.m. there was double guard duty. In this way four guards were required to be on duty from 2 p.m. to 5 a.m. and for day duty from 5 a.m. to 2 p.m. at least one guard was also necessary thus fifth guard was also required.

7. The workman's representative has drawn my attention to the ruling H. D. Singh versus Reserve Bank of India, 1985 Lab. I. C. page 1733 wherein it was observed thus :

> That the workman offered to work on rotation basis and characterising them as Maidoor as Badlee worker amounts to unfair labour practice.

8. The management has failed to show what was the permanent strength guard at the branch however from the requirements at least four guards were absolutely necessary and fifth

was also necessary to relieve any of them or for completion of double duty between 2 p.m. to 5 a.m. The appointment of workman would not be deemed to be casual or badlee when he was performing regular duty of a guard and would be a temporary workman as he was working in the banking industry as guard.

9. In the present case it is admitted that the workman worked for 173 days from November 73 to June 74 and again for 41 days in 82. It is further admitted from the joint inspection report that another man was appointed after the termination of the workman in question and the workman has not been given 14 days notice as required under para 522(4) of the Sastri Award, thus the termination/retrenchment of the workman concerned would be illegal on this count alone.

10. Further the employment of another person namely Vikram Singh without giving the workman a chance again would be illegal thus the termination of the workman is illegal also on this count for non compliance of rule 25-H of the I. D. Act.

11. The management has taken the plea that the workman was a casual badli guard, but from the joint inspection report it appears that he was paid bonus, this would not have been possible had he not been treated as temporary employees of the bank. The representative for the workman has drawn my attention to the ruling M/s. Hindustan Lever Vs. Their workman 1974 SC Cases L and S page 47 wherein it was observed thus :

> That a post which is likely to continue for an indefinite period is a permanent post.

12. Further in the case of Suresh Narkar Versus FCI 1984 Lab. I.C. page 267 it was held thus :

> Workman engaged for work of permanent nature are not casual workman and after completion of 240 days in 12 consecutive months he would be entitled to be confirmed in service.

13. Thus the management has also violated the provision as mentioned in rule 77 of the I. D. Rules Central as held in the case of Shri Gaffar Vs. Union of India Lab. I. C. 1984 page 645.

14. Thus in any view of the matter the workman having worked 2254 days was entitled to notice, notice pay and retrenchment compensation, and reemployment for violation of above provisions i.e. 522(4) of Sastri Award and industrial dispute rule 77 and provisions of section 25-G of the Act, the workman is entitled to be reinstated in service with full back wages as the termination of the workman was illegal and viod abinitio on the above counts.

15. I, therefore, hold that the action of the management of State Bank of India in relation to its Nunhai branch under control of Regional Manager Region I Agra in not absorbing Shri Mahendra Singh sub-staff in the Bank's services and terminating his services on 10-6-84 is not justified. The result is that the workman be reinstated in service with full back wages.

16 I, therefore, give my award accordingly.

17. Let six copies of this award be sent to the Government for publication.

Dated : 4-4-1986.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012/256/82-D.II (A)]

का.आ. 1945—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार, यूनियन बैंक आफ इंडिया के प्रबंध तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-4-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1945.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947, the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th April, 1986.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I.D. 60 of 1985 (Chandigarh

PARTIES :

Employers in relation to the management of the Union Bank of India.

AND

Their Workman : Sh. Sohan Lal Gupta.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri Gopal Mahajan

For the Workman : Shri B. K. Gupta.

INDUSTRY : Banking. STATE : Haryana.

AWARD

Dated, the 7th April, 1986

The Central Government, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Secion 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 vide their Order No. L-12012/186/84-D.II.A. dated the 22nd of January, 1985 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

> "Whether the action of the management of the Union Bank of India in not promoing Shri S. L. Gupta, Clerk-cum-Cashier at their Kurukhetra Branch, Haryana is justified ? If not to what relief is the workman entitled to and from what date ?"

2. To trace a short history of the matter the petitioner/workman was employed as a Clerk-cum-Cashier in the Respondent Bank since September 1975 and was posted at their Kurukshetra Branch since July 1981. In March 1978 the Bank proposed to fill up ceratin posts of Officer Grade II and in accordance to the promotion Agreement, signed between the management and the employees Federation, 50 per cent of these posts had to be filled up on promotion of the eligible employees on the basis of their seniority; 25 per cent from amongst the eligible Bank employees by subjecting them to a competitive written test and inerview whereas the other 25 per cent were to be filled up by direct recruitment from the outsiders. It appears that there was some further dialouge between the Management and the Employees or as a matter of good-will, the former agreed to allow their clerical staff to compete for the "outsider-quota' also and so much so that even the age ceiling was relaxed for them. Thus there emerged the following three sources of recruitment to the posts of Officer Grade II as enumerated in Clause 4(2); of the Promotion Agreement.

> 4(2)(a) 50 per cent by way of promotion of the eligible employees in view of their seniority.
>
> (b) 25 per cent from amongst the eligible employees who had to participate in the Written test and interview.
>
> (c) 25 per cent by direct recruitment from the "outsider-quota".

3. The petitioner averred that in response to the management's advertisement, he participated in the examination meant for outsider-quota and was placed at serial No. 41 in the relevant Merit List; which for the reasons better known to the management was never published. All the same he came to know that 54 persons were appointed in the Officer-Grade II cadre by way of promotions from the category detailed at point 4(2)(b) of the Promotion Policy; meaning thereby that the management was obliged to recruit an equal number of Grade II Officers from category 4(2)(c) also; It was pleaded that despite petitioners' repeated reminders,

entreaties and even a notice through his Union the management refused to offer him appointment. He, therefore, raised an issue which defied any amicable settlement/dispute or intervention by the A.L.C. (C) at the Conciliation Stage and hence the reference.

4. Resisting the proceedings the management questioned the jurisdiction of the Tribunal to adjudicate upon the dispute because according to them there was no relationship of employer and employee between the parties quo the particular post demanded by the petitioner. Elaborating their version the management explained that since the petitioner had competed in the quota mean for the "outsiders" therefor, he could not seek his remedy as their employee and that otherwise also he could not be promoted under clause 4(2)(c) of the Promotion Agreement which related to the proposition of direct recruitment/appointments whereas his claim was for "promotion" and so much so that even the terms of reference, as made by the Appropriate Government were limited to the point of "promotion" so as to restrict the scope of adjudication by the Tribunal.

5. On merits the Management admitted that the petitioner was their employee, that he had participated in the examination as an outsider in response to their advertisement and was placed at serial No. 41 in the select list but was not offered any appointment in the Officer cadre even though 54 persons were appointed from the category 4(2)(b) pertaining to the employees who had passed out the competitions. However it was explained that they could offer appointments only to 39 successful candidates from the "outsider-quota" by 31st December, 1978 when under orders of the Central Government all further recruitments were taken away from their hands and entrusted to the Banking Service Recruitment Board over which they could not possibly have any control. A preliminary objection was also raised against the validity of the reference with the averment that being an individuald spute it was beyond the pale of Section 2-A of the Industrial Disputes Act 1947, so as to warrant any adjudication.

6. In support of his case, the petitioner examined himself and produced one of his colleague Sunil Kumar Chopra who had also competed in the same examination from the "outsider-quota" alike him and despite being placed at serial No. 21 of the Select-list was not offered the requisite appointment. On the other hand the management examined their Asstt. Supdt. Regional Office Shri P. L. Gairola. Of course both the parties led a number of documents also, whose authenticity was not questioned from either side.

7. I have carefully perused the entire available data and heard the parties. Drawing my attention towards the case of Sindhu Re-settlement Corporatios Ltd. Vs. Industrial Tribunal Gujarat 1969 Lab. Ind. Cases 526=AIR 1969 S.C. 529 and M/s. Indian Tourism Development Corpn. Vs. Delhi Administration and others 1982 Labour and Industrial Cases : 309 (Delhi) the learned counsel for the management doubted competence of the Tribunal to adjudicate upon the reference since it proceeds on the assumption that there was a dispute on the petitioner's right to promotion whereas on admitted facts, he had competed for the post from the "outsider quota" meaning thereby that there was no occasion for him to fill up the post by way of promotion. In the same sequence it was argued that because the petitioner's claim to the Officer-cadre was linked to competitive test as an outsider, therefore, to that extent there was a complete lack of Master-Servant relationship between the parties and that otherwise also being an individual's dispute it was beyond the scope of Section 2-A of the Industrial Disputes Act so as to call for any adjudication in this forum.

8. Despite its seeming attraction the submission failed to carry conviction with me. The pertinent point is that the Industrial Disputes Act is a beneficial lagislation enacted primarily to ensure welfare of the down trodden Working-class; obviously its interpretative benefits would go to them rather than to the management. And it is, perhaps, in appreciation thereof that the Ld. Judges of the apex Court have time and again frowned upon the myopic approach of the Management. To be illustrative, one may have the advantage of their following observations in the matter of S. K. Verma Vs. Mahesh Chander and Others AIR 1984 S.C. 1462.

> "There appear to be three preliminary objections which have become quite the fashion to be raised by all employers, particularly Public Sector Corporations, whenever an industrial dispute is referred to a Tribunal for adjudication. One objection is that there is no industry, a second that there is no industrial dispute and the third that the workman is no workman. It is a pity that when the Central Government, in all solmnity, refers an industrial dispute for adjudication, a Public Sector Corporation which is an instrumentality of the State instead of Welcoming a decision by the Tribunal on merits so as to absolve itself of any charge of being a bad employer or of victimisation etc. should attempt to evade decision on merits by raising such objections and never thereby satisfied, carry the matter other times to the High Court and to the Supreme Court, wasting public time and money we expect Public Sector Corporations to be model employers and model litigants. We do not expect them to attempt to avoid adjudication or to indulge in luxurious litigation and drag workmen from court to court merely to vindicate, not justice, but some rigid technical stand taken up by them. We hope that Public Sector Corporations will henceforth refrain from raising needless objections, fighting needless litigations and adopting needless postures".

9. In so far as the judical precedents cited by the learned counsel are concerned there hardly appears to be any scope of explanations, except that the judgements in these cases were delivered in entirely different context and on distinguishable facts. In the matter of Sindhu Re-settlement Corporation the employees had demanded payment of retrenchment compensation whereas the Appropriate Govt. referred the proposition of their re-instatement; obviously the reference was beyond the sphere of dispute. Similarly in Tourism Development Corporation case, the controversy between the parties was as to whether there was lock out or closure in the establishment, and the Appropriate Govt. referred the matter to the Tribunal on the assumption that it was a case of lockout. To put it in other words the Govt, arrogated itself the powers of the Tribunal in ruling out the proposition of "Closure".

10. In our case there is no such ambiguity, rather here the bone of contention is as to whether the petitioner should have been offered a post in the Officer-cadre in view of his being placed at a particular serial number in the Select-list of the successful candidates; it is absolutely immaterial as to whether the exercise was given the nomeclature of Promotion or Recruitment. And so far as his locustandi to claim reference as an employee of the Respdt. Bank is concerned, suffice to say that from the circulars Ex. W2 and W3 dated 7-9-76 and 12-1-1977, it is abundantly clear that the very facility to appear in the competitive test was accorded to him by the management on account of his employment under them and that was how that even the condition pertaining to age-ceiling was also relaxed.

11. Similarly the management's effort to knock him out on the technical implication of Section 2-A is misconceived because both from the contents of reference as well as the parties correspondence consisting of the letters Ex. W15 to W17 at the Conciliation stage, there remains no manner of doubt that his case was espoused by a recognised Union on a point concerning the terms and conditions of his employment. The controversy therefore amounted to an industrial dispute as definded by Section 2(K) of the Act which could be legitimately referred by the Appropriate Govt. for adjudication under ection 10 of the Industrial Disputes Act.

12. That directly confronts the Tribunal with the merits of the case where the management appears to be on a slippery ground because on their own showing they had offered only 39 appointments to the successful candidates placed like the petitioner even though 54 persons were appointed under category 4(2)(b).

13. On behalf of the management it was argued that because the petitioner was placed at serial No. 41, therefore he could not be offered the appointment by the time the list was scrapped under the orders of the Central Govt. on

constitution of the Banking Service Recruitment Board w.e.f. 1-1-1979.

14. It appear that for some reasons of their own the management skipped over the inconvenient evidence of WW2 Sunil Kumar Chopra who was also one of their employee like the petitioner and had successfully completed in the examination to be placed at serial No. 21 but never offered any appointment despite his persistent entreaties as would evident from his unrebutted sworn testamony and office correspondence consisting of the letters Ex. W2 to W29. One therefore, can not escape the inference that there was some mistake somewhere either inadvertant or delibrate in deviating from the Merit-list and ignoring the Petitioner's Claim.

15. Hence for the reasons recorded above, on overruling the management's view point, I return my Award in favour of the petitioner/workman with a direction to them to offer him the next available vacancy in the cadre of Officer Grade II.

Chandigarh
7-4-86

I.P. VASISHTH, Presiding Officer

[No. L. 12012/186/84-D. II(A)]
K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1986

का. आ. 1946.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मण्डलीय रेलवे प्रबंधक, पश्चिमी रेलवे, भावनगर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 1 बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-4-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 25th April, 1986

S.O. 1946.—In pursuance of section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employer in relation to the management of Divl. Railway Manager, Western Railway, Bhavnagar and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th April, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO I AT BOMBAY

PRESENT

Dr. Justice R.D. Tulpule Esqr., Presiding Officer

Reference No. CGIT-13 of 1985

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Western Railway Bhavnagar.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :—

For the Management : Mr. P. R. Pai, Advocate
For the workmen : Mr. Gandhi, Advocate

INDUSTRY : Railways STATE : Gujarat

Bomaby, dated the 19th day of February, 1986.

AWARD

This reference No. 13/85 refers to the discontinuance from service of one Shaiffudin Ibrahim from service between the period 5-10-1974 to 20-6-1980.

2. The employee concerned Shaiffudin Ibrahim filed a statement of claim wherein he contended that he was first appointed as a Mill Wright Khalasi on 4th March, 1973. In that capacity, he worked till the 5th of December, 1973 and again with effect from 6th December 1973 to 4th October, 1974. As both these appointments were in the Loco Foremen's Shed at Bhavnagar, his srvices were wrongly terminated on 5th October, 1974, though he worked for more than 240 days between the period 4th March, 1973 to 5th December, 1973, and also between 6th December, 1973 to 4th October, 1974. Under the provisions of the Industrial Disputes Act, he was not paid any retrenchment compensation nor notice wages or notice.

3. The employee contended thereafter that he took up the matter with the railways and after a long time, was successful in getting reinstated w.e.f. 21st of June, 1980. He was however, not paid salary and wages for the period, he was wrongfully terminated, namely w.e.f. 5th October, 1974 to 20th June, 1980. He was not given the benefit of continuous service and other monetary and promotional benefits. He therefore contended that as the action of the Railways was against the provisions of S. 25F and 25G and 25H of the Industrial Disputes Act, he was entitled to benefits of compenation, notice wages and back wages and promotion also. The Railways took up a number of technical defences and contentions including that the claim is barred on the principle of res judicata the employee have filed a suit in Bhavnagar Civil Court being Reg. Civil Suit No. 529/74 and not having proceeded further with that suit. The other contentions are that the claim is barred by time.

4. The applicant also contended that he was entitled to seniority and should have been appointed before his colleague whose services were also terminated on 6th October, 1974 like Hanif Nandalal and others.

5. The Railways' defence seems to be that the workman Saifuddin Ibrahim firstly joined the Railways under a different name, namely, Lakshmidhar Saifuddin w.e.f. 11th March, 1973 as Beldar for the purpose of stamping of weighing machine. It is the Railways' contention that he left the services of his own on the 5th December and secured another with effect from 6th December, 1973 as a Wash out Khalasi in the name which is shown in the refernce, namely, Saifuddin Ibrahim and not Lakshmidhar Saifuddin. He did not actually join on the 6th December, but on the 30th of December, though apparently, according to the Railway his appointment order was dated 6th December. The applicant therefore, was not in service between 6th December and 29th December, 1973. Apparently, Railways seem to contend that the workman can not take advantage of two different periods and they can not be tacked or counted together. There was and there can be no continuity. It is then admitted that the applicant started working with the Railways w.e.f. 30th December, 1973 and continued to work till 5th of October, 1974. According to it, his services were terminated with a 14 days notice, as he had not completed one year's service and was also therefore, not eligible to any retrenchment compensation. It says that it had prepared "an emergency pay-sheet bearing number EPS 38207 dated 5-10-1974....on the very day of termination of service for making payment due to the applicant but he refused to accept the payment". It is significant that the Railways did not say that the emergency pay sheet was for payment of retrenchment compensation and/or notice wages. According to it, pursuant to some administrative orders issued by the Railways, those whose services had been earlier dispensed with were considered for appointment and taken back in ervice depending upon the category of fitness, certified by the medical officers for the respective persons. The Railways say that Saifuddin was classified as "C-1" medical category and therefore, others who had been certified and classified in higher categories such as A-1, B-1 etc. were first absorbed and taken in service and those with a lower medical category appointed later. Thus, Saifuddin came to be appointed subsequent to Nandlal and Hanif H., etc. who had obtained higher medical categoy in the medical examination.

6. Parties filed a number of documents and oral evidence was also led. However, I do not think that the oral evidence adduced in this case is of any assistance or material for the purposes of determing the issue before us

7. The questions arise for consideration. One is whether the workman, Saifuddin Ibrahim was in the continuous employment of the Railways for a period of one year as contemplated under S 25-B of the Industrial Disputes Act, and the second if he was in continuous service as

contemplated in S. 25B of the ID Act, whether the provisions of S. 25F were followed in his behalf. Depending upon the finding on the two questions, relief to be granted to the workman will have to be determined.

8. It may be mentioned in the present case that most of the facts are not in dispute excepting on a small aspect of the matter. The admitted facts are that one Lakshmidhar Saifuddin was working in the Railways as a Mill Wright Khalashi from 4th March, 1973 to 5th December, 1973. The second admitted fact is that Saifuddin Ibrhaim, whose name is mentioned in that manner in the reference was in the employment of the Railways as a Wash Out Khalashi from 30th December 1973 to 5th October, 1974 and it is not the case of the Railways that it paid any retrenchment compensation and notice pay or notice wage to him. I have already adverted to the contention in the written statement that an emergency pay sheet was prepared. But it is not said that by that emergency pay sheet what was sought to be paid to Saifuddin Ibrahim was notice wages or notice pay and retrenchment compensation. On the other hand, what is said is that that pay-sheet related to "payment due to the applicant", but not by way of retrenchment compensation or other monetary benefits under the Industrial Disputes Act. Indeed, the contention of the Railways is clearly that as Saifuddin had not completed one year's service according to rule and provisions of the Industrial Disputes Act and since were not applicable to him, he was not entitled to any retrenchment compensation. That therefore, is the main issue in the present case.

9. On behalf of the workman, attempt was also made and evidence adduced to establish that he had been in the employment of Railways from March, 1973 to 4th October, 1974 continuously. Besides, it is also his attempt to show that Lakshmidhar Saifuddin and Saifuddin Ibrahim are but one and the same person. Saifuddin Ibrahim, the workman who gave evidence, admittedly is a Muslim. Saifuddin Ibrahim is also a Muslim name. However, Lakshmidhar is not a Muslim name. According to the workman, Lakshmidhar is a surname. I am not impressed with the evidence led by the workman to establish himself as Lakshmidhar Saifuddin alias Saifuddin Ibrahim and in continuous employment with the Railways from 4th March, 1973 to 4th October, 1974. However, as I shall presently point out there is clear evidence, which is also the case of the Railways that Saifuddin Ibrahim was in employment from 30th December, 1973 to 4th October, 1974.

10. It may be mentioned that the number of days which the applicant would be deemed to have worked, even if we accept the Railways version that Saifuddin Ibrahim was in its employment from 30th December, 1973 to 4th October, 1974 was more than 240 days. He would have clearly worked with the Railways in that case for 279 days. In any case, it is quite plain that he has worked with the Railways between 30th December, 1973 to 4th October, 1974 which is more than 240 days. This is undisputable and admitted by the Railways.

11. In this context, if we turn to S. 25-B of the Industrial Disputes Act, which defines what is a continuous service, it will be seen that under Subsection 2 of S. 25-B, even if the workman is in employment for a period of 240 days, "he shall be deemed to be in continuous service under an employer (a) for a period of one year, if the workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than" 240 days. Now in the present case, the period of 12 calendar months which have to be considered and which must be deemed to be for the purpose of this reference, preceding the date namely, 4th October, 1974, would be upto October, 1973. Employee Saifuddin Ibrahim, in this case, even according to the Railways started work with it on 30th December, 1973 and worked upto 4th October 1974. Even then, the number of days during which he was in service on that basis would be, as I pointed out, 279 days. This is more than 240 days. He must therefore, be deemed to be in continuous service, even if we hold an which I am inclined to do that Saifuddin Ibrahim is not entitled to attach or annex the period between 4th March, 1973 to 5th December, 1973 as a period of his service, as I am not satisfied that Lakshmidhar Saifuddin and Saifuddin Ibrahim are one and the same person. Besides, the reference order does not refer to this earlier period of employment, nor does it say Lakshmidhar Saifuddin alias Saifuddin Ibrahim.

12. It is not necessary to refer to S. 25F of the Industrial Disputes Act, which lays down the conditions precedent to retrenchment of a workman. That section lays down particularly that "No workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer" unless he has been paid " at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months" and unless he has been given "one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period fo ntice has expired, or workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice." In the case of employees who have been in continuous employment with an employer, the employer can not retrench them, which is equivalent to terminating his a service, without giving notice for one month or wages for one month are paid to him in lieu of notice, as also retrenchment compensation. It is now settled law that where retrenchment is effected, without simultaneously giving notice as contemplated above or making payment of notice wages for one month and retrenchment compensation, such retrenchment is of no consequence or effect at all and it is bound to be ignored. It is totally invalid.

13. What is now contended by the Railways is that the employee had not completed one year of service and was not entitled under the Industrial Disputes Act to any notice wages or any retrenchment compensation. That his services were terminated is not in dispute. Now, termination of service "for any reason whatsoever" has been held and is in terms of S. 2(oo) of the Industrial Disputes Act retrenchment S. 2(oo) defines retrenchment as amongst other things "termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment; subject to the exceptions incorporated in the sub-section and clauses (a), (b), (bb) and (c) thereof. The employee in this case, admittedly, does not come within the exceptions as mentioned in clauses (a), (b), (bb), and (c). Therefore, the removal of Saifuddin Ibrahim from service is "termination for any reason whatsoever" and therefore, amounts to retrenchment. If it is a retrenchment, then it follows that provisions of S. 25F read with S. 25B are attracted. Once we come to the conclusion that Saifuddin Ibrahim had put in, as contemplated in S. 25B, service for a continuous period of one year with the Railways, termination of his service on 4th October, 1974 was in violation of S. 25F, and therefore, has to be ignored and is of no consequence, and he must be deemed to be in continuous service right from 30th December, 1973 to 20th June, 1980 when he was again formally re-employed or started work again with the Railways. It must therefore, be held that the action of the Divisional Railway Manager, Bhavnagar, Western Railway in terminating the services of Saifuddin on 5th October, 1974 is improper and can not be justified. It is illegal and consequently, Saifuddin must be held to be in continuous service. The between the period 5th October, 1974 to 20th June, 1980 will have to be treated as no break at all. In this connection, I may also refer to a decision of the Supreme Court reported in 1986-I-LLJ-(P. 34 Management of standard Motors Products of India Ltd. and Shri A. Parthasarthy and others).

14. The second part of the reference however, requires dealing with the question of wages and other service benefits to employee Saifuddin. I have already held and it must be held that Saifuddin must be deemed to be in continuous employmeent notwithstanding the so called break between 5th October, 1974 to 20th June, 1980. He would therefore, be entitled to seniority and his seniority must be treated and fixed as if he joined employment on 30th December, 1973 and not on 20th June, 1980.

15. Two questions however, still remain and arise. First is with regard to wages between the period 5th October, 1974 to 20th June, 1980 and the second with regard to his claim for promotions. The second part of his claim does not present any difficulty. Promotion is not a matter of right and it is not shown that promotions were given or

would have been given to Saifuddin by sheer seniority. If there is an element of suitability and selection notwithstanding seniority in service, then a person must be found suitable and chosen for the post. He can not claim automatic promotion and no rule has been shown to me or directions governing the service conditions of Saifuddin that he would be automatically, by sheer reason of seniority and service entitled to be promoted and should, therefore be deemed to be promoted to a higher grade or scale. Even what that higher grade or scale would be or should be has not been shown or mentioned. His claim therefore, for promotion made only in a passing manner in the statement of claim has to be rejected.

16. With regard to service for the period 5th October, 1974 to 20th June, 1980, once it is held that the employee was retrenched without following the provisions of S. 25F, the rule would be that he would be entitled to back wages. In this particular case, the employee had been appointed and started working from 20th June, 1980. The question is about the intervening period. Unfortunately, the workman did not say anything in his statement of claim, as to how he had occupied himself and whether he was in employment between the period 5th October, 1974 to 20th June, 1980. He also did not give any evidence by himself as to his activities during this period. It is only in cross-examination that certain questions were asked. The Railways also in their written statement rest contained that the employee Saifuddin was doing some work or was in employment. Evidence given by Saifuddin is that he "used to attend to" his father's stove repairing shop and that his father used to pay him some money every month, as a result of which he was able to maintain himself. It has also come in evidence that Saifuddin got himself married during this time. It was therefore suggested that he would not have been married had he been unemployed. Besides it is also contended that the claim of Saifuddin with regard to wages for this period was an old claim and it should not be entertained. In view of all these facts, I am not inclined to straight away grant wages at the same rate at which the employee would have drawn had he continued in service with Railways. Firstly, as it appears he has been some where gainfully employed and secondly he has not made any contentions or even for that matter satisfactorily established that he was not gainfully employed. I would however, grant him half wages for the period 5th October, 1974 to 20th June, 1980 and seniority right from the date of his employment namely 30th Decembre 1973. That leaves only two matters to be dealt with and considered, particularly, the claim that Lakshmidhar Saifuddin and Saifuddin Ibrahim are one and the same person. I shall briefly deal with these two aspects of the mater.

17. The applicant produced a number of copies of documents, at the initial stage and subsequently produced their originals. All the documents are not consistent and some of them do not correspond with the original. No original of Annexure-B, which he produced has been produced. With regard to C and O there is a conflict as to the date of entry in service. Besides, the names are shown differently in Annexure-C as Saifuddin Ibrahin only and not Lakshmidhar Saifuddin alias Sifuddin Ibrahim. The date of entry in service in Annexure-E is shown as 4th March. 1973. In that document, i.e. Annexure-D name is not shown as Lakshmidhar Ibrahim. It contains particulars of employment of one Saifuddin Ibrahim. As to the autority of the person issuing that document, there is nothing to indicate. Nobody has authenticated that document. The School Leaving Certificate, particularly the one which is produced alongwith the affidavit (Ex-W-3 p. 5-Annexure-A) is mysteriously different from the original which was subsequently produced at W-8 (p.3). That makes it all the more suspicious. The original of that School Leaving Certificate wherein his birth date is mentioned contains a number of corrections, which are not initialled, and the changes are suspicious, particularly with regard to date of birth, name and status of the pupil.

18. The Railways however, can not dispute and did not dispute the certificate produced by him, issued by the Loco Foreman, Bhavanagar, wherein, the loco-foreman's office has stated that Saifuddin Ibrahim has worked in the Foreman's shed Khalashi for the periods 6-12-1973 to 25-12-1973 and 30-12-1973 to 4-10-1974. That certificate also says that he has been granted a temporary status. The other certificates upon which the workman relied and sought to adduce evidence dated 10-1-1986 does not impress me as a genuine and bonafide document. The person who gave that certificate was examined. That person is one Krishna Prasadji Gangaram Purohit, who soon after giving this certificate retired. He gave details of service of Saifuddin Ibrahim and pay for the period 6-12-1973 to 26-2-1974. In his cross-examination, however the admitted that he gave this certificate without referring to any document. He had no authority to issue such certificate clearly replied that he "had not seen any documents before this certificate." He had not obtained his superior's permission issue such certificate, and later admitted that Saifuddin was his friend and since he asked him to issue such certificate, he issued that certificate. Krishna Prashad retired on 31st January, 1986 while he issued the certificate on 10th January, 1986. I do not think that it was necessary for the employee to indulge in all this, in view particularly of the admission by the Railways as to the period during which he was in employment. His attempt to produce all kinds of evidence does not give much credit to him and has been a factor in denying to him full back wages which he would have otherwise been entitled in law.

19. I do not think therefore, it is necessary to refer to any other documentary or oral evidence adduced in this case. the result therefore, is that it has to be held that the action of the Loco Foreman, Bhavanagar in terminating the services of Saifuddin Ibrahim from 5th October, 1974 was not in accordance with the law. Saifuddin must be held to be in continuous employment from 30th December, 1973 and seniority fixed as if having entered service on 30th December, 1973. He would be entitled to half-wages for the period 5th October, 1974 to 20th June, 1980, but would be entitled to any other benefits, such as promotion.

20. Awarad accordingly.

R.D. TULPULE, Presiding Officer

[No. L-41012/44/83-D. II(B)]

HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1986

का.आ. 1947.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स वी.एस. डेम्पो एण्ड कं. प्रा.लि. पणजी के प्रबंधक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 2 बंबई के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 15 अप्रैल 1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 29th April, 1986

S.O. 1947.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. V. S. Dempo and Co. Pvt. Ltd., Panaji and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th April, 1986.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande, Pesiding Officer.

Reference No. CGIT-2/70 of 1985

PARTIES :

Employers in relation to the management of M/s. V. S. Dempo and Co. Pvt. Ltd., Panaji.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri P. K. Rele, Advocate and Solicitor.

For the Workmen—Shri Subhas Naik Union Official.

INDUSTRY : Ports and Docks STATE : Goa, Daman and Diu

Bombay, the 31st March, 1986

AWARD

By their order No. L-30011/8/84-D.IV (A) dated 13-9-1985 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the action of the management of M/s. V. S. Dempo and Co. Ltd. in terminating the 14 workmen (as given in Annexure) of Transhipper M. V. Priyamvada is justified ? If not, to what relief the said workmen are entitled to ?"

ANNEXURE

1. Shri P. Tavares,
2. Shri D. Gonsalves,
3. Shri Caitan Gracias.
4. Shri C. M. Miranda,
5. Shri Luis Fernandes,
6. Shri J. X. Fernandes,
7. Shri R. G. Sawant,
8. Shri Govind Tulaskar,
9. Shri A. J. Sawant,
10. Shri S. F. Gauns,
11. Shri S. C. Sawant,
12. Shri S. A. Gawada,
13. Shri D. P. Shibde,
14. Shri S. A. Kadar.

2. It was contested by both the parties and therefore even issues were framed and matter was fixed for hearing. As the order of reference speaks the dispute arose because of the termination of services of 14 workmen then serving in Transhipper M. V. Priyamvada and finding was to be given whether the said action of the management was justified and if not, to what relief the workmen were entitled.

3. After discussions the parties have come to terms and have filed terms of settlement which I find to be reasonable and fair and as such when they are acceptable to both the parties ,the order to be passed would be award in terms of the settlement.

Award accordingly.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

BEFORE HON'BLE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 AT BOMBAY

Reference No. CGIT-2/70 of 1985

BETWEEN

Workmen as represented by Goa Mining Labour Welfare Union Party No. I

AND

M/s. V. S. Dempo and Co. Pvt. Ltd., Panjim, Goa Party No. II

May it please this Hon'ble Tribunal :—

The parties to the above reference have arrived at a settlement in respect of the matter covered under reference and pray that an award be made in terms of the settlement recorded herein below :—

Terms of Settlement

(1) (a) M/s. V. S. Dempo and Co. Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as 'the Party No. II) agrees to employ with effect from 1st March, 1986 the 14 workmen referred to in the Schedule attached to the Order of Reference in the permanent employment of the Company and/or its sister concerns mentioned against their respective names in Annexure 'A' hereto.

ANNEXURE 'A'

(b) It is agreed that they will be fitted in the scale of pay and category shown against their respective names in the Annexure 'A' hereto and they will be governed by the terms and conditions of service and the settlements applicable to respective concerns in which they are absorbed.

(c) It is agreed between the parties that the concerned workmen will be given 15 days time to report for duty. The workmen will however, be paid wages from the date they report for work.

(2) The Party II, agrees to pay to each of the concerned workmen an amount by way of ex-gratia as per Annexure 'B'.

ANNEXURE 'B'

(3) The payment referred to in Clause No. 2 above will be paid to the concerned workmen on or before 30th March, 1986.

(4) It is agreed between the parties that as a special case the intervening period from their respective dates of termination of their services on board m.v. "Priyamvada" till the date of their employment as referred to above will be treated as leave without pay. It is further agreed between the parties that the period from the dates of their respective appointment on board m.v. "Priyamvada" as shown in Annexure 'A' till the date of their employment will be counted for the purpose of payment of retireral benefits.

(5) It is agreed and understood between the parties that as and when there is a vacancy in the category of 'Crane Operator' on board "Priyamvada", the Crane Operators from among the concerned workmen who will be employed in the terms of this settlement shall be given first preference irrespective of their present designation, in the employment on board m.v. "Priyamvada". The Union and the workmen confirm that they have no claim of whatsoever nature against Party II in respect of their employment with the Party II on board m.v. "Priyamvada" save and except to the extent mentioned above.

(6) (i) The workmen who are not desirous of accepting employment shall communicate their decision to Party II on or before 15th March, 1986.

(ii) The employer agrees to pay to such workmen who are not desirous of accepting employment as agreed in Annexure 'A' to this settlement, an ex-gratia amount equivalent to 2 months consolidated wages and daily allowance last drawn by them at the time of termination of their services on board m.v. "Priyamvada" for every completed year of service.

(iii) It is, however, agreed and understood between the parties that whatever retrenchment compensation and notice pay paid by the Party II at the time of termination of service on board m.v. "Priyamvada" shall be adjusted against the amount payable under subclause (ii). However, it is agreed between the parties that such employees will be entitled to the benefit of Clause No. 2 of this settlement.

(iv) It is further agreed and understood that those workmen who do not accept employment under the terms of this settlement shall have no lien for employment with the employer Party II.

(7) The concerned workmen and the Union agree that in view of the Clauses 1 to 6 above, the dispute referred to this Hon'ble Tribunal is finally settled between the parties and they have no further claim or dispute of whatsoever nature against Party No. II and the amounts received or payable under the settlement is in full and final settlement of all their claims against Party II.

(8) This settlement is arrived at in the peculiar and special circumstances of the case and will not be cited as a precedent for any purpose by either of the parties hereto or any other person in any other proceedings before any authority whether under The Industrial Disputes Act, 1947 or any other enactment.

For Party No. I

Subhas Naik, Jt. Secretary

Goa, Mining Labour Welfare Union.

For Party No. II

Group Personnel Manager

for V. S. Dempo and Co. Pvt. Ltd.

Bombay, this 28th February, 1986.

ANNEXURE 'A'

Sr. No.	Name	Date of joining on m.v. Priyam-vada	Designation on m.v. priyamvada	Last Drawn salary inclusive of Daily Allow.	Category on re-employmnt	Posting	Pay Scales	Fitment in the Pay Scale
								Rs.
1.	Mr. P. Tavares	27-9-82	Crane Opr., Tech.	1290.00	Power Shovel Opr. (2.5 cyd) II	Bicholim Mines	Rs. 425-25-550-30-700-35-1050	640.00
2.	Mr. Luis Fernandes	21-10-82	Vrane Opr., Tech.	1290.00	Power Shovel Opr. (2.5 cyd) II.	Bicholim Mines	Rs. 425-25-550-30-700-35-1050	640.00
3	Mr. C.F.P. Gracias	8.10.82.	Crane Opr. Tech	1290.00	Power shovel opr.(2.5 cyd,	Bicholim Mines	Rs. 425-25-550-30-700-35-1050	640.00
4.	Mr. Domingo Gonsalves	27-9-82	Crane Opr., Tech.	1290.00	Asstt. Crane opr.	D.E.W.	Rs. 320-18-410-23-640-26-770	525.00
5.	Mr. C. M. Miranda	27-9-82	Crane Opr., Tech.	1290.00	Power Shovel Opr. (2.5 cyd) II.	Surla Mines	Rs. 450-20-550-24-790-30-940.	622.00
6.	Mr. G.J. Tulas-kar	27-9-82	Asst. Tech.	1140.00	Plantman III	Kirlapale Mines	Rs. 315-12-375-15-525-20-625.	510.00
7.	Mr. S.T. Gawade	27-9-82	Asst. Tech.	1140.00	Jr. Mech (I)	Bicholim Mines	Rs. 350-15-425-20-525-25-775.	485.00
8.	Mr. S.G. Sawant	27-9-82	Asst. Tech.	1140.00	Jr. Mech. (I)	Bicholim Mines	Rs. 350-15-425-20-525-25-775.	485.00
9.	Mr. D P. Chibde	27-9-82	Asst. Tech.	1140.00	Jr. Mech (I)	Bicholim Mines	Rs. 350-15-425-20-525-25-775.	485.00
10.	Mr. S.F. Gauns	27-9-82	Asst. Tech.	1140.00	Jr. Mech. (I)	Bicholim Mines	Rs. 350.15-425-20-525-25-775.	485.00
11.	Mr. A.J. Sawant	27-9-82	Asst. Tech.	1140.00	Jr. Mech (I)	Surla Mines	Rs. 370-15-445-18-625-22-735.	481.00
12.	Mr. J. H. Fernandes	27-9-82	Con. Loader Opr.,Tech.	1140.00	Jr. Mech. (I)	Kirlapale Mines	Rs. 370-15-445-18-625-22-735.	481.00
13.	Mr. R.G. Sawant	27-9-82	Asst. Tech.	1140.00	Jr. Mech (I)	Surla Mines	Rs. 370-15-445-18-625-22-735.	481.00
14.	Mr. S.A. Kadar	27-9-82	Khalasi	1040.00	Helper (I)	Sarmanas Loading Point	Rs. 265-10-315-12-435-15-510.	399.00

ANNEXURE 'B'

Sr. No.	Name	Ex-Gratia Amount (Rs.)
1.	Mr. C. M. Miranda	4000.00
2.	Mr. P. Tavares	4000.00
3.	Mr. D. Gonsalves	4000.00
4.	Mr. C. F. P. Gracias	4000.00
5.	Mr. Luis Fernandes	4000.00
6.	Mr. J. X. Fernandes	3000.00
7.	Mr. S. T. Gawade	3000.00
8.	Mr. S. G. Sawant	3000.00
9.	Mr. D. P. Chibde	3000.00
10.	Mr. S. F. Gauns	3000.00
11.	Mr. A. J. Sawant	3000.00
12.	Mr. G. S. Tulaskar	3000.00
13.	Mr. R. G. Sawant	3000.00
14.	Mr. S. A. Kadar	2000.00

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L. 36011/8/84-D-IV(A)]

28th February, 1986

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1986

का.आ. 1948:— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार महा प्रबंधक, पश्चिम रेलवे बम्बई के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. II बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-4-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 29th April, 1986

S.O. 1948.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. II, Bombay, as shown in the Annexure, in the indusrtial dispute between the employers in relation to the management of General Manager, Western Railway, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th April, 1986.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/60 of 1985

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of General Manager, Western Railway, Bombay and Divl. Signal and Telecommunication Engineer, Western Railway, Baroda.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Workme : Noappearance.

For the Workmen : No appearance.

INDUSTRY : Railways. STATE : Gujarat.

Bombay, the 31st March, 1986

AWARD

By their order No. L-41011(40)|84-D.II(B) dated 29-8-1985 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the action of the Railway management of Baroda Division in marking absence of Shri J. R. Bhakta at Varediya on 13-6-1984 and not paying the wages and allowance for that date is justified ? If not, to what relief the workman is entitled to ?"

2. The dispute is the outcome of controversy between the Railway management on one side and the Union on the other ground of alleged absence of the workman on 13-6-1984 while this contention is refuted by the management who says that on the relevant date the workman absented himself from duty as such on the ground no work no wages he was not paid his wages.

3. Consequently as the dispute stands everything depends upon whether the workman establishes that he was present at the place of duty on the relevant date. By nature of this issue itself since he was marked absent by the person supervising his duties, the burden squarely falls on the workman to establish his presence which he has failed to do having remained absent at the time of hearing of the reference despite due service of notice. The result is that if there is no proof of his presence at the place of his duty and if under these circumstances he was not paid his wages, the workman cannot make any grievance about non-payment.

The reference fails.

Award accordingly.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L-41011(40)|84-DI(B)]

का.आ. 1949:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पश्चिमी कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-4-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1949.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay-2, as shown in the Annexure, in the indusrtial dispute between the employers in relation to the management of Western Coalfields Ltd., P.O. Ghugus, Distt. Chandrapur and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th April, 1986

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/66 of 1985

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Western Coalfields Lmited.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers : Shri Rajendra Menon, Advocate.

For the Workmen : Shri D. V. Gangal, Advocate.

INDUSTRY : Coal Mines. STATE : Maharashtra.

Bombay, the 1st April, 1986

AWARD

By their order No. L-22012|76|84-DV dated 25-9-1985 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Indusrtial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the action of the management of Bellera Colliery, Sub-Area No. 2 of M/s. Western Coal fields Limited, P.O. Ghugus Distt. Chandrapur in terminating the services of the workman Shri Nanaji Dattoo Nande is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. The services of the workman were terminating on the ground of long standing absence and since there was never any enquiry held but straightaway the relationship was severed, at the request of the management opportunity was given to prove the misconduct. The workman in the statement of claim has raised certain contentions alleging that the termination is in violation of Section 25F and G of the Industrial Disputes Act but since as the facts stand the termination was for the alleged misconduct, these contentions trying to invoke he provisions of Section 25F and G would not survive.

3. The issues which arise for determination and my findings thereon are :—

ISSUES	FINDINGS
(1) Does the management establish the misconduct as alleged ?	Yes
(2) Whether the order of termination was justified ?	No
(3) If not, is the workman entitled to any relief ?	Yes
(4) What award ?	As per award.

REASONS

4. In order to establish the absence there is evidence of Shri Devidas Trandra, Register Clerk who has deposed that from 18-8-1983 the workman was continuously absent and therefore first show cause notice was issued and then finally the order of termination. From the record it appears that on 28-8-1983 the witness submitted his report stating that the workman was absent from 18-8-1983, vide documents No. 1 of list of document dated 18-2-1986. Then there is another letter S. No. 2, whereby it is reported that in the year 1982 he worked for 210 days, and in 1983 till 18-8-1983 he worked for 126 days only. Admittedly the workman joined the service on 16-7-1981. The contention of the management is that from 18-8-1983 the workman never cared for his duties but they themselves have brought on record an application dated 24-8-1983, S. No. 3 submitted by the workman requesting to allow him to join duty. It is not therefore that he was continuously absent from 18-8-1983 till November, 1983 but in the month of August 1983 he made attempt to join duty but he was not allowed to do so. Then there is a letter dated 14-10-1983 asking the workman to show cause and by order dated 2-11-1983 terminated the service.

5. The net result of the above discussion is that although the workman remained absent from 18-8-1983 might be without anybody's permission as stated by the witness, but he says that he was ill and further he says that attempt was made to join duty which is supported by the letter dated 24-8-1983, S. No. 3. Now it is true that the misconduct of remaining absent without permission from 18-8-1983 is established. The record also shows that he did not work for all the days in the previous year. Although the misconduct is established, it is not such that it calls for the extreme punishment of termination of service. I think that the order of discharge is harsh and disproportionate and the workman should be given an opportunity to serve the tuine. Because he committed a misconduct as a sort of punishment I disallow the bank wages to which normally he would have been entitled and he shall start earning wages from the day when he report for duty.

6. The workman therefore shall be allowed to join the service. Now wages would be payable from 18-8-1983 till he joins service. The order of discharge however is set aside and for purpose of other benefits the period from 18-8-1983 till he joins service shall be treated as special leave without pay.

Award accordingly.

M.A. DESHPANDE, Presiding Officer
[No. L-22012/76/84-D. V/D. III (B)]
HARI SINGH, Desk Officer

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 1986

का.आ. 1950:—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 21 मई, 1986 से भारत पीस्टअर्ड सर्विस, 2-8-बी, शरत बोस रोड, कलकत्ता-700020 को अभिकरण के रूप में धुमकरण की निम्नलिखित मदों के लिए एक वर्ष की और अवधि के लिए मान्यता देती है

1. तेल रहित चावल की भुसी, और
2. हड्डियों का चूरा खुर और सींग।

[फा.सं. 5(4)/82-ई.आई.एण्ड ईपी]
एन.एस. हरिहरन, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 1986

S.O. 1950.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year with effect from 21st May, 1986, M/s. Bharat Pest-Erad Services, 2/8-B, Sarat Bose Road, Calcutta-700020 as an agency for the fumigation of following items :—

1. De-oiled Rice Bran; and
2. Crushed Bones, Hooves and Horns.

[F. No. 5(4)/82-EI&EP]
N. S. HARIHARAN, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986